# चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 29 जून –05 जुलाई 2015 | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467


# ऐसे लोकायुक्तों से भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा

फोटो-प्रभात पाण्डेय

**जब अन्ना हजारे लोकपाल और लोकायुक्त के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो कई लोगों को लगता था कि लोकपाल और लोकायुक्त बनते ही देश में भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा. आज भी कई लोग इन संस्थानों की मांग को लेकर ज़मीन-आसमान एक करने पर तुले हैं. लेकिन, पिछले कुछ समय से जिस तरह की ख़बरें आ रही हैं, वे लोकपाल और लोकायुक्त के लिए संघर्ष करने वालों के लिए किसी सदमे से कम नहीं हैं. जब अन्ना हजारे दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, तब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह लोकपाल के ख़िलाफ़ एक शब्द बोल दे, क्योंकि ऐसा करने पर लोगों द्वारा उसे भ्रष्टाचारियों का दलाल घोषित कर दिए जाने का डर था. मीडिया ने लोकपाल और लोकायुक्त नामक संस्थानों की ऐसी मार्केटिंग की कि ये दोनों ईमानदारी और पारदर्शिता के पर्याय बन गए.**

मनीष कुमार

आज पूरे देश में लोकायुक्त की रिपोर्ट का नाम सुनते ही जनता द्वारा चुनी सरकार से लेकर राज्यपाल और चुनाव आयोग तक कांपने लगते हैं. सब दबाव में आ जाते हैं. इस देश का सौभाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट किसी के दबाव में नहीं आता है, वर्ना अनर्थ हो गया होता. उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से उन लोगों की याद आ गई, जो अन्ना आंदोलन के समय कह रहे थे कि अगर लोकपाल और लोकायुक्त ग़लत फ़ैसले लेने लगे, तो वह किसके प्रति ज़िम्मेदार होगा. अगर लोकपाल और लोकायुक्त ही राजनीति का अड्डा बन जाएंगे, तो उन पर कैसे नियंत्रण किया जाएगा. अगर लोकपाल और लोकायुक्त ही भ्रष्ट निकल गया, तो भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम लगाई जा सकेगी. उस वक्त ये सवाल भी उठाए जा रहे थे कि क्या किसी प्रजातंत्र में लोकपाल और लोकायुक्त को इतनी शक्तियां दी जा सकती हैं कि वह बिल्कुल तानाशाह बन जाए. क्या किसी प्रजातंत्र में हम ऐसी संस्था बना सकते हैं, जो बिल्कुल निरंकुश हो और जिसके भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का कोई तरीका न बचे. आज वही डर सही साबित होने लगा है. हम एक ऐसी शर्मनाक कहानी आपके सामने रख रहे हैं.

उमा शंकर सिंह रसड़ा विधानसभा क्षेत्र (बलिया) के विधायक हैं. कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने उन्हें विधायक पद से बर्ख़ास्त कर दिया था. बर्ख़ास्तगी की वजह उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की रिपोर्ट थी. लोकायुक्त ने यह रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी थी. समझने वाली बात यह है कि लोकायुक्त के पास किसी विधायक को बर्ख़ास्त करने की शक्ति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में खुद-ब-खुद उमा शंकर सिंह को अयोग्य करार दिया था. राज्यपाल ने इस रिपोर्ट को चुनाव आयोग के पास भेज दिया. चुनाव आयोग ने भी लोकायुक्त की जांच को आधार बनाकर उमा शंकर सिंह को अयोग्य करार दिया. इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें बर्ख़ास्त कर दिया. लेकिन, इस मामले में लोकायुक्त को सबसे बड़ा झटका तब लगा, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्यपाल और चुनाव आयोग के फ़ैसले पर रोक लगा दी और उमा शंकर सिंह की विधायकी बहाल कर दी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ लोकायुक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए.

सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, वह चौंकाने वाला है. जस्टिस आरके अग्रवाल एवं जस्टिस अमिताभ रॉय की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फ़ैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की याचिका खारिज कर दी. रसड़ा के विधायक उमाशंकर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई. दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 मई को बसपा विधायक की सदस्यता बहाल रखते हुए आदेश दिया था कि चुनाव आयोग 15 जून से मामले की सुनवाई दोबारा करे. साथ ही हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि लोकायुक्त को भ्रष्टाचार के मामले में जांच करने का अधिकार है, लेकिन वह किसी विधायक की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश नहीं कर सकता. तो पहला सवाल यह है कि लोकायुक्त ने विधायक की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश क्यों की? दूसरा सवाल यह है कि राज्यपाल ने लोकायुक्त की रिपोर्ट को इतनी तरजीह क्यों दी? और, तीसरा सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने भी लोकायुक्त की रिपोर्ट को ब्रह्म-सत्य मानकर फ़ैसला क्यों लिया? होना तो यह चाहिए था कि शिकायत मिलने पर चुनाव आयोग स्वयं जांच करता और अगर उसकी जांच में साक्ष्य मिलते, तो वह सदस्यता रद्द करने का फ़ैसला ले सकता था. आख़िर ऐसी क्या बात है कि लोकायुक्त की रिपोर्ट आते ही राज्यपाल और चुनाव आयोग के हाथ-पैर फूलने लगे?

ग़ौर करने वाली एक और बात है. जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फ़ैसला दे दिया और उमा शंकर सिंह की विधायकी बहाल कर दी, तो उस फ़ैसले को चुनौती देने लोकायुक्त साहब सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच गए? वह भी इतनी स्पीड से, जबकि कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला तो चुनाव आयोग के फ़ैसले के ख़िलाफ़ था. जब लोकायुक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो वहां उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द करने की मांग की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजों ने लोकायुक्त की कार्यशैली सही तरीके से पहचान ली. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आपको यानी लोकायुक्त को इस मामले में इतनी रुचि क्यों है और आपके कोर्ट आने के पीछे क्या मंशा है? अगर कोर्ट द्वारा लोकायुक्त

(शेष पृष्ठ 2 पर)

**उमा शंकर सिंह रसड़ा विधानसभा क्षेत्र (बलिया) के विधायक हैं. कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने उन्हें विधायक पद से बर्ख़ास्त कर दिया था. बर्ख़ास्तगी की वजह उत्तर प्रदेश केलोकायुक्त की रिपोर्ट थी. लोकायुक्त ने यह रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी थी. समझने वाली बात यह है कि लोकायुक्त के पास किसी विधायक को बर्ख़ास्त करने की शक्ति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में खुद-ब-खुद उमा शंकर सिंह को अयोग्य करार दिया था.**

**सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, वह चौंकाने वाला है. जस्टिस आरकेअग्रवाल एवं जस्टिस अमिताभ रॉय की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फ़ैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की याचिका खारिज कर दी. रसड़ा के विधायक उमाशंकर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई. दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 मई को बसपा विधायक की सदस्यता बहाल रखते हुए आदेश दिया था कि चुनाव आयोग 15 जून से मामले की सुनवाई दोबारा करे.**

विधायक उमाशंकर सिंह, रसड़ा विधानसभा क्षेत्र (बलिया).


चंद्रशेखर जी सादगी और ईमानदारी की मिसाल हैं | P-3

क्या किसानों-आदिवासियों का दुःख दूर कर पाएंगे राहुल | P-4

हत्यारोपी मंत्री के बचाव में ताल ठोंक रही सरकार | P-5

# ऐसे लोकायुक्तों से भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा

पृष्ठ 1 का शेष

की मंशा पर टिप्पणी होने लगे, तो इसका मतलब साफ़ है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है. दरअसल, यह मामला 2011 में शुरू हुआ, जब उमा शंकर सिंह के ही गांव के एक वकील सुभाष सिंह उर्फ क्रांतिकारी ने लोकायुक्त में उनके ख़िलाफ़ एक शिकायत दर्ज करा दी. आरोप भ्रष्टाचार का था कि वह अपने रसूख के बल पर और ग़ैर-क़ानूनी तरीके से सरकारी ठेके लेते हैं. यह शिकायत 2011 में की गई, जब उमा शंकर सिंह विधायक नहीं थे. जबकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2012 में हुआ था. दूसरी बात यह कि जब भी कोई व्यक्ति शिकायत करता है, तो हलफ़नामे के रूप में करता है और शिकायत के साथ उसे साक्ष्य भी देने पड़ते हैं. 2011 में उमा शंकर सिंह विधायक नहीं थे. कोई सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी नहीं थे. वह उस वक्त सरकार द्वारा पंजीकृत एक ठेकेदार थे, फिर भी लोकायुक्त ने शिकायत स्वीकार कर ली. पहली बात तो यह कि लोकायुक्त को उसे स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था. दूसरी बात यह कि उमा शंकर सिंह न तो सरकार की ब्लैक लिस्ट में थे, न उन पर काम न करने या खराब काम करने का कोई आरोप था और न कोई भ्रष्टाचार का आरोप था. लोकायुक्त ने शिकायत तो स्वीकार कर ली, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की.

**सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त की याचिका न सिर्फ़ खारिज की, बल्कि सुनवाई के दौरान उनकी मंशा पर टिप्पणी भी कर दी. अब लोकायुक्त के इस आचरण का जवाब कौन देगा? इन सब कामों में जो खर्च हुआ, वह लोकायुक्त ने अपनी जेब से नहीं, बल्कि जनता के पैसों से किया होगा. उसका हिसाब कौन देगा? एक विधानसभा के विधायक का भविष्य तीन साल तक अधर में लटका रहे, तो जनता की समस्याओं का हल कौन निकालेगा? रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जो नुक़सान हुआ, उसकी भरपाई क्या लोकायुक्त करेंगे?**

उमा शंकर सिंह छह मार्च, 2012 को चुनाव जीतकर विधायक बन जाते हैं उसके बाद शिकायतकर्ता से लोकायुक्त ने एक हलफ़नामा लिया और उमा शंकर सिंह को धारा 9 (ए) के तहत नोटिस दिया कि विधायक बनने के बाद आपने ठेकेदारी की, जबकि भारतीय संविधान के मुताबिक, सांसद या विधायक बनने के बाद कोई भी व्यक्ति सरकारी ठेके नहीं ले सकता. नोट करने वाली बात यह है कि उमा शंकर सिंह जिस फर्म के नाम पर पीडब्ल्यूडी के ठेके लेते थे, वह फर्म 2009 में लिमिटेड कंपनी बन गई थी. क़ानून के मुताबिक, अगर कोई लिमिटेड कंपनी है, तो इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है कि सांसद या विधायक उसके सीएमडी हैं या कुछ और. फिर वह सांसद या विधायक इस क़ानून की परिधि से बाहर चला जाता है. उमा शंकर सिंह की फर्म का नाम छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी था, जो 2009 में सीएस इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बन गई, जिसे 2010 में पीडब्ल्यूडी ने स्वीकार कर लिया. मतलब यह कि उमा शंकर सिंह की पुरानी छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी नामक फर्म का अस्तित्व समाप्त हो गया है. अब यह लिमिटेड कंपनी में कनवर्ट हो गई है. 2010 के बाद से जो भी सरकारी ठेका मिला, वह एक लिमिटेड कंपनी को मिला.

अब सवाल यह उठता है कि अगर किसी सांसद या विधायक की अयोग्यता का मामला बनता है, तो उसकी जांच करने का अधिकार चुनाव आयोग को है. लोकायुक्त को उसकी जांच करने का अधिकार नहीं है, बावजूद इसके वह इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे थे? लोकायुक्त को तो सिर्फ़ भ्रष्टाचार के मामले में जांच करने का अधिकार है. सांसद या विधायक की अयोग्यता परखने की शक्ति लोकायुक्त को किसने दे दी? साथ ही जब लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल और मुख्यमंत्री को सौंपी, तो उनके अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने पर राज्यपाल ने आपत्ति क्यों नहीं उठाई? दरअसल, लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा कि लोकायुक्त के पास किसी विधायक को अयोग्य घोषित या बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई से उमा शंकर सिंह के मामले को विधायक बजरंग बहादुर सिंह के साथ जोड़ दिया और यह भी कह दिया कि राज्यपाल को चुनाव आयोग के माध्यम से फ़ैसला लेना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में साफ़-साफ़ कहा है कि इस मामले में लोकायुक्त के पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन लोकायुक्त की रिपोर्ट को पूरी तरह से अमान्य नहीं घोषित किया जा सकता है. यह रिपोर्ट राज्यपाल के समक्ष एक संदेह या सवाल उठाने भर के लिए मान्य है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. मतलब यह कि लोकायुक्त की रिपोर्ट अपने आप में परिपूर्ण या अंतिम नहीं है. लोकायुक्त की रिपोर्ट का महत्व सिर्फ़ इतना है कि वह राज्यपाल के समक्ष एक संदेह अंकित करती है, ताकि राज्यपाल उस पर जांच के आदेश दें या मामले को सक्षम प्राधिकारी को भेज दें. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा, क्योंकि लोकायुक्त की रिपोर्ट आते ही राज्यपाल ने उसे चुनाव आयोग को भेज दिया और चुनाव आयोग ने भी लोकायुक्त की रिपोर्ट को ही आधार बनाकर उमा शंकर सिंह को अयोग्य करार दिया, जिसके बाद उमा शंकर सिंह को विधायक पद से बर्खास्त कर दिया गया. किसी विधायक के बर्खास्त होने का मतलब है कि उस विधानसभा क्षेत्र में छह महीने के भीतर फिर से चुनाव हो. चुनाव आयोग चुनाव से पहले की प्रक्रिया शुरू कर देता है.

बर्खास्त होने के तुरंत बाद उमा शंकर सिंह ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी. हाईकोर्ट ने रिट मंजूर भी कर ली. इसके बाद रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की प्रक्रिया रुकवाने के लिए उमा शंकर सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां उन्हें राहत मिली. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनकर आदेश दिया कि रसड़ा विधानसभा में चुनाव प्रक्रिया रोक दी जाए. इसके बाद हाईकोर्ट में रिट पिटीशन पर सुनवाई शुरू हुई, जिसका फ़ैसला उमा शंकर सिंह के पक्ष में आया. हैरानी की बात तो यह है कि हाईकोर्ट से किरकिरी होने के बाद लोकायुक्त ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन लगा दी. अब सवाल यह है कि हाईकोर्ट के फ़ैसले के बाद लोकायुक्त को सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब यह सबको पता है कि किसी विधायक को बर्खास्त करने या उसकी जांच करने का अधिकार लोकायुक्त के पास नहीं है, तब वह इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? ऐसे में लोकायुक्त पर कई प्रकार के कष्टप्रद सवाल उठना लाजिमी है.

**अब सवाल यह उठता है कि अगर किसी सांसद या विधायक की अयोग्यता का मामला बनता है, तो उसकी जांच करने का अधिकार चुनाव आयोग को है. लोकायुक्त को उसकी जांच करने का अधिकार नहीं है, बावजूद इसके वह इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे थे? लोकायुक्त को तो सिर्फ़ भ्रष्टाचार के मामले में जांच करने का अधिकार है. सांसद या विधायक की अयोग्यता परखने की शक्ति लोकायुक्त को किसने दे दी? साथ ही जब लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल और मुख्यमंत्री को सौंपी, तो उनके अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने पर राज्यपाल ने आपत्ति क्यों नहीं उठाई?**

सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त की याचिका न सिर्फ़ खारिज की, बल्कि सुनवाई के दौरान उनकी मंशा पर टिप्पणी भी कर दी. अब लोकायुक्त के इस आचरण का जवाब कौन देगा? इन सब कामों में जो खर्च हुआ, वह लोकायुक्त ने अपनी जेब से नहीं, बल्कि जनता के पैसों से किया होगा. उसका हिसाब कौन देगा? एक विधानसभा के विधायक का भविष्य तीन साल तक अधर में लटका रहे, तो जनता की समस्याओं का हल कौन निकालेगा? रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जो नुक़सान हुआ, उसकी भरपाई क्या लोकायुक्त करेंगे? इससे बड़ा सवाल यह है कि लोकायुक्त की जवाबदेही कौन तय करेगा? आज यह कहा जा सकता है कि जिन-जिन राज्यों में लोकायुक्त हैं, वहां भ्रष्टाचार में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई है. यह कहना ग़लत नहीं होगा कि ज़्यादातर राज्यों में लोकायुक्त का पद अब एक सफेद हाथी बन चुका है. उत्तर प्रदेश और बिहार से मिली सूचनाओं के मुताबिक़, उनके कार्यालयों पर हर साल करोड़ों रुपये ख़र्च हो रहे हैं. 2002 से 2007 के बीच उत्तर प्रदेश लोकायुक्त कार्यालय पर पांच करोड़ 20 लाख रुपये से ज़्यादा ख़र्च हो गए. सवाल यह है कि जनता के इन पांच करोड़ रुपये के बदले हासिल क्या हुआ? क्या उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया? जनता के पैसों का इस्तेमाल कुछ लोगों को दफ्तर, गाड़ियां और तनख्वाह देने के लिए करना आख़िर कहां का न्याय है? उत्तर प्रदेश सरकार को लोकायुक्त के कामकाज पर श्वेत-पत्र जारी करना चाहिए, ताकि जनता को पता चल सके कि लोकायुक्त नामक संस्था ने कितना काम किया है? साथ ही यह भी बताना चाहिए कि अगर लोकायुक्त नामक संस्था न होती, तो क्या वह काम सरकार की दूसरी एजेंसी आसानी से न कर पाती?

अब जरा बिहार में लोकायुक्त कार्यालय पर हुए खर्च को समझते हैं. 2002 से 2007 के बीच बिहार लोकायुक्त कार्यालय पर पांच करोड़ 12 लाख रुपये से ज़्यादा ख़र्च हो गए. इन पांच सालों में इस कार्यालय के पास 8,743 शिकायतें आईं, जिनमें से 7,043 मामलों में जांच शुरू की गई. 131 नौकरशाहों एवं राजनेताओं के ख़िलाफ़ शिकायतें आईं. इन सभी मामलों में अंतिम कार्रवाई क्या हुई, यह अब तक किसी को पता नहीं है. नौकरशाहों एवं राजनेताओं के ख़िलाफ़ क्या हुआ, इसकी ख़बर कम से कम मीडिया में तो आज तक नहीं आई है. यह हाल सिर्फ़ इन्हीं दो राज्यों का नहीं है, बल्कि और जिन राज्यों में लोकायुक्त हैं, वहां की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है. हर राज्य में लोकायुक्त विवाद के केंद्र बन चुके हैं, साथ ही उनके कामकाज पर सवाल उठने लगे हैं. ऐसा एक भी उदाहरण सामने नहीं आया है, जिसमें लोकायुक्त ने किसी राजनेता के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की हो. दरअसल, सूचना आयोग की तरह ही लोकायुक्त का पद भी राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति का एक ज़रिया बन गया है.

मध्य प्रदेश में तो लोकपाल और सूचना आयुक्त के बीच जंग हो गई. मामला थाने तक पहुंच गया था. बात 2007 की है, जब मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त और लोकायुक्त आपस में झगड़ते हुए भोपाल के एमपी नगर थाने तक पहुंच गए थे. मामला यह था कि मुख्य सूचना आयुक्त एक प्रकरण में लोकायुक्त के ख़िलाफ़ निर्णय सुनाने वाले थे, जो लोकायुक्त कार्यालय से जुड़ी सूचना से संबंधित था. फ़ैसले के एक दिन पहले लोकायुक्त साहब मुख्य सूचना आयुक्त के घर पहुंच गए और उन्होंने उनसे अपने ख़िलाफ़ फ़ैसला न सुनाने के लिए कहा. लोकायुक्त स्तर के व्यक्ति द्वारा ऐसी हरकत किसी भी लिहाज से उचित नहीं थी. जब मुख्य सूचना आयुक्त ने अपना फ़ैसला दिया, तो उस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख कर दिया कि लोकायुक्त उन्हें प्रभावित करने के उद्देश्य से उनके घर आए थे. इससे लोकायुक्त नाराज़ हो गए और मामला पुलिस तक पहुंच गया. लोकायुक्त ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त ने फ़ैसले के बाद यह नोट जोड़ा, जो एक आपराधिक मामला है. इसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त ने भी थाने में लोकायुक्त के ख़िलाफ़ फ़ैसला प्रभावित करने के लिए दबाव बनाने का प्रकरण दर्ज करा दिया. बाद में इन दोनों का विवाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया. ये दोनों संस्थाएं देश में भ्रष्टाचार ख़त्म करने और पारदर्शिता कायम करने के लिए बनाई गई थीं. मध्य प्रदेश में इन दोनों के इस प्रकार लड़ने से यह साबित होता है कि सिर्फ़ संस्थाएं बना देने से ही मसले का हल नहीं निकलता.

जब अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान में आंदोलन किया था, तो उस समय लोगों के मन में लोकपाल और लोकायुक्त को लेकर एक अलग-सी छवि बन गई थी. लोगों ने यह सोचा कि इनके बनते ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लग जाएगा. विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त बने अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन इस संस्था का पतन होना शुरू हो गया है. अन्ना हजारे और उनकी टीम ने देश को बहुत सपने दिखाए थे. अब जबकि राज्यों में लोकायुक्त हैं, तो सपना दिखाने वाली टीम ने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन करना तो दूर, बयान देना भी बंद कर दिया है. अब ऐसा प्रतीत होने लगा है कि विचार-शून्यता की वजह से लोकपाल आंदोलन किसी तार्किक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया. उनके पास भ्रष्टाचार से निपटने का कोई वैचारिक ब्लूप्रिंट नहीं था. वे त्वरित जनभावना और दीर्घकालिक योजनाओं में सामंजस्य नहीं बैठा सके. यही वजह है कि लोकायुक्त भी दूसरी संस्थाओं की तरह व्यक्ति आधारित हो गया.

भ्रष्टाचार एक गंभीर और बड़ी समस्या है. इससे निपटने के लिए देश को एक ज़िम्मेदार और जवाबदेह व्यवस्था की ज़रूरत है. वर्तमान में विभिन्न राज्यों से लोकायुक्तों के बारे में जिस तरह की ख़बरें आ रही हैं, वे चिंताजनक हैं. लोकपाल और लोकायुक्त को लेकर सरकार को नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है. पहले यह तय करना ज़रूरी है कि उनका औचित्य है भी या नहीं. सरकार को यह भी बताना होगा कि हर राज्य में पुलिस है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, विजिलेंस डिपार्टमेंट है, सूचना का अधिकार है, अदालत है, पुलिस है, सीबीआई है. जब सब कुछ है, तो फिर लोकपाल और लोकायुक्त का औचित्य क्या है? और, अगर औचित्य है, तो फिर उनकी ज़िम्मेदारी और जवाबदेही तय करनी होगी, क्योंकि देश को ग़ैर-ज़िम्मेदार और ग़ैर-जवाबदेह लोकायुक्तों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. ■

manishbph244@gmail.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 17
दिल्ली, 29 जून –05 जुलाई 2015
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

> चंद्रशेखर जी जहां अन्याय होता था, वहां खड़े हो जाते थे, अन्याय करने वाले के ख़िलाफ़. एक साधारण परिवार में रहकर उनकी पढ़ाई कैसे चली. उन्होंने बताया था मुझे कि कैसे वह पढ़ पाए और अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े. उसके बाद निकल कर कहां पहुंचे, देश के सबसे उच्च पद पर. स्वाभिमान के ख़िलाफ़ समझौता न करने की वजह से वह प्रधानमंत्री पद से हटे. उन्होंने कहा कि वह स्वाभिमान के ख़िलाफ़ कभी समझौता नहीं करेंगे. उन्होंने किसी को नहीं हटाया. वह कभी पद के भूखे नहीं रहे.

# चंद्रशेखर जी सादगी और ईमानदारी की मिसाल हैं

**मैंने लोहिया जी के जन्म दिन के अवसर पर भी कहा था कि चंद्रशेखर जी के आचरण, सादगी और ईमानदारी को आप एक मिसाल समझें. इतनी सादगी किसी नेता में नहीं थी. या तो डॉ. लोहिया में थी या फिर चंद्रशेखर जी में. कुछ लोग तो प्रधानमंत्री बनते-बनते न जाने कौन-कौन से कपड़े बदल कर पहनने लगते. चंद्रशेखर जी जो कपड़े रोज़ाना पहनते थे, वही धोती-कुरता, उसी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनकर पहना. वह जो सोचते थे, वही करते थे, लेकिन कभी समझौता नहीं करते थे. इसी बात को लेकर वह बहुत लंबे समय तक सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जयप्रकाश जी के साथ रहे, लोहिया जी के साथ भी रहे. एक बार मैंने कहा, आप सोशलिस्ट पार्टी में थे और आप लोहिया जी का बहुत सम्मान करते हो. इस पर उन्होंने दु:खी होकर कहा, आज तक मुझे बहुत बड़ा पश्चाताप है, आख़िरी तक वह पश्चाताप हम भूल नहीं पा रहे हैं. हमने कहा कि मामला क्या है? दरअसल, बात यह थी कि तब चंद्रशेखर जी कांग्रेस में चले गए थे. एक दिन लोहिया जी सेंट्रल हाल में बैठे थे. उसी वक्त इंदिरा जी ने चंद्रशेखर जी को बुलवाया. लोहिया जी ने कहा, चंद्रशेखर जी, इतनी तेजी से कहां जा रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा, अभी लौटकर आ रहा हूं लोहिया जी. लेकिन उन्हें देर हो गई और देर होने पर उन्होंने सोचा कि अब लोहिया जी नहीं होंगे. इधर लोहिया जी इंतज़ार करते रहे. कोई सदन में नहीं रहा, केवल दो-चार लोग रह गए. लेकिन लोहिया जी बैठे रहे कि चंद्रशेखर जी ने वादा किया था कि वह आ रहे हैं. पर चंद्रशेखर जी चले गए. चंद्रशेखर जी बोले, हम आज तक दु:खी होते हैं कि लोहिया जी इतनी देर तक इंतज़ार करते रहे. हमने समझा कि अब नहीं बैठे होंगे, इसलिए हम चले गए. बहुत सारी बातें हैं. हम उनके यहां रहते थे. वहां कोई चला जाए, उनका विरोधी चला जाए, चाहे उनका समर्थक चला जाए, कभी व्यवहार में अंतर नहीं आया. कई बार मैंने टोका उनको. मैं जाता था, तो मुझे गाड़ी तक छोड़ने आते थे. मैंने कई बार धक्का देकर कहा, नहीं, आप नहीं जाइएगा. मैंने एक बार गाड़ी जान-बूझकर बाहर सड़क पर खड़ी कराई. और, वह मुझे सड़क पर छोड़ने चले आए. उन्होंने कहा कि पार्टी का सम्मेलन कहां करना चाहते हो, तो मैंने दूसरी जगह बताई. इस पर उन्होंने कहा कि बलिया में ही होने दो. तब बलिया में ही हुआ था. देवीलाल जी भी गए थे और हम सब लोग गए थे. वहीं पर पार्टी के नाम में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था. चंद्रशेखर जी ने कहा, मैं तो समाजवादी हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है. देवीलाल से पूछ लो. देवीलाल जी ने कहा, जो चाहो सो रख लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है. पार्टी बनाओ, मजबूत बनाओ. तब नाम रखा गया था समाजवादी जनता पार्टी. ये थे बड़े नेता. जो सरलता चंद्रशेखर जी में थी, वही देवीलाल में थी. कर्पूरी ठाकुर की तो बात ही छोड़िए, कोई जवाब नहीं मिलेगा पूरे देश में. मैंने छह दिनों का दौरा किया था बिहार का. सात दिनों का था, लेकिन एक दिन पहले ही चला आया था. ये जितने समाजवादी हैं, उनकी अभी तक सादगी ज्यों की त्यों है. ये विचारधारा वाले लोग हैं, लोकभोजन, लोकभूषा और लोकभाषा. अभी एक शख्स ऐसा आया, इतना बढ़िया पैंट-शर्ट पहन कर, अभी परसों-तरसों की बात है. मैंने कहा कि खादी का बढ़िया पहन कर आता, तो मुझे आपत्ति नहीं होती, हैंडलूम ही पहन लेता. जब समाजवादी पार्टी ने साफ़ लिखा है कि हम खादी पहनेंगे, नहीं तो हैंडलूम पहनेंगे. चंद्रशेखर जी की सादगी समाजवादी सादगी थी. एक बार मैंने देखा कि कुछ दूसरे नेताओं ने अलग मंच लगा दिया और यशवंत सिंह ने अलग मंच लगा दिया. उन नेता से मैंने कहा कि मैं तो ज़रूर जाऊंगा, यशवंत सिंह ने मंच लगाया है और नारे मेरे लग रहे हैं, तो मैं कैसे नहीं जा सकता हूं. हम इनके मंच पर गए और इनको धन्यवाद भी दिया. इन्होंने अपना अलग मंच लगाया, उसका कारण सही था. मैंने कहा, चंद्रशेखर जी के ख़िलाफ़ बोलोगे, तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा. रात को जब डरौला पर ठहरे, साथ-साथ थे, तो मैंने कहा, चंद्रशेखर जी के ख़िलाफ़ कहीं आपने बोल दिया, तो मैं भी आपके साथ नहीं रहूंगा. खैर, नहीं बोले. आज ऐसे दिन जब मनाए जाते हैं, तो आपको प्रेरणा लेनी चाहिए. एक साधारण परिवार में, एक किसान परिवार में पैदा होकर चंद्रशेखर जी उच्चतम शिखर पर पहुंचे.**

मुलायम सिंह यादव

चंद्रशेखर जी के बारे में वही जानते हैं, जो उनके साथ रहे, उनके पीछे रहे. मुझे उनके भाषण सुनने के लोकसभा में भी बहुत-से मौक़े मिले. चंद्रशेखर जी ने कभी भी सदन का बहिष्कार नहीं किया. लेकिन, एक ऐसा मौक़ा आया कि उन्हें बहिष्कार करना पड़ गया. एक सवाल उठा दिया उन्होंने गांधी ट्रस्ट का. बनारस में गांधी ट्रस्ट स्थापित करने का काम चंद्रशेखर जी ने किया. लोकसभा में कुछ लोगों ने उन पर टिप्पणी कर दी. मुझमें और चंद्रशेखर जी में थोड़ा ही अंतर रहता था. तब वह उधर बैठते थे, हम इधर बैठते थे. मैंने चंद्रशेखर जी से कहा कि आप बोलिए. मैंने कहा, मैं तो बोलूंगा ही, आप बोलिए. तब वह बोले और उन्होंने बहुत मार्मिक भाषण दिया. उन्होंने कहा कि अगर हमने गांधी ट्रस्ट बनाया है, तो आप इस पर टिप्पणी करोगे? और जो कार्यक्रम हुए कई महान नेताओं पर, उस पर तो हमने टिप्पणी की नहीं थी. लेकिन वह टिप्पणी ऐसी थी, जिसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था. हम उस पर बोले और बोलने के बाद मैंने कहा, टिप्पणी करने वाले माफी मांगें. हमारे बोलने के बाद जब मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया और सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया, तो हमने सदन का बहिष्कार कर दिया. चूंकि वह सवाल उठाया था चंद्रशेखर जी ने, हमने तो उनका समर्थन किया था, लेकिन उन्हें बहिष्कार करना पड़ गया. उन्होंने मेरी पीठ पर मारा थप्पड़ और कहा, मैं पहली बार सदन से बहिष्कार कर रहा हूं. आपने मुझे मजबूर कर दिया, क्योंकि मेरा ही सवाल था. उस सवाल पर आपने जो बहिष्कार किया, तो मैंने सोचा कि यदि अब हम नहीं करेंगे, तो बड़ी दिक्कत होगी. उन्होंने कहा, मैंने कभी भी सदन का बहिष्कार नहीं किया और आज पहली बार मुलायम सिंह ने मुझे मजबूर कर दिया. वह सेंट्रल हाल चले आए, किया बहिष्कार.

मैंने लोहिया जी के जन्म दिन के अवसर पर भी कहा था कि चंद्रशेखर जी के आचरण, सादगी और ईमानदारी को आप एक मिसाल समझें. इतनी सादगी किसी नेता में नहीं थी. या तो डॉ. लोहिया में थी या फिर चंद्रशेखर जी में. कुछ लोग तो प्रधानमंत्री बनते-बनते न जाने कौन-कौन से कपड़े बदल कर पहनने लगते. चंद्रशेखर जी जो कपड़े रोज़ाना पहनते थे, वही धोती-कुरता, उसी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनकर पहना. वह जो सोचते थे, वही करते थे, लेकिन कभी समझौता नहीं करते थे. इसी बात को लेकर वह बहुत लंबे समय तक सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जयप्रकाश जी के साथ रहे, लोहिया जी के साथ भी रहे. एक बार मैंने कहा, आप सोशलिस्ट पार्टी में थे और आप लोहिया जी का बहुत सम्मान करते हो. इस पर उन्होंने दु:खी होकर कहा, आज तक मुझे बहुत बड़ा पश्चाताप है, आख़िरी तक वह पश्चाताप हम भूल नहीं पा रहे हैं. हमने कहा कि मामला क्या है? दरअसल, बात यह थी कि तब चंद्रशेखर जी कांग्रेस में चले गए थे. एक दिन लोहिया जी सेंट्रल हाल में बैठे थे. उसी वक्त इंदिरा जी ने चंद्रशेखर जी को बुलवाया. लोहिया जी ने कहा, चंद्रशेखर जी, इतनी तेजी से कहां जा रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा, अभी लौटकर आ रहा हूं लोहिया जी. लेकिन उन्हें देर हो गई और देर होने पर उन्होंने सोचा कि अब लोहिया जी नहीं होंगे. इधर लोहिया जी इंतज़ार करते रहे. कोई सदन में नहीं रहा, केवल दो-चार लोग रह गए. लेकिन लोहिया जी बैठे रहे कि चंद्रशेखर जी ने वादा किया था कि वह आ रहे हैं. पर चंद्रशेखर जी चले गए. चंद्रशेखर जी बोले, हम आज तक दु:खी होते हैं कि लोहिया जी इतनी देर तक इंतज़ार करते रहे. हमने समझा कि अब नहीं बैठे होंगे, इसलिए हम चले गए. बहुत सारी बातें हैं. हम उनके यहां रहते थे. वहां कोई चला जाए, उनका विरोधी चला जाए, चाहे उनका समर्थक चला जाए, कभी व्यवहार में अंतर नहीं आया. कई बार मैंने टोका उनको. मैं जाता था, तो मुझे गाड़ी तक छोड़ने आते थे. मैंने कई बार धक्का देकर कहा, नहीं, आप नहीं जाइएगा. मैंने एक बार गाड़ी जान-बूझकर बाहर सड़क पर खड़ी कराई. और, वह मुझे सड़क पर छोड़ने चले आए. उन्होंने कहा कि पार्टी का सम्मेलन कहां करना चाहते हो, तो मैंने दूसरी जगह बताई. इस पर उन्होंने कहा कि बलिया में ही होने दो. तब बलिया में ही हुआ था. देवीलाल जी भी गए थे और हम सब लोग गए थे. वहीं पर पार्टी के नाम में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था. चंद्रशेखर जी ने कहा, मैं तो समाजवादी हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है. देवीलाल से पूछ लो. देवीलाल जी ने कहा, जो चाहो सो रख लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है. पार्टी बनाओ, मजबूत बनाओ. तब नाम रखा गया था समाजवादी जनता पार्टी. ये थे बड़े नेता. जो सरलता चंद्रशेखर जी में थी, वही देवीलाल में थी. कर्पूरी ठाकुर की तो बात ही छोड़िए, कोई जवाब नहीं मिलेगा पूरे देश में. मैंने छह दिनों का दौरा किया था बिहार का. सात दिनों का था, लेकिन एक दिन पहले ही चला आया था. ये जितने समाजवादी हैं, उनकी अभी तक सादगी ज्यों की त्यों है. ये विचारधारा वाले लोग हैं, लोकभोजन, लोकभूषा और लोकभाषा. अभी एक शख्स ऐसा आया, इतना बढ़िया पैंट-शर्ट पहन कर, अभी परसों-तरसों की बात है. मैंने कहा कि खादी का बढ़िया पहन कर आता, तो मुझे आपत्ति नहीं होती, हैंडलूम ही पहन लेता. जब समाजवादी पार्टी ने साफ़ लिखा है कि हम खादी पहनेंगे, नहीं तो हैंडलूम पहनेंगे. चंद्रशेखर जी की सादगी समाजवादी सादगी थी. एक बार मैंने देखा कि कुछ दूसरे नेताओं ने अलग मंच लगा दिया और यशवंत सिंह ने अलग मंच लगा दिया. उन नेता से मैंने कहा कि मैं तो ज़रूर जाऊंगा, यशवंत सिंह ने मंच लगाया है और नारे मेरे लग रहे हैं, तो मैं कैसे नहीं जा सकता हूं. हम इनके मंच पर गए और इनको धन्यवाद भी दिया. इन्होंने अपना अलग मंच लगाया, उसका कारण सही था. मैंने कहा, चंद्रशेखर जी के ख़िलाफ़ बोलोगे, तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा. रात को जब डरौला पर ठहरे, साथ-साथ थे, तो मैंने कहा, चंद्रशेखर जी के ख़िलाफ़ कहीं आपने बोल दिया, तो मैं भी आपके साथ नहीं रहूंगा. खैर, नहीं बोले. आज ऐसे दिन जब मनाए जाते हैं, तो आपको प्रेरणा लेनी चाहिए. एक साधारण परिवार में, एक किसान परिवार में पैदा होकर चंद्रशेखर जी उच्चतम शिखर पर पहुंचे.

**मैं जब तक मिनिस्टर नहीं बना, तो लोग कहते थे कि मुलायम सिंह यादवों के घर कैसे पैदा हो गए, उन्हें तो बनिया या ब्राह्मण के घर पैदा होना चाहिए था. जब मिनिस्टर बन गया 1977 में, तो मेरे ख़िलाफ़ ऐसी किताब छपी, जिसकी एक-एक लाइन गंदी थी. उसे चौधरी साहब (चरण सिंह) को दिखा दिया गया. फाड़कर फेंक दी उन्होंने, बोले, क्या बात करते हो? यह बेचारा मामूली मिनिस्टर है. मैंने कभी परवाह नहीं की. जो लोग आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वे नेता कभी नहीं बन सकते. चंद्रशेखर जी की कितनी आलोचना होती थी. और वही जब मिलने जाता, तो ऐसे बैठा लेते थे कि उनका सबसे ज़्यादा प्रिय यही है. यह गुण था उनके अंदर. एक बार सर्दी का मौसम था. अमिताभ बच्चन शॉल ओढ़े चुपचाप बैठे थे. हमने देखा ही नहीं, कौन बैठा है और जाकर बैठ गए ऐसे ही. तब चंद्रशेखर जी ने कहा, देखा नहीं, कौन बैठा है? तब मैंने देखा कि अरे, यह तो अमिताभ बच्चन बैठे हैं. एक काम था उनका, चंद्रशेखर जी ने तुरंत कर दिया.**

मैं जब तक मिनिस्टर नहीं बना, तो लोग कहते थे कि मुलायम सिंह यादवों के घर कैसे पैदा हो गए, उन्हें तो बनिया या ब्राह्मण के घर पैदा होना चाहिए था. जब मिनिस्टर बन गया 1977 में, तो मेरे ख़िलाफ़ ऐसी किताब छपी, जिसकी एक-एक लाइन गंदी थी. उसे चौधरी साहब (चरण सिंह) को दिखा दिया गया. फाड़कर फेंक दी उन्होंने, बोले, क्या बात करते हो? यह बेचारा मामूली मिनिस्टर है. मैंने कभी परवाह नहीं की. जो लोग आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वे नेता कभी नहीं बन सकते. चंद्रशेखर जी की कितनी आलोचना होती थी. और वही जब मिलने जाता, तो ऐसे बैठा लेते थे कि उनका सबसे ज़्यादा प्रिय यही है. यह गुण था उनके अंदर. एक बार सर्दी का मौसम था. अमिताभ बच्चन शॉल ओढ़े चुपचाप बैठे थे. हमने देखा ही नहीं, कौन बैठा है और जाकर बैठ गए ऐसे ही. तब चंद्रशेखर जी ने कहा, देखा नहीं, कौन बैठा है? तब मैंने देखा कि अरे, यह तो अमिताभ बच्चन बैठे हैं. एक काम था उनका, चंद्रशेखर जी ने तुरंत कर दिया. इतने आरोप लगने के बाद. उन्होंने पता पहले ही लगा लिया था कि अमिताभ बच्चन बिल्कुल निर्दोष हैं, उन्हें कैसे फंसाया गया था. तारीख कहां पड़ती थी विदेश में और विदेश में तारीख पड़ने का वकील कितने में खड़ा होता, कितना खर्च होता था. बर्बाद कर दिया था. अमिताभ बच्चन ने कोई परवाह नहीं की. आज कोई है मुकाबला इस कलाकार का. सबने मान लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार अमिताभ बच्चन.

जयप्रकाश जी का आंदोलन चला, तो उनकी मीटिंग यूपी निवास में हुई. चौधरी साहब बोले, क्या करते हो? तुम भी समाजवाद को मानते नहीं हो. भाई, पांच साल के लिए जनता ने उनको जनादेश दिया है. तब हम लोग निकलेंगे एक साथ. मैंने कहा, यहां नीति हमारी पार्टी की कुछ और है कि जहां अन्याय हो, पक्षपात हो, वहीं संघर्ष करो. राज नारायण जी ने कहा, तुम्हीं समझाओ जाकर. मान गए चौधरी साहब और मीटिंग में गए. मीटिंग में ही सबके सब गिरफ्तार कर लिए गए, चौधरी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनको भी जेल में डाल दिया गया. वह सात महीने जेल में रहे. चुगलखोरों ने जाकर कह दिया कांग्रेस के नेताओं से कि उनको छोड़ दो, तो हम आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे. उन्हें बाद में पता चला कि कौन-कौन थे, तीनों को पार्टी से निकाल दिया. तीनों षड्यंत्रकारी थे. और फिर निकल पड़े इमरजेंसी के ख़िलाफ़. आपको पता है कितने समय तक बोले हैं विधानसभा के अंदर? दो घंटे. दो घंटे उन्होंने इमरजेंसी लगाने वालों, प्रधानमंत्री और सबकी इतनी आलोचना की जबरदस्त विधानसभा के अंदर. अख़बारों में छपा. मैं तो जेल में था. उस समय ऐसे पत्रकार थे, जो कभी नहीं झुके. मैंने पत्रकारों से कहा भी था, मेरा सुप्रीम कोर्ट में सम्मान किया गया था. मैंने कहा, इस देश के पत्रकार कभी नहीं झुके, ज्यूडिशिरी ने भी कभी परवाह नहीं की. लेकिन, एक मौक़ा ऐसा आया, जब पत्रकार भी झुक गए और ज्यूडिशरी भी. आपके समाजवादी आंदोलन ने मामूली काम नहीं किया है. अगर हिंदुस्तान में कहीं काम हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर. लेकिन, यह बात हमारे एक भी साथी के मुंह से नहीं निकलती. मैंने कहा, कार्यकर्ता मीटिंग में कहो कि क्या-क्या किया है. ऐसा हिंदुस्तान में कोई भी राज्य सरकार नहीं कर रही, जैसा उत्तर प्रदेश की कर रही है.

हम आपसे कहना चाहते हैं कि सीखना चाहिए चंद्रशेखर जी और अन्य महापुरुषों से. चंद्रशेखर जी भले ही थोड़े दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने. बाहर थे, तब भी उनके भाषण वही होते थे. युवा तुर्क कहलाते थे वह. चंद्रशेखर जी, आजमगढ़ के एक हरिजन नेता और एक अन्य, ये तीनों लड़ते थे. चौथे थोड़े-बहुत राम सरोही थे बिहार के. वह भी अपनी सरकार के ख़िलाफ़ बोलते थे. और, कांग्रेस की नाक में दम कर देते थे. चंद्रशेखर जी ने जब कभी सच्चाई समझी, तो संकोच नहीं किया. हमने कई बार आपसे कहा कि जहां अन्याय हो, वहां विरोध करो. एक बार हम लोग राज नारायण जी को इटावा स्टेशन छोड़ने आए. राज नारायण जी चल रहे थे, तो पुलिस ने भीड़ हटाने के लिए किसी को एक थप्पड़ मार दिया. सब वहीं के वहीं खड़े हो गए. मैंने कहा, तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा? जवाब मिला, राज नारायण जी के रास्ते में भीड़ हो रही थी, इसलिए थप्पड़ मारा. राज नारायण जी बोले, आपने डांट दिया, इतना ही काफी है. चंद्रशेखर जी ने कहा, इसने मेरे सामने थप्पड़ मारा. अन्याय होगा, तो विरोध नहीं करेंगे?

चंद्रशेखर जी जहां अन्याय होता था, वहां खड़े हो जाते थे, अन्याय करने वाले के ख़िलाफ़. एक साधारण परिवार में रहकर उनकी पढ़ाई कैसे चली. उन्होंने बताया था मुझे कि कैसे वह पढ़ पाए और अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े. उसके बाद निकल कर कहां पहुंचे, देश के सबसे उच्च पद पर. स्वाभिमान के ख़िलाफ़ समझौता न करने की वजह से वह प्रधानमंत्री पद से हटे. उन्होंने कहा कि वह स्वाभिमान के ख़िलाफ़ कभी समझौता नहीं करेंगे. उन्होंने किसी को नहीं हटाया. वह कभी पद के भूखे नहीं रहे. मैंने एक बार आपसे कहा था. आपने देखा होगा कि महादेव जी की बारात में कैसे-कैसे लोग थे. किसी की एक आंख थी, किसी के कुछ. इसी तरह राजनीतिक दल भी महादेव की बारात बनकर चलें, तो वे मजबूत होंगे और कामयाबी मिलेगी.■

*लेखक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं.*

## हसदेव अरण्य

# क्या किसानों-आदिवासियों का दुःख दूर कर पाएंगे राहुल

शशि शेखर

जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई बहुत पुरानी है. जंगल में रहने वालों का मानना है कि उस पर पहला अधिकार उनका है, क्योंकि जंगल ही उनके जीने और रोजी–रोटी का सहारा है. बात सही भी है. जंगल आज भी देश के करोड़ों लोगों के लिए रहने, खाने और जीने का सहारा है. एक उदाहरण अगर हसदेव अरण्य वन्य क्षेत्र का लें, तो यह बात सौ फ़ीसद सही साबित होती है. छत्तीसगढ़ के कोरबा, सरगुजा एवं रायगढ़ ज़िलों में फैला हुआ हसदेव अरण्य आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है. यह क्षेत्र संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत आता है. यहां पर रहने वाले आदिवासियों की आजीविका, संस्कृति एवं जीवनशैली पूर्ण रूप से जंगल और खेती पर ही निर्भर है, जिसका वे पीढ़ियों से संरक्षण व संवर्धन करते आए हैं. यह इलाका बहुत ही समृद्ध एवं जैव विविधता से परिपूर्ण है और कई महत्वपूर्ण वन्य–जीवों का आवास स्थल भी है. इसलिए यह वन संपदा न सिर्फ़ स्थानीय, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है.

वर्ष 2009 में इस संपूर्ण कोल फील्ड को खनन के लिए नो गो एरिया घोषित किया गया था, लेकिन इस सबके बाद भी मौजूदा केंद्रीय सरकार ने इस इलाके में कोयला खदानों का आवंटन किया है. छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन इस मसले पर सालों से विरोध करता आ रहा है. उसकी मांग है कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में आवंटित कोयला खदानों को तुरंत निरस्त किया जाए और पूरे हसदेव अरण्य को खनन से मुक्त रखा जाए. इसके साथ ही हसदेव अरण्य क्षेत्र की क़रीब 20 ग्राम सभाओं ने एक प्रस्ताव पारित करके यह साफ़ कर दिया था कि वे अपने क्षेत्र में होने वाले कोल ब्लॉक आवंटन और कोयला खनन का विरोध करेंगी, लेकिन कोल ब्लॉक आवंटन के वक्त ग्राम सभाओं के उस प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि चूंकि हमारे क्षेत्र में पेसा एक्ट (पंचायत एक्सटेंशन टू शिड्यूल एरिया एक्ट, जो आदिवासी इलाकों को विशेषाधिकार देता है) लागू है, इसलिए किसी भी कोल ब्लॉक के लिए ज़मीन अधिग्रहण करने से पहले सरकार को यहां की ग्राम सभाओं की अनुमति लेना आवश्यक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं.

बहरहाल, अब कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई है. जून के दूसरे सप्ताह में वह छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले के मदनपुर गांव में किसानों एवं आदिवासियों के बीच पहुंचे. राहुल गांधी ने कहा कि जंगलों पर वहां निवास करने वाले आदिवासियों का हक़ है. कोयला खदान बनने से जंगल ख़त्म हो जाएंगे, तो आदिवासियों के हाथ कट जाएंगे. राहुल गांधी ने मौजूदा केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण क़ानून का उल्लेख करते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने अपने भूमि अधिग्रहण अधिनियम में पंचायतों, ग्राम सभाओं और किसानों–आदिवासियों की सहमति से ही भूमि लेने का प्रावधान किया था. अधिग्रहीत भूमि पर पांच वर्ष में उद्योग न लगाने पर किसानों को उनकी ज़मीन वापस देने का नियम बनाया गया था, लेकिन एनडीए सरकार ने उक्त सारे नियम–प्रावधान बदल दिए हैं. राहुल गांधी ने मदनपुर में एकत्र हुए ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी और वह उनके साथ हैं. ग़ौरतलब है कि मदनपुर हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्रों के तहत कोयला खदानों के ख़िलाफ़ लोगों के विरोध का केंद्र रहा है. राहुल गांधी ने मदनपुर साउथ, ईस्ट और मोरगा कोल ब्लॉक से प्रभावित होने वाले मदनपुर, पतुरियाडांड, गिद्धमुड़ी, मोरगा, भुलसीभावना, खिरटी, उच्चलेंगा, पुटा, परोगिया, जामपानी, कैरहियापारा, साल्टी, घाटबरी, हरिहरपुर एवं फतेपुर सहित 20 गांवों के निवासियों से मुलाकात करके उनसे चर्चा की. मौजूदा सरकार ने इस क्षेत्र में सात कोल ब्लॉक आवंटित किए हैं, जिनका भंडार अनुमानित तौर पर 5.53 अरब टन का है. इन ब्लॉकों में से तीन परिचालन में हैं, जिनमें चोटिया खदान बाल्को को प्रकाश इंडस्ट्रीज से मिली है और दो खदानें राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड को आवंटित की गई हैं, जो माइंस डेवलपर एंड ऑपरेटर (एमडीए) मॉडल के तहत अडाणी माइनिंग द्वारा संचालित हैं. तीन ब्लॉक छत्तीसगढ़ पावर जेनरेशन कंपनी को, जबकि तारा में एक ब्लॉक नीलामी में जिंदल को मिलने के बाद अभी स्वीकृति नहीं मिली है.

ग्रामीणों ने बताया कि हसदेव अरण्य क्षेत्र कोरबा और सरगुजा में फैला हुआ है. इस क्षेत्र में कुल 20 कोल ब्लॉक हैं, जिनमें 45,883 एकड़ भूमि समाहित होगी. इसमें अकेले कोरबा ज़िले की 26,712.67 एकड़ भूमि शामिल है. बहरहाल, हसदेव अरण्य क्षेत्र के लोग कोल ब्लॉक आवंटन का अभी भी विरोध कर रहे हैं. उन्हें लगता है कि कोल ब्लॉक के चलते उनकी आजीविका छिन जाएगी, विस्थापन होगा और आदिवासी संस्कृति ख़तरे में पड़ जाएगी. लेकिन, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस विरोध का कोई मायने है? क्योंकि, मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कोल ऑर्डिनेंस में ऐसे प्रावधान हैं, जिनकी वजह से ग्रामीणों का विरोध कोई मायने नहीं रखता. इस अध्यादेश में कहा गया है कि कोयला खनन का विरोध करने पर प्रतिदिन एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर इस तरह का काम दोबारा होता है, तो प्रतिदिन दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.■

feedback@chauthiduniya.com

### हसदेव अरण्य संरक्षित क्षेत्र क्यों नहीं

**हसदेव अरण्य वन्य क्षेत्र मध्य भारत के कुछ बड़े वन्य क्षेत्रों में से एक है. जैव विविधता से भरे इस क्षेत्र में कई दुर्लभ जड़ी-बूटियां और वन्य-जीव पाए जाते हैं. इस समृद्ध पर्यावरणीय क्षेत्र में, कोयला मंत्रालय के मुताबिक, 1,878 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक बिलियन मीट्रिक टन कोयले का भंडार है. इसमें से 1,502 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन क्षेत्र है. 2010 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई थी. उस रिपोर्ट केआधार पर हसदेव अरण्य क्षेत्र को नो गो एरिया घोषित कर दिया गया. इसका अर्थ यह हुआ कि इस क्षेत्र में कोई कंपनी जाकर खनन का काम नहीं कर सकती. इससे पहले भी राज्य सरकार ने हसदेव अरण्य वन्य क्षेत्र को हाथी अभयारण्य घोषित करने केलिए एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा था. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने उस पर अपनी मुहर भी लगा दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया. यह कहा जाता है कि सीआईआई ने छत्तीसगढ़ में कोयले की प्रचुरता को देखते हुए इस फ़ैसले पर आपत्ति जताई थी. दरअसल, एक बार अगर कोई वन्य क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र या राष्ट्रीय अभयारण्य घोषित हो जाता है, तो उस इलाके में खनन कार्य नहीं किया जा सकता.**

# रोज़ एक कानून खत्म करने के दावे की हकीकत

शफीक आलम

सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार पुराने, बेकार और अप्रासंगिक हो चुके क़ानूनों में से रोज़ाना एक क़ानून से जनता का पीछा छुड़ाएगी. दवा की खुराक की तरह पेश किए जाने वाले इस नुस्खे से आशा थी कि बहुत–से बेकार और अप्रासंगिक हो चुके कम से कम 300 क़ानूनों से जनता का पीछा बहुत जल्द छूट जाएगा, लेकिन हाल में चौथी दुनिया द्वारा विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में दाखिल की गई आरटीआई के जवाब में जो तथ्य सामने आए हैं, उनके मुताबिक, इस दिशा में कोई पर्याप्त प्रगति होती नज़र नहीं आ रही है. चौथी दुनिया ने इस आरटीआई के ज़रिये यह जानने की कोशिश की कि अब तक सरकार ने कौन–कौन से क़ानून निरस्त किए हैं? लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स पर कोई कार्रवाई हुई है या नहीं? इस संबंध में क्या कोई बिल लोकसभा में पेश किया गया है?

इस आरटीआई के जवाब में कहा गया कि नई सरकार की तरफ़ से अब तक कोई भी अधिनियम निरस्त नहीं हुआ है. हालांकि, लॉ कमीशन ने हालिया दिनों में अपनी चार रिपोर्ट्स 248वीं, 249वीं, 250वीं और 251वीं पेश की हैं, जिनमें क्रमश: 72, 113, 74 और 30 बेकार और अप्रासंगिक हो चुके क़ानूनों (जिनमें कुछ राज्यों के क़ानून भी शामिल हैं) की पहचान करके उन्हें जल्द से जल्द निरस्त करने की सिफारिश की गई है. विधायी विभाग का कहना है कि उसने संबंधित मंत्रालयों–विभागों व राज्य सरकारों की राय और कार्रवाई के लिए उक्त सिफारिशें भेज दी हैं, लेकिन अभी तक कहीं से भी इसका जवाब नहीं आया है. इस पर आख़िरी फ़ैसला संबंधित मंत्रालयों–विभागों और राज्य सरकारों की राय के बाद ही लिया जाएगा. जवाब में यह भी कहा गया कि एक सितंबर, 2014 को अप्रासंगिक और बेकार क़ानूनों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक दो सदस्यीय समिति गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में 637 क़ानून रद्द करने की सिफारिश की है. इस रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों–विभागों और राज्य सरकारों को विधायी विभाग द्वारा पत्र लिखे जा रहे हैं. इन तथ्यों से तो यही ज़ाहिर होता है कि सरकारी दावों के विपरीत ज़्यादातर चिन्हित किए गए बेकार और अप्रासंगिक क़ानून अभी तक केवल विभागीय कार्रवाई के मायाजाल में ही फंसे हुए हैं. ख्याल रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से उनके मंत्रालय के पहले 100 दिनों के कार्य का लक्ष्य तय करने के लिए भी कहा था. इस संबंध में उन्होंने तत्कालीन विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद को प्राथमिकता के आधार पर ऐसे क़ानूनों की पहचान करने की ज़िम्मेदारी सौंपी थी, जो बेकार हो चुके हैं. पिछली एनडीए सरकार ने भी 1998 में इस संबंध में प्रशासनिक क़ानूनों की एक समिति गठित की थी, जिसने 1,382 अप्रासंगिक क़ानूनों की सूची पेश की थी. उन 1,382 क़ानूनों में से अब तक केवल 415 क़ानून ही रद्द किए जा सके हैं. इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी ने विधि आयोग को भी पत्र लिखकर अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करने के लिए कहा था. निजी तौर पर भी लोगों ने इस संबंध में अपनी तरफ़ से ऐसे क़ानूनों की सूची प्रकाशित की, जो आज अप्रासंगिक और हास्यास्पद हो चुके हैं.

बहरहाल, मोदी सरकार की तरफ़ से वर्ष 2014 में संसद में दो विधेयक पेश किए गए. निरस्त एवं संशोधन विधेयक–2014 में कुल 36 क़ानून शामिल थे, जिनमें 32 संशोधन अधिनियम और केवल चार मूल अधिनियम थे. उसके बाद सरकार ने निरस्त एवं संशोधन (द्वितीय) विधेयक–2014 पेश किया, जिसमें 88 ऐसे संशोधन अधिनियमों को क़ानून की किताब से हटाने की बात कही गई थी, जो अप्रासंगिक हो चुके थे और जिन्हें एक अलग अधिनियम के तौर पर रखना ज़रूरी नहीं था. आरटीआई के जवाब में कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की स्वीकृति के बाद ये दोनों विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिए गए हैं. यहां पर यह बता देना ज़रूरी है कि ये वे क़ानून थे, जो दूसरे क़ानून बन जाने की वजह से अप्रासंगिक हो गए थे या जिनमें भाषा की त्रुटि थी. जब इन्हें रद्द करने में इतना समय लग रहा है, तो जिन अप्रासंगिक क़ानूनों की बात सरकार कर रही है, उन्हें ख़त्म होने में कई साल लग जाएंगे या कम से कम इस लोकसभा के कार्यकाल में तो यह कार्य संभव नहीं हो पाएगा.

अख़बारों में छपने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर फिलहाल तक़रीबन 1,400 क़ानून रद्द करने का लक्ष्य रखा है. कुछ विधि विशेषज्ञ तक़रीबन 3,000 क़ानूनों को अनावश्यक क़ानून के दायरे में रख रहे हैं. लेकिन, अब तक की कार्रवाई से नतीजा यह निकलता है कि सरकार ने जिस उत्साह से इस मुद्दे को उठाया था, वह उत्साह अब कहीं खो गया है. नतीजतन, जनता को इंडिया ट्रेजर ट्रोव एक्ट–1878, दि बंगलौर मैरिजेज वेलिडेटिंग एक्ट–1934, दि इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट–1898, दि संथाल परगना एक्ट–1855, दि शेरिफ फीस एक्ट–1852, कॉफी एक्ट–1942, दि न्यूज पेपर (प्राइस एंड पेज) एक्ट–1956, यंग पर्सन्स (हार्मफुल पब्लिकेशंस) एक्ट–1956, एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स एक्ट–1948, विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए (भूमि अधिग्रहण) अधिनियम–1948 और इंडियन इंडिपेंडेंस पाकिस्तान कोर्ट्स (पेंडिंग प्रोसेडिंग्स) एक्ट–1952 जैसे बिल्कुल अप्रासंगिक और हास्यास्पद क़ानून कुछ दिन और बर्दाश्त करने पड़ेंगे.

दरअसल, ये वे क़ानून हैं, जिनका इस्तेमाल न केवल आम लोगों को परेशान करने के लिए किया जाता है, बल्कि हमारे देश में चलने वाली लंबी क़ानूनी प्रक्रिया को और जटिल बनाने के लिए भी होता है. ये क़ानून भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देते हैं, क्योंकि आम लोग लंबी क़ानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए किसी अधिकारी–कर्मचारी को रिश्वत देना ज़्यादा आसान समझते हैं. और, इन सबके बीच जिस तरह से मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण विधेयक पर अड़ी हुई है, उसे देखते हुए यह आशंका अभी भी बरकरार है कि कहीं बेकार और अप्रासंगिक क़ानूनों के चक्कर में मज़दूरों और किसानों के अधिकार वाले क़ानून भी न समाप्त कर दिए जाएं.■

feedback@chauthiduniya.com

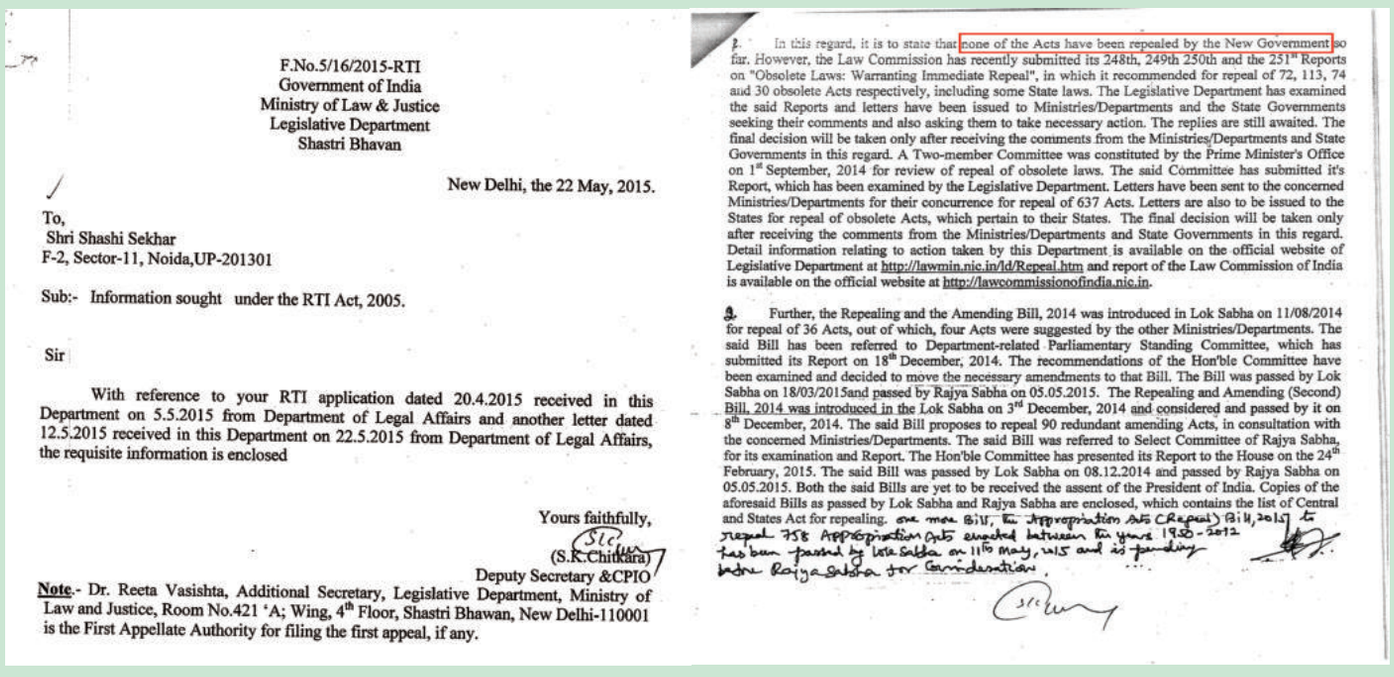

F.No.5/16/2015-RTI
Government of India
Ministry of Law & Justice
Legislative Department
Shastri Bhavan

New Delhi, the 22 May, 2015.

To,
Shri Shashi Sekhar
F-2, Sector-11, Noida,UP-201301

Sub:- Information sought under the RTI Act, 2005.

Sir

With reference to your RTI application dated 20.4.2015 received in this Department on 5.5.2015 from Department of Legal Affairs and another letter dated 12.5.2015 received in this Department on 22.5.2015 from Department of Legal Affairs, the requisite information is enclosed

Yours faithfully,
(S.K.Chitkara)
Deputy Secretary &CPIO

Note.- Dr. Reeta Vasishta, Additional Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice, Room No.421 'A; Wing, 4th Floor, Shastri Bhawan, New Delhi-110001 is the First Appellate Authority for filing the first appeal, if any.

2. In this regard, it is to state that none of the Acts have been repealed by the New Government so far. However, the Law Commission has recently submitted its 248th, 249th 250th and the 251st Reports on "Obsolete Laws: Warranting Immediate Repeal", in which it recommended for repeal of 72, 113, 74 and 30 obsolete Acts respectively, including some State laws. The Legislative Department has examined the said Reports and letters have been issued to Ministries/Departments and the State Governments seeking their comments and also asking them to take necessary action. The replies are still awaited. The final decision will be taken only after receiving the comments from the Ministries/Departments and State Governments in this regard. A Two-member Committee was constituted by the Prime Minister's Office on 1st September, 2014 for review of repeal of obsolete laws. The said Committee has submitted it's Report, which has been examined by the Legislative Department. Letters have been sent to the concerned Ministries/Departments for their concurrence for repeal of 637 Acts. Letters are also to be issued to the States for repeal of obsolete Acts, which pertain to their States. The final decision will be taken only after receiving the comments from the Ministries/Departments and State Governments in this regard. Detail information relating to action taken by this Department is available on the official website of Legislative Department at http://lawmin.nic.in/ld/Repeal.htm and report of the Law Commission of India is available on the official website at http://lawcommissionofindia.nic.in.

3. Further, the Repealing and the Amending Bill, 2014 was introduced in Lok Sabha on 11/08/2014 for repeal of 36 Acts, out of which, four Acts were suggested by the other Ministries/Departments. The said Bill has been referred to Department-related Parliamentary Standing Committee, which has submitted its Report on 18th December, 2014. The recommendations of the Hon'ble Committee have been examined and decided to move the necessary amendments to that Bill. The Bill was passed by Lok Sabha on 18/03/2015and passed by Rajya Sabha on 05.05.2015. The Repealing and Amending (Second) Bill, 2014 was introduced in the Lok Sabha on 3rd December, 2014 and considered and passed by it on 8th December, 2014. The said Bill proposes to repeal 90 redundant amending Acts, in consultation with the concerned Ministries/Departments. The said Bill was referred to Select Committee of Rajya Sabha, for its examination and Report. The Hon'ble Committee has presented its Report to the House on the 24th February, 2015. The said Bill was passed by Lok Sabha on 08.12.2014 and passed by Rajya Sabha on 05.05.2015. Both the said Bills are yet to be received the assent of the President of India. Copies of the aforesaid Bills as passed by Lok Sabha and Rajya Sabha are enclosed, which contains the list of Central and States Act for repealing. one more Bill, the Appropriation Acts (Repeal) Bill, 2015 to repeal 758 Appropriation Acts enacted between the years 1950-2012 has been passed by Lok Sabha on 11th May, 2015 and is pending before Rajya Sabha for consideration.

## पत्रकार हत्या के मामले में खुल गई समाजवाद की कलई

# हत्यारोपी मंत्री के बचाव में ताल ठोंक रही सरकार

प्रभात रंजन दीन

कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह राष्ट्रीय अधिवेशन के मंच से लेकर प्रांतीय बैठकों के मंच तक से लगातार यह कहते रहे कि प्रदेश सरकार के मंत्री ग़लत धंधों में लगे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कान में तेल डाले पड़े रहे. पत्रकार जगेंद्र की हत्या के आरोपी मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा के तमाम गोरखधंधों के बारे में मुलायम सिंह को चिट्ठी लिखकर बताने वाले पूर्व विधायक देवेंद्र पाल सिंह को ही पार्टी से निकाल बाहर किया गया. बहरहाल, शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र सिंह की नृशंस हत्या पूरे देश में चर्चा में है. मंत्री की नृशंसता के साथ-साथ पार्टी के शीर्ष नेताओं की अमानवीयता भी चर्चा में है. किसी ज़िंदा व्यक्ति के शरीर पर पेट्रोल उड़ेल कर आग लगा देना और उस व्यक्ति का अस्पताल में चीख-चीख कर अपराधियों का नाम बताना, किसी भी व्यक्ति को झकझोर कर रख देने के लिए काफी है, लेकिन नेताओं की खाल तो देखिए! उत्तर प्रदेश सरकार के हत्यारोपी मंत्री राममूर्ति वर्मा के बचाव में सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. राम गोपाल यादव फौरन कूद पड़े और राममूर्ति वर्मा के लिए चरित्र का प्रमाण-पत्र बांटने लगे. पत्रकार जगेंद्र के जख्मी होने से लेकर उनकी मौत के बाद तक जो भी तूल मचा, वह मझोले एवं छोटे दर्जे के फ्रेम में रखकर देखे जाने वाले पत्रकारों के कारण संभव हुआ. बाद में बड़े पत्रकार-नेताओं ने अपनी दुकानदारी चलाई.

उधर, जगेंद्र का परिवार, साथ में कुछ पत्रकार और गांव वाले शाहजहांपुर में भूख हड़ताल पर बैठे हैं. आग से जलाकर जगेंद्र के मारे जाने पर जब सरकार की खाल पर कोई असर नहीं पड़ा, तो उनके परिवार के अनशन पर होने से सरकार पर क्या फ़र्क़ पड़ता है! जगेंद्र के पिता सुमेर सिंह, पत्नी सुमन सिंह, बेटी दीक्षा, बहन गरिमा, बहू नित्या सिंह और बेटे राजवेंद्र, पुष्पेंद्र एवं राहुल के साथ गांव के लोग भी अनशन पर हैं. परिवार का कहना है कि राममूर्ति वर्मा के मंत्री पद पर रहते मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती. जब तक उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, अनशन और धरना जारी रहेगा. उत्तर प्रदेश और देश की जनता समवेत स्वर से मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है, विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, जगेंद्र के परिवार वाले सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार जगेंद्र के हत्या-प्रकरण की हत्या करने की कोशिशों में लगी है. मामले को सीबीसीआईडी को सौंपने की निर्लज्ज सत्ताई कोशिशें चल रही हैं. सब जानते हैं कि जिस मामले को दफन करना होता है, उसे सरकार सीबीसीआईडी को सौंप देती है.

अभी हाल ही में एक इंजीनियर की नृशंस हत्या करने वाले बांसगांव के विधायक और उसकी पत्नी को बचाने के लिए सरकार ने मामले को सीबीसीआईडी के पास दफा कर दिया. शासन के इस रवैये का प्रशासन पर क्या असर पड़ता है, इसका उदाहरण शाहजहांपुर की ज़िलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना हैं. उन्होंने कहा कि वह मौक़े पर इसलिए नहीं गईं, क्योंकि वहां जातीं तो

**मुलायम सिंह को मंत्री के कारनामे बताने के जुर्म में पार्टी से निकाले गए पूर्व विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि उन्होंने सरकार के आला लोगों से मिलकर पहले ही बता दिया था कि शाहजहांपुर में कुछ गड़बड़ होने वाला है. जगेंद्र सिंह को लगातार मंत्री की ओर से धमकियां दी जा रही थीं. इस बारे में भी सरकार को पता था. पता नहीं क्यों सपा सरकार मंत्री को बचाने में लगी है? जगेंद्र हत्याकांड मामले में राज्यपाल राम नाईक ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि पत्रकार की हत्या के मामले में सरकारी जांच में ढील ठीक नहीं है. राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं. जगेंद्र के मामले में गहराई से जांच की ज़रूरत है.**

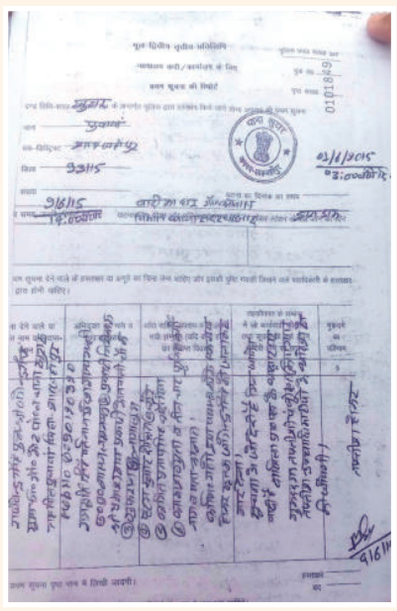

विवादास्पद हो जातीं. सपा सरकार में शासन और प्रशासन, दोनों का अमानवीय पक्ष सुर्खियों में रहा है. आप सबने देखा-सुना कि अखिलेश सरकार के महामूर्धन्य मंत्रियों में शुमार उद्यान मंत्री पारस नाथ यादव पत्रकार जगेंद्र की वीभत्स मौत पर गीता का उपदेश देने की विद्रुत हरकत करने लगे. उन्होंने कहा कि सिर्फ़ ख़बर छपने या आरोप लगने से कोई दोषी नहीं हो जाता. पारस नाथ यादव अपने शीर्ष नेता प्रो. राम गोपाल यादव की नकल में कुछ ज़्यादा ही गल्लेबाजी कर गए. हाल ही में सपा के मुख्य प्रवक्ता बनाए गए वरिष्ठ मंत्री शिवपाल यादव ने भी मीडिया वालों को बुलाकर वही घिसा-पिटा रामगोपाली डायलॉग सुनाया और यह संदेश दिया कि दृष्टिहीन सपा नेतृत्व का एक ही राग है कि उनकी नज़र में राममूर्ति बेदाग है. दूसरी तरफ़ कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और बसपा नेता मायावती ने तो कहा कि आरोपी मंत्री को उसी दिन गिरफ्तार कर लेना चाहिए था.

सपा सरकार मंत्री राममूर्ति वर्मा को बचाने की चाहे जितनी कोशिश करे, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य और मौत से पहले दिया गया जगेंद्र का बयान मंत्री के लिए मुसीबत बनेगा. साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत मृत्यु पूर्व दिया गया बयान क़ानून की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाता है. इसे नकारना मुश्किल होता है. जगेंद्र ने अपने बयान में मंत्री राममूर्ति और पांचों पुलिसवालों को खुद को जलाए जाने का ज़िम्मेदार बताया था. जगेंद्र के बयान वाला वीडियो आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के पास भी सुरक्षित है. विडंबना यह है कि हत्या का आरोपी मंत्री जेल के बजाय सत्ता के शीर्ष गलियारे में विचरण कर रहा है. कभी वह मुख्यमंत्री से मिलता है, तो कभी दूसरे नेताओं से. पिछले 12 जून को राममूर्ति वर्मा, उनके पैरोकार पूर्व सांसद मिथिलेश कुमार एवं पूर्व ज़िलाध्यक्ष प्रदीप यादव ने सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और फिर वे बाकायदा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिले. हत्यारोपी के पैरोकार पूर्व सांसद मिथिलेश तो यहां तक कहते हैं कि नेताजी एवं मुख्यमंत्री ने पूरी जांच करा ली है और उन्हें सच्चाई का पता चल गया है कि मंत्री का कहीं कोई रोल नहीं है. पूर्व सांसद के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि जब मुख्यमंत्री ने अपनी स्व-जांच में राममूर्ति वर्मा को निर्दोष पाया है, तो पत्रकार जगेंद्र के बेटे को दस लाख रुपये का मुआवज़ा और 30 हज़ार रुपये की नौकरी देने का प्रलोभन क्यों दिया गया?

मुलायम सिंह को मंत्री के कारनामे बताने के जुर्म में पार्टी से निकाले गए पूर्व विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि उन्होंने सरकार के आला लोगों से मिलकर पहले ही बता दिया था कि शाहजहांपुर में कुछ गड़बड़ होने वाला है. जगेंद्र सिंह को लगातार मंत्री की ओर से धमकियां दी जा रही थीं. इस बारे में भी सरकार को पता था. पता नहीं क्यों सपा सरकार मंत्री को बचाने में लगी है? जगेंद्र हत्याकांड मामले में राज्यपाल राम नाईक ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि पत्रकार की हत्या के मामले में सरकारी जांच में ढील ठीक नहीं है. राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं. जगेंद्र के मामले में गहराई से जांच की ज़रूरत है. राज्यपाल ने कहा कि वह इस विषय में अखिलेश से दोबारा बात करेंगे. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से पत्रकार जगेंद्र की हत्या के मामले में हुई कार्रवाई की अद्यतन रिपोर्ट मांग ली है. कोर्ट ने भी पूछा है कि इस मामले की क्यों न जांच सीबीआई से कराई जाए? न्यायाधीश एसएन शुक्ला और प्रत्युष कुमार की बेंच ने एनजीओ वी द पीपुल के महासचिव प्रिंस लेनिन की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर यह आदेश दिया. ■

feedback@chauthiduniya.com

## अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला विधायक

रविदास मेहरोत्रा अकेले ऐसे सपा विधायक हैं, जिन्होंने जगेंद्र हत्याकांड पर न केवल आवाज़ उठाई, बल्कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखकर हत्यारोपी मंत्री के ख़िलाफ़ सख्त क़ानूनी कार्रवाई की मांग भी की. रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के अकेले संवेदनशील विधायक के रूप में राजनीतिक पटल पर उभर कर सामने आए हैं. इसके पहले भी जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर रविदास मेहरोत्रा अपना अलग स्टैंड लेते रहे हैं. मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में रविदास ने राममूर्ति वर्मा को मंत्री पद से तत्काल हटाने को कहा. उन्होंने अखिलेश यादव को सलाह दी कि वह पार्टी की गिरती छवि को बचाएं.

## पुलिसवाले निलंबित, मंत्री आज़ाद

पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या का आरोपी मंत्री राममूर्ति वर्मा किसी भी क़ानूनी कार्रवाई से मुक्त है, लेकिन सदर बाज़ार के इंस्पेक्टर श्रीप्रकाश राय समेत पांच पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है. जगेंद्र के बेटे राघवेंद्र ने एफआईआर में जिन तीन-चार अज्ञात पुलिस वालों का जिक्र किया था, उनकी पहचान एसआई क्रांतिवीर सिंह, हेड कॉन्स्टेबल सुभाष चंद्र यादव, कॉन्स्टेबल उदयवीर सिंह और मंसूर के रूप में हुई है. उनके नाम केस डायरी में शामिल कर लिए गए हैं. घटना के बाद लीपापोती के इरादे से सरकार ने इंस्पेक्टर श्रीप्रकाश राय को फौरन झांसी स्थानांतरित कर दिया था, लेकिन दबाव पड़ने पर उसे भी निलंबित किया गया. उन नामजद अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो मंत्री के गुर्गे बताए जाते हैं, जिन्होंने पुलिस के साथ मिलकर पत्रकार को ज़िंदा जलाने का काम किया था. उन नामजद अभियुक्तों में गुफरान, ब्रह्म कुमार दीक्षित उर्फ भूरे, अमित प्रताप सिंह भदौरिया और आकाश गुप्ता शामिल हैं.

## कहां है चश्मदीद महिला?

जगेंद्र के शरीर में आग लगाए जाते वक्त एक महिला भी वहां मौजूद थी. वह महिला पूरे घटनाक्रम की जीवंत चश्मदीद गवाह है, लेकिन उसके बाद से वह लापता है. कुछ स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि उस महिला और जगेंद्र को साथ-साथ फूंकने की साजिश थी, जिससे मामले को दूसरा रंग दे दिया जाता. लेकिन, अफरा-तफरी मच जाने के कारण ऐसा नहीं हो सका और उस समय महिला बच गई. लोग यह भी कहते हैं कि चश्मदीद महिला वही है, जिसने राममूर्ति वर्मा पर बलात्कार का आरोप लगाया था. पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि उस महिला से पूछताछ चल रही है, लेकिन वह उसका अता-पता नहीं बता पाए. घटनाक्रम जानने-समझने वाले लोग उस महिला को भी रास्ते से हटाए जाने का अंदेशा जताते हैं.

## प्रेस काउंसिल ने भेजी जांच टीम!

पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या के मामले में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी एक जांच टीम शाहजहांपुर भेजी. जांच दल में शामिल एसएन सिन्हा, प्रकाश दूबे और सुमन गुप्ता ने बंद कमरे में जगेंद्र के परिवार के लोगों से बातचीत की. संदेहास्पद यह है कि इस दौरान उनके साथ सूचना विभाग के सहायक निदेशक अशोक शर्मा भी मौजूद थे, जो (अभियुक्त को संरक्षण देने वाली) राज्य सरकार के अधिकारी हैं. प्रेस काउंसिल की कथित जांच टीम यह भी जांच कर रही है कि जगेंद्र सिंह पत्रकार थे भी या नहीं. जांच टीम की इस पड़ताल की वजहों की भी गहराई से पड़ताल की आवश्यकता है. बहरहाल, जगेंद्र के परिवार ने साक्ष्य के तौर पर उन दो चैनलों और एक अख़बार के पहचान-पत्र भी जांच टीम को सौंपे, जहां जगेंद्र काम कर चुके थे.

**प्रदर्शन :** दिल्ली के जंतर मंतर पर पत्रकार जगेंद्र की मौत का विरोध प्रदर्शन करते युवा पत्रकार और समाज सेवी. उत्तर प्रदेश सरकार मुर्दाबाद का नारा भी लगा.

व्यापम ?!?

एक तरफ केंद्र सरकार व्हिसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट को ठंडे बस्ते में डाल कर बैठी है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में सुशासन का दावा करने वाली शिवराज सरकार लगातार व्यापमं घोटाले के जाल में उलझती जा रही है. अपने को बचाने की कोशिश में जुटी शिवराज सरकार इसमें मामले को उजागर करने वाले प्रमुख व्हिसिल ब्लोअर्स को पुख्ता सुरक्षा भी मुहैया नहीं करवा पा रही है. इन सभी ने सरकार की नाक में दम कर रखा है. आए दिन इन्हें जान से मारने की धमकियां मिलती रहती हैं. गार्ड की उपस्थिति में इन पर हमले हो जाते हैं, लेकिन सरकार में उनकी सुरक्षा को लेकर कोई आवाज नहीं उठती है.

## व्यापमं घोटाला

# सच के सिपाहियों की जान कौन बचाएगा

व्हिसिल ब्लोअर बिल 2010 में सरकारी धन के दुरुपयोग और सरकारी संस्थाओं में हो रहे घोटालों की जानकारी देने वाले व्यक्ति को व्हिसिल ब्लोअर माना गया है. यानी भ्रष्टाचार केख़िलाफ़ बिगुल बजाने वाला. इस बिल में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को अतिरिक्त अधिकार दिए गए. सीवीसी को दीवानी अदालत जैसी शक्तियां भी देने की बात कही गई. सीवीसी भ्रष्टाचार केख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों केख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई रोक सकता है. भ्रष्टाचार की जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखने की ज़िम्मेदारी सीवीसी की है. अगर पहचान उजागर होती है, तो ऐसे अधिकारियों केख़िलाफ़ शिक़ायत भी की जा सकेगी. इस विधेयक केदायरे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र केकर्मचारी भी शामिल हैं.

नवीन चौहान

डॉ. आनंद राय

प्रशांत पांडेय

आशीष चतुर्वेदी

साल 2005 में जब आरटीआई क़ानून लागू हुआ था, तब से आज तक सैकड़ों आरटीआई कार्यकर्ता अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं. कुल मिलाकर यह कि जो भी भ्रष्टाचार केख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा, उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी. बहरहाल, साल 2010 में यूपीए–2 सरकार भ्रष्टाचार केखिलाफ आवाज उठाने वालों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से एक बिल लेकर आई, जिसे पब्लिक इंटरेस्ट डिसक्लोज़र ऐंड प्रोटेक्शन फॉर पर्सन्स मेकिंग डिसक्लोज़र बिल 2010 नाम दिया गया... संक्षेप में कहें, तो व्हिसिल ब्लोअर बिल 2010.

व्हिसिल ब्लोअर बिल 2010 में सरकारी धन के दुरुपयोग और सरकारी संस्थाओं में हो रहे घोटालों की जानकारी देने वाले व्यक्ति को व्हिसल ब्लोअर माना गया है. यानी भ्रष्टाचार केख़िलाफ़ बिगुल बजाने वाला. इस बिल में केंद्रीय सतर्कता आयोग(सीवीसी) को अतिरिक्त अधिकार दिए गए. सीवीसी को दीवानी अदालत जैसी शक्तियां भी देने की बात कही गई. सीवीसी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई रोक सकता है. भ्रष्टाचार की जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखने की ज़िम्मेदारी सीवीसी की है. अगर पहचान उजागर होती है, तो ऐसे अधिकारियों के ख़िलाफ़ शिक़ायत भी की जा सकेगी. इस विधेयक केदायरे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी भी शामिल हैं. बहरहाल, इस विधेयक में सीवीसी को जितनी ज़िम्मेदारी सौंपी गई, सीवीसी उसे पूरा कर पाने में सफल होगा या नहीं, यह एक सवाल था. जैसे, क्या सीवीसी की सांगठनिक संरचना इतनी बड़ी है, जिससे वह भारत जैसे बड़े देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की समस्या से लड़ पाए? राज्यों, ज़िलों और पंचायतों में फैले भ्रष्ट्राचार से कैसे निबटेगा सीवीसी? यह विधेयक 2011 में ही लोकसभा से पारित हो गया था, लेकिन उच्च सदन से पारित होने में इसे लंबा समय लगा. खैर, यूपीए–2 ने अंतिम समय में जब इस विधेयक को पारित कराने के लिए राज्यसभा में पेश किया, तो भाजपा ने कुछ संशोधन पेश किए थे. यूपीए–2 सरकार ने इन संशोधनों को ज़रूरी बताते हुए स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन उच्च सदन में बहस के दौरान यूपीए ने भाजपा से इस बिल को दोबारा निचले सदन में भेजने का दबाव न बनाने का आग्रह भी किया था. संसद ने इस विधेयक को पारित कर दिया था, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी. राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर 9 मई, 2014 को हस्ताक्षर किए जाने केबावजूद सरकार ने अब तक इसे क़ानून केतौर पर लागू नहीं किया है.

हालांकि सत्ता में आने केएक साल बाद मोदी सरकार इस कानून को लागू करने केबजाय इसमें संशोधन करना चाहती है. कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार बताने वाली भाजपा ने एक साल होने के बाद भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सुरक्षा देने के मामले में गंभीर नहीं दिखाई दे रही है. सालों से मांग उठ रही थी कि भ्रष्टाचार केखिलाफ आवाज बुलंद करने वालों का नाम गुप्त रखने और उन्हें सुरक्षा देने के लिए कानून लाया जाए, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार इसमें संशोधन कर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को व्हिसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्टशन एक्ट के दायरे से बाहर रखने जा रही है.

एक तरफ केंद्र सरकार व्हिसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट को ठंडे बस्ते में डाल कर बैठी है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में सुशासन का दावा करने वाली शिवराज सरकार लगातार व्यापमं घोटाले के जाल में उलझती जा रही है. अपने को बचाने की कोशिश में जुटी शिवराज सरकार इसमें मामले को उजागर करने वाले प्रमुख व्हिसिल ब्लोअर्स को पुख्ता सुरक्षा भी मुहैया नहीं करवा पा रही है. इन सभी ने सरकार की नाक में दम कर रखा है. आए दिन इन्हें जान से मारने की धमकियां मिलती रहती हैं. गार्ड की उपस्थिति में इन पर हमले हो जाते हैं, लेकिन सरकार में उनकी सुरक्षा को लेकर कोई आवाज नहीं उठती है. जून के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश विधानसभा केनेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे ने भी व्यापमं मामले के व्हिसिल ब्लोअर्स को पुख्ता सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है. व्यापमं घोटाला अपने आप में एक अनोखा घोटाला बन गया है. साल 2012 से लेकर अब तक इस घोटाले से जुड़े 40 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं. इस मामले में तीन प्रमुख व्हिस्ल ब्लोअर हैं आशीष चतुर्वेदी, डॉ. आनंद राय और प्रशांत पांडेय. तीनों को कोर्ट के आदेश पर सुरक्षा दी गई है, लेकिन तीनों में से कोई भी मिल रही सुरक्षा से संतुष्ट नहीं है. इंदौर में रहने वाले व्हिसिल ब्लोअर डॉ आनंद राय का कहना है कि सरकार ने जो बिल बनाया है, वह सड़ा हुआ है. एक तो मुद्दतों बाद यह बिल पास भी हो गया, उसे राष्ट्रपति की सहमति भी मिल गई, लेकिन एक सड़े हुए कानून को भी सरकार लागू करने में हिचकिचा रही है. कानून व्यवस्था राज्य के हाथों में होती है. इस कानून के लागू होने के बाद नियम तो राज्य सरकारों को बनाने हैं. ऐसे भी जो प्रावधान अभी हैं, उस हिसाब से सीवीसी अथॉरिटी होगा. राज्यों में व्हिसिल ब्लोअर्स को इस एक्ट से कुछ फायदा नहीं होने वाला है. पहचान छुपाने के प्रावधान का भी हम जैसे लोगों को कोई फायदा नहीं है. हम जैसे लोग सीना ठोंककर कहते हैं कि हमने इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है, लेकिन इस क़ानून के भरोसे व्हिसिल ब्लोअर्स को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, यह केवल नाम के लिए है. इस एक्ट से व्हिसिल ब्लोअर्स को किसी तरह की सुपर पावर नहीं मिलने जा रही है. आप सोचिये उस कानून से आम आदमी को क्या फायदा होगा, जब हम जैसे लोगों को राहत और फायदा महसूस नहीं हो पा रहा है. इतने बड़े मामले को उजागर करने के बाद भी हमें अपनी सुरक्षा के लिए कोर्ट से गुहार लगानी पड़ी, क्योंकि प्रदेश के पुलिस रेगुलेशन नियमों में व्हिसिल ब्लोअर को सुरक्षा मुहैया कराने का कोई प्रावधान नहीं है. डॉ. आनंद बताते हैं कि मैंने मार्च 2014 में हाइकोर्ट से सुरक्षा मांगी, कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने राज्य सुरक्षा परिषद के पास प्रस्ताव भेजा और तब मेरी सुरक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इस एक्ट को लागू करने से पहले पुलिस रेगुलेशन को सुधारने की जरूरत है. पूर्व सासंदों, पूर्व विधायकों को सुरक्षा देने का प्रावधान है, लेकिन व्हिसिल ब्लोअर को सुरक्षा देने का कोई प्रावधान नहीं है. सुरक्षा का दायित्व राज्यों का है. हमें अभी जो सुरक्षा मिली हुई है वह भी खिलवाड़ की तरह है. जो सुरक्षा गार्ड मेरे घर में तैनात किया गया है, वह सुबह 11 बजे आता है और शाम 7 बजे चला जाता है. इसके बाद हमारी सुरक्षा का भगवान ही मालिक है. सबसे पहले जब मुझे सुरक्षा दी गई तो पुलिस प्रशासन ने इसकेएवज में मुझसे 60 हजार रुपये लिए. इसकेबाद मैंने कोर्ट में कहा कि मेरी तनख्वाह 40 हजार रुपये है, मैं हर महीने सुरक्षा के एवज में 60 हजार रुपये नहीं दे सकता. अगर सरकार को लगता है कि मुझे सुरक्षा दी जानी चाहिए तो दीजिए, नहीं तो वापस ले लीजिए.

ग्वालियर के 25 वर्षीय छात्र आशीष चतुर्वेदी व्यापमं मामले के प्रमुख व्हिसिल ब्लोअर हैं. उनपर अब तक 14 बार जानलेवा हमले हो चुकेहैं. इस संबंध में छह बार एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है. कैंसर से जूझती अपनी मां के इलाज के दौरान ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में फर्जी डॉक्टरों के संपर्क में आने के बाद आशीष मामले की तह में चले गए. उन्होंने धीर–धीरे करके फर्जीवाड़ा करने वालों के साथ संबंध बनाने शुरू किए और इस संबंध में जानकारियां जुटानी शुरू किया. उन्हें धीरे–धीरे कई अहम सुराग मिलते चले गए. इसके बाद उन्होंने सूचना के अधिकार के जरिये जानकारी जुटानी शुरू की. आज वह इस मामले केसबसे अहम गवाहों में से एक हैं. उनके कई खुलासों केकारण व्यापमं घोटाले केकई बड़े आरोपी जेल में हैं. आशीष का मानना है कि व्हिसिल ब्लोअर्स एक्ट केलागू होने से भ्रष्टाचार केखिलाफ आवाज उठाने वालों को कानूनन सुरक्षा मिलने लगेगी. पुलिस और राज्य सरकार सुरक्षा देने के बाद कानूनन जवाबदेह भी हो जाएंगी. साथ ही व्हिसिल ब्लोअर्स को सुरक्षा देने की बाध्यता भी हो जाएगी. अभी एसआईटी के आदेश पर मुझे 24 घंटे (राउंड द क्लॉक) सुरक्षा देने की बात है, लेकिन दिन भर में केवल 8–10 घंटे ही मुझे सुरक्षा मिल पाती है. ऊपर से वीआईपी सिक्योरिटी में तैनात रहने वाले सुरक्षा गार्ड मेरी सुरक्षा में लापरवाही बरतते हैं, भेदभाव और अभद्रता करते हैं. 40 वर्ष से ज्यादा उम्र केसुरक्षा गार्ड तैनात करने का प्रावधान है, लेकिन मेरी सुरक्षा में पचास वर्ष से ज्यादा केलोगों को ही अब तक तैनात किया गया है. सरकार और पुलिस महकमा मुझे जानबूझ कर परेशान कर रहा है. वर्तमान में हरिनारायणचारी मिश्रा ग्वालियर के एसपी हैं. मेरी सुरक्षा में लापरवाही में वे व्यक्तिगत तौर पर रुचि ले रहे हैं. कोर्ट में अगली सुनवाई केदौरान मैं कोर्ट से आग्रह करूंगा कि मुझे सही तरीके से सुरक्षा दी जाये या फिर इसे पूरी तरह हटा लिया जाए. इंदौर के प्रशांत पांडेय डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं. उन्होंने इस मामले से संबंधित कई अहम दस्तावेज जुटाने में एसटीएफ की मदद की थी. इंदौर वे कई मामलों को सुलझाने में इंदौर पुलिस, आईबी और रॉ की मदद कर चुकेहैं. एसटीएफ के लिए भी उन्होंने करीब एक साल तक काम किया था. अब वे एसटीएफ से अलग हो गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस उन्हें धमकी दे रही है कि मामले से जुड़ी संवेदनशील जानकारी वह किसी केसाथ साझा न करें. उन्होंने कुछ महीने पहले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह को घोटाले से जुड़े कथित असली नामों वाली एक्सेल शीट उपलब्ध करवाई थी, जिसे लेकर कांग्रेस केनेताओं ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और शिवराज सिंह पर इस शीट में स्वयं केनाम को बदलने का आरोप लगाया था. प्रशांत का कहना है कि इस घोटाले की अब तक पांच फीसद गड़बड़ियों का ही खुलासा हुआ है. उन्हें कोर्ट के आदेश पर सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन वह भी केवल नाम केलिए है. शाम 6 बजे केबाद से सुबह तक आपकेसाथ कुछ भी हो सकता है. सरकार का रवैया लापरवाही भरा है. सरकार सुरक्षा में लापरवाही करके व्हिसिल ब्लोअर्स को दबाव में लाना चाहती है, ताकि इस मामले की तह तक जांच एजेंसियां न जा सकें. व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आने से सरकार सुरक्षा देने के लिए बाध्य हो जाएगी. पहले की तरह उनपर दबाव नहीं डाला जा सकेगा और मनमाने तरीके से उनकी सुरक्षा वापस नहीं ली जा सकेगी. कुछ हद तक इस एक्ट केआने से फायदा मिलेगा. जो लोग नहीं चाहते हैं कि व्हिसिल ब्लोअर्स अपना काम नहीं कर सकें. मानसिक तौर पर उनपर इस कानून केआने से प्रभाव पड़ेगा. उन्हें इस बात का कहीं न कहीं डर रहेगा कि हमें कानूनन सुरक्षा मिली हुई है. अभी तक व्हिसिल ब्लोअर्स को सिस्टम के द्वारा ही झूठे मुकदमे लगाकर या अन्य तरीकों से खत्म कर दिया जाता था. जनता केसामने और कुछ कहानी रख दी जाती थी, लेकिन अब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला इस कानून के अंतर्गत सुरक्षा की मांग कर सकता है.

कुल मिलाकर गेंद राज्य सरकारों केपाले में ही रहेगी. जब तक वे व्हिसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन के लिए प्रावधान नहीं करेंगे, तब तक इस कानून का कोई लाभ नहीं होने वाला है. राज्य व्हिसिल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए सुरक्षा बल की कमी का रोना रोते हैं, जबकि नेताओं को सुरक्षा देने के लिए उनकेपास पर्याप्त सुरक्षा कर्मी हैं, लेकिन जब बात आम आदमी और भ्रष्टाचार का खुलासा करने वालों की आती है, तो सरकारें कन्नी काटने लगती हैं.■

navinonline2003@gmail.com

इन दिनों केदारपुरी में भवन स्वामियों द्वारा अपने सुरक्षित भवनों से मलबा हटाया जा रहा है. साथ ही भवनों तक आने–जाने के लिए पैदल रास्ते का निर्माण किया जा रहा है. उसी खुदाई के दौरान उक्त नरकंकाल बरामद हो रहे हैं. पूर्व में भी केदारपुरी में नरकंकाल बरामद हुए थे, जिसे देखते हुए पुलिस–प्रशासन ने केदारपुरी में दो दिनों तक सर्च अभियान चलाया था. केदारपुरी स्थित बॉम्बे हाउस के निकट मलबा साफ़ करते समय हाथ के पंजे, पैर एवं पसली की हड्डियां पाई गईं, जिनका दाह संस्कार कर दिया गया.

झारखंड

# हादसे को दावत देती जारंगडीह कोलियरी

**सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड (सीसीएल) की कथारा स्थित जारंगडीह कोलियरी के अधीन दो खदानें हैं, एक भूमिगत (अंडर ग्राउंड), जो काफी नुक़सान में चल रही है और दूसरी खुली (ओपेन कास्ट), जिसमें काफी वर्षों से कोयले का खनन-उत्पादन किया जा रहा है. भूमिगत और खुली खदानों में खनन-उत्पादन और रखरखाव की ज़िम्मेदारी परियोजना पदाधिकारी (प्रोजेक्ट ऑफिसर) की होती है.**

दिलीप कुमार शर्मा

कोल इंडिया लिमिटेड के सहायक उपक्रम सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड (सीसीएल) की कथारा एरिया स्थित जारंगडीह कोलियरी (ओपन कास्ट कोल माइंस) में चौबीसों घंटे बड़े वाहनों के आवागमन और सड़क मार्ग संकरा होने की वजह से किसी भी समय कोई भयंकर दुर्घटना हो सकती है. इस आशंका ने खदान में काम करने वाले कर्मचारियों के परिवार काफी चिंतित कर रखा है. कर्मचारी जब अपने घर लौट नहीं आते, तब तक उनके परिवारीजन चैन से बैठ नहीं पाते हैं. ग़ौरतलब है कि सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड (सीसीएल) की कथारा स्थित जारंगडीह कोलियरी के अधीन दो खदानें हैं, एक भूमिगत (अंडर ग्राउंड), जो काफी नुक़सान में चल रही है और दूसरी खुली (ओपेन कास्ट), जिसमें काफी वर्षों से कोयले का खनन–उत्पादन किया जा रहा है. भूमिगत और खुली खदानों में खनन–उत्पादन और रखरखाव की ज़िम्मेदारी परियोजना पदाधिकारी (प्रोजेक्ट ऑफिसर) की होती है. खदान के सारे अधिकारी–कर्मचारी परियोजना पदाधिकारी के निर्देशन में अपने काम को अंजाम देते हैं. परियोजना पदाधिकारी जनरल मैनेजर के प्रति जवाबदेह होता है, जिसके कंधे पर पूरे एरिया की ज़िम्मेदारी होती है.

जारंगडीह खुली खदान से पिछले कई वर्षों से रोड सेल (लोकल सेल) का काम भी किया जा रहा है, जिससे कोयले की उठान (ट्रांसपोटेशन) के लिए भारी वाहनों की भरमार रहती है. रोड सेल के उक्त वाहनों के अलावा कोलियरी के अपने वाहनों जैसे डोजर लोडर, होल्पैक डंफर, जो सिर्फ़ खदान के ट्रांसपोटेशन के लिए होते हैं, की एक बड़ी संख्या है. उक्त सारे वाहन जिस संकरी सड़क पर चलते हैं, उसके दोनों तरफ़ गहरी खाई (माइंस) है. इस मार्ग पर ख़तरनाक तस्वीर तब देखते बनती है, जब एक तरफ़ से कोई बड़ा वाहन आता है और दूसरी तरफ़ कोई बड़ा वाहन उसे रास्ता देने के लिए किनारे खड़ा कर दिया जाता है. अगर गुज़रने वाले वाहन के चालक से थोड़ी भी चूक हो जाए, तो दोनों वाहन पलक झपकते हज़ारों फुट गहरी खाई के अंदर. एक वाहन में चालक को कम से कम तीन लोग होते हैं, जिनकी मौत तय समझिए. सीसीएल को जो करोड़ों का नुक़सान होगा, सो अलग. जारंगडीह कोलियरी के कर्मचारी इस स्थिति से पिछले कई वर्षों से जूझ रहे हैं. यह ख़तरा पिछले वर्ष से तब और भी बढ़ गया, जब जारंगडीह खुली खदान में एक इलाकाई निजी कंपनी बीकेबी द्वारा आउटसोर्सिंग का काम शुरू किया गया. बीकेबी को खदान के अंदर मौजूद कोयले पर पत्थर और मिट्टी उठाने का काम दिया गया है. इस निजी कंपनी के वाहनों की संख्या अच्छी–खासी है और वे भी उसी संकरी सड़क से आते–जाते हैं. कोलियरी में चौबीसों घंटे यानी तीन शिफ्टों में काम होता है. रोड सेल, कोलियरी और बीकेबी के वाहनों के लगातार आवागमन के चलते कर्मचारियों को हर समय अपनी जान को खतरा महसूस होता रहता है. पिछले दिनों इसी सड़क पर बीकेबी का एक डंफर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. हालांकि कोई बड़ा नुक़सान नहीं हुआ, फिर भी कोलियरी कर्मचारियों ने कामकाज ठप्प कर दिया था. इस पर कोलियरी की सभी ट्रेड यूनियनों के नेताओं–कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें कहा गया कि उक्त सड़क मार्ग यथाशीघ्र चौड़ा किया जाएगा. इसके अलावा सुरक्षा के अन्य इंतजाम भी किए जाएंगे. समझौते के वक्त आरसीएमएस के एरिया सेक्रेटरी वरुण सिंह, बेरमो प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद सिंह, कोल फील्ड मज़दूर यूनियन के नेता इरफान और कोलियरी के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. उसके बाद कर्मचारियों ने अपना काम शुरू कर दिया था.

समझौता तो हो गया, लेकिन आज तक सड़क मार्ग चौड़ा करने का काम शुरू नहीं हुआ है. कोलियरी प्रबंध तंत्र चुप्पी साधे बैठा है, जिससे कर्मचारियों में फिर से रोष बढ़ता जा रहा है. ट्रेड यूनियन के नेताओं का कहना है कि प्रबंध तंत्र जान–बूझकर हादसे को दावत दे रहा है. यदि उक्त सड़क मार्ग शीघ्र ही चौड़ा न किया गया, तो कर्मचारियों को मजबूरन कामकाम ठप्प करना पड़ेगा. इस बीच अगर कोई दुर्घटना हो गई, तो उसके लिए प्रबंध तंत्र ही ज़िम्मेदार होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तरा खंड

# अब नरकंकालों पर राजनीति

राजकुमार शर्मा

केदार नाथ धाम आपदा की दूसरी बरसी पर दो राष्ट्रीय दलों यानी भाजपा और कांग्रेस के बीच लाशों पर राजनीति करने की होड़–सी मची है. बरसी से पहले हरिद्वार के सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने केदार धाम पहुंच कर क्षेत्र में लाशें होने की जो चिंगारी छोड़ी, वह अब शोला बन गई है. अब इसकी आंच सूबे की हरीश रावत सरकार पर आनी तय मानी जा रही है. आपदा राहत कार्यों में घोटाले का आरोप लगते ही हरीश रावत सरकार घिरी नज़र आने लगी, उनके राजनीतिक महारथी भी उनके बचाव में शब्द बाणों की बौछार करने में जुट गए. ऐसे में जो संदेश जा रहा है, वह हरीश सरकार ख़तरे की घंटी साबित हो सकता है. निशंक के ताल ठोंकने से पूरी हरीश रावत सरकार सवालों के घेरे में आ गई है. जल–प्रलय के दो साल बाद भी केदार नाथ धाम में नरकंकालों के मिलने का सिलसिला जारी है. पिछले दिनों उदक कुंड के निकट सफाई के दौरान दो नरकंकाल मिले. पुलिस ने डीएनएन सैंपल लेने के बाद उनका दाह संस्कार करा दिया. उदक कुंड केदार नाथ मंदिर से 50 मीटर दूर है.

उल्लेखनीय है कि केदार घाटी में 16–17 जून, 2013 को आई भीषण आपदा में बड़ी संख्या में लोग लापता हुए थे और मारे गए थे. नरकंकालों के रूप में अब तक लापता लोगों के शव मिलने पर सवाल उठाए जा रहे हैं. खासकर, विपक्ष इस मसले पर सरकार को घेर रहा है. निशंक ने केदार नाथ में दो और नरकंकाल बरामद होने के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत से नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफ़ा देने की मांग की है. निशंक ने कहा कि कुछ दिनों पूर्व जब उन्होंने केदार नाथ में नरकंकाल होने की आशंका जताई थी, तो प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने उन्हें झुठलाते हुए उन पर ग़लत बयानबाजी करने का आरोप मढ़ दिया था, लेकिन अब केदार नाथ में दो और नरकंकारल मिलने के बाद उनकी आशंका सच साबित हुई है. सांसद निशंक ने कहा कि सरकार द्वारा झूठा बताने पर उन्होंने मुख्यमंत्री को सीधी चुनौती दी थी कि केदार नाथ में यदि नरकंकाल न मिले, तो वह संसद की सदस्यता से इस्तीफ़ा दे देंगे. अब जब केदार नाथ में फिर दो नरकंकाल बरामद हुए हैं, तो मुख्यमंत्री को सरकार समेत न सिर्फ़ इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, बल्कि देश की जनता से सार्वजनिक तौर पर माफ़ी भी मांगनी चाहिए.

ग़ौरतलब है कि इन दिनों केदारपुरी में भवन स्वामियों द्वारा अपने सुरक्षित भवनों से मलबा हटाया जा रहा है. साथ ही भवनों तक आने–जाने के लिए पैदल रास्ते का निर्माण किया जा रहा है. उसी खुदाई के दौरान उक्त नरकंकाल बरामद हो रहे हैं. पूर्व में भी केदारपुरी में नरकंकाल बरामद हुए थे, जिसे देखते हुए पुलिस–प्रशासन ने केदारपुरी में दो दिनों तक सर्च अभियान चलाया था. केदारपुरी स्थित बॉम्बे हाउस के निकट मलबा साफ़ करते समय हाथ के पंजे, पैर एवं पसली की हड्डियां पाई गईं, जिनका दाह संस्कार कर दिया गया. सरकार क्षेत्र को पावन बनाने एवं दुरुस्त करने के लिए अब तक करोड़ों रुपये खर्च कर चुकी है. चारधाम यात्रा भी गति पकड़ रही है. ऐसे में दिग्गज कांग्रेसियों को लगता है कि निशंक के माध्यम से भाजपा लाशों यानी नरकंकालों की राजनीति करके माहौल खराब कर रही है और इसके पीछे अमित शाह की दूषित मानसिकता काम कर रही है. कांग्रेस नेताओं का मानना है कि चारधाम यात्रा अच्छे मौसम के चलते और सरकारी सुविधाओं के अभाव के बावजूद सफल दिख रही है. दुर्गम और पथरीले रास्ते की परवाह किए बगैर यात्रियों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है. निशंक को इसलिए केदार नाथ की यात्रा पर भेजा गया, ताकि यात्रा नाकाम की जा सके.

**इन दिनों केदारपुरी में भवन स्वामियों द्वारा अपने सुरक्षित भवनों से मलबा हटाया जा रहा है. साथ ही भवनों तक आने-जाने के लिए पैदल रास्ते का निर्माण किया जा रहा है. उसी खुदाई के दौरान उक्त नरकंकाल बरामद हो रहे हैं. पूर्व में भी केदारपुरी में नरकंकाल बरामद हुए थे, जिसे देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने केदारपुरी में दो दिनों तक सर्च अभियान चलाया था**

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि निशंक से पहले केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी केदार नाथ गई थीं, लेकिन उन्हें इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली, न उन्हें लाशों की बदबू आई. केवल निशंक की नाक क्यों फूल रही है? योग गुरु रामदेव भी आपदा के एक वर्ष बाद ही संत समाज के साथ केदार धाम की यात्रा कर चुके हैं, तब उन्हें सब कुछ ठीक नज़र आया था. बाबा ने लौट कर हरीश सरकार की सराहना भी की थी. कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी तो पैदल जाकर बाबा केदार के दर्शन करके ऑल इज वेल का प्रमाण–पत्र जारी कर चुके हैं. जानकारों का कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार तंज कसने वाले हरीश राव पर ब्रेक लगाने और उनकी उपलब्धियों पर पर्दा डालने के लिए ऐसी बयानबाजी जान–बूझकर की जा रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com


कमल मोरारका

# सरकार को नई सोच अपनाने की ज़रूरत है

नरेंद्र मोदी ने 282 जैसी संख्या के साथ बड़ा बहुमत हासिल किया है, जैसे 1971 में इंदिरा गांधी ने हासिल किया था. लेकिन, यहां एक बड़ा अंतर यह है कि इंदिरा गांधी अपनी नीतियों को लेकर स्पष्ट थीं या कम से कम उनके आसपास के लोग नीतियों को लेकर स्पष्ट थे. श्री मोदी के साथ ऐसा नहीं है. वह ज़्यादातर नौकरशाहों पर निर्भर रहते हैं और फिर उनके पास ऐसे एक्सपर्ट नौकरशाह भी नहीं हैं, जैसे इंदिरा गांधी के पास पीएन हक्सर जैसे नौकरशाह थे. यहां गुजरात के कुछ नौकरशाह लाए गए हैं, जो उनकी तरफ़ से काम कर रहे हैं. लोकतंत्र के लिए यह ख़तरनाक है. आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए, जो आपको बेहतर सुझाव दे सकें. बाद में जब इंदिरा गांधी कुछ ऐसा करना चाहती थीं, जो पीएन हक्सर के मुताबिक उचित नहीं था, तब हक्सर उनसे अलग हो गए. इसके बाद इंदिरा गांधी की हार हुई. 1980 में हालांकि वह विपक्ष की ग़लतियों की वजह से फिर सत्ता में आईं.

बिहार चुनाव अब नज़दीक हैं. अब यह बिल्कुल साफ़ हो गया है कि जदयू और राजद एक गठबंधन के रूप में कांग्रेस और दूसरी ग़ैर-भाजपा पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे. भाजपा ने जीतन राम मांझी को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया है, इसलिए लड़ाई की रूपरेखा अब साफ़ हो चुकी है. भाजपा में जो कमजोरी नज़र आ रही है, वह है मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चेहरा. उसके नेता सुशील मोदी के पास न तो जातीय आधार है और न ही वह कोई प्रेरणादायक व्यक्तित्व के मालिक हैं. हां, यह ज़रूर है कि नीतीश के डिप्टी के तौर पर उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन वह चुनावी जंग के लिए पर्याप्त नहीं होगा. यह भाजपा की कमजोरी है. जहां तक जदयू-राजद की चुनावी रणनीति का सवाल है, तो वह सही दिशा में जा रही है. अब मतदाताओं को फ़ैसला करना है कि उन्हें किस तरफ़ जाना है. इस पर कोई विवाद नहीं है कि नीतीश कुमार का प्रदर्शन शानदार रहा है. यहां तक नीतीश से गठबंधन टूटने से पहले भाजपा भी उस प्रदर्शन पर गर्व करती थी. बेशक, अब सुशील मोदी उनके बारे में तरह-तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन वह जनता के दिमाग से नीतीश के कामों को निकाल नहीं सकते. बिहार में अक्टूबर में चुनाव होने की संभावना है, इसलिए अब समय बहुत कम है. दोनों पक्ष सही रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे. बिहार को एक स्थिर और अच्छी सरकार की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी अपनी समस्याएं हैं. ग़रीबी स्तर ऊंचा है, वहां की कृषि आत्मनिर्भर नहीं है. इसलिए उसे सभी प्रकार की मदद की ज़रूरत है.

इस बार दूसरे मुद्दे के दरअसल दो पहलू हैं. पहला यह कि आडवाणी जी ने आपातकाल की 40वीं वर्षगांठ पर एक बयान दिया कि वह निश्चिंत नहीं हैं कि आपातकाल दोबारा नहीं लगेगा. दरअसल, उन्होंने कहा कि जो ताक़तें लोकतंत्र विरोधी हैं, वही लोकतांत्रिक ताक़तों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जो आपातकाल लागू करने की स्थितियां बनाता है. यह एक स्वयंसिद्ध बयान है, जो मोदी सरकार के ऊपर हमला नहीं है, जैसा कि कांग्रेस इससे नतीजा निकलने की कोशिश कर रही है. लेकिन, इसमें तथ्य यह है कि एक साल से अधिक समय से सत्ता में रहते हुए ऐसे संकेत नहीं मिले हैं कि लोकतंत्र को मजबूती मिली हो. सबसे पहली बात यह कि यहां गोपनीयता बरती जा रही है. लोकतंत्र और गोपनीयता एक साथ नहीं चल सकते. चीज़ों पर जितनी अधिक खुली चर्चा होगी, लोकतंत्र के लिए उतना ही अच्छा होगा. उच्चस्तरीय पदों जैसे सीबीआई के निदेशक, सीवीसी, सूचना आयुक्त की नियुक्तियों को कौन कहे, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रमुख जैसी नियुक्तियों की जानकारी भी बहुत कम या अप्रत्यक्ष रूप से बाहर आ रही है. वित्त मंत्री ने खुद अपनी नीति न बताकर इस स्थिति को और अधिक अस्पष्ट कर दिया. हमें मालूम है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हालत ठीक नहीं है, लेकिन इन बैंकों की अपनी एक प्रणाली मौजूद थी. अब आप यह कह रहे हैं कि इसमें बाहर से बेहतरीन लोगों को लाएंगे. लेकिन, बाहर से मतलब कहां से? क्या हम यह सोच रहे हैं कि निजी क्षेत्र के बैंकर्स सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामूली वेतन पर काम करना पसंद करेंगे? यह मुमकिन नहीं है. या आप उन्हें निजी क्षेत्र के बैंकों के बराबर वेतन देने जा रहे हैं? यह भी मुमकिन नहीं है. असल समस्या यह है कि हमारे पास कोई वैकल्पिक मॉडल ही नहीं है.

अब योजना आयोग की बात करते हैं. यह अच्छी बात है कि सरकार कहती है कि हमने योजना आयोग ख़त्म कर दिया. लेकिन, यह नीति आयोग क्या है? इसने अब तक क्या किया? किसी को मालूम नहीं है. यहां तक कि नीति आयोग के सदस्यों को भी यह नहीं पता कि उनके काम क्या हैं? नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगढ़िया देश के लिए बहुत कुछ करने की उम्मीद के साथ अमेरिका से आए थे. लेकिन जिस तरह से उन्हें अपमानित किया जा रहा है, मुझे ताज्जुब है कि अब तक उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया और वापस अमेरिका क्यों नहीं चले गए? एक तो उन्हें कैबिनेट रैंक नहीं दिया गया, जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष को दिया जाता था. यहां तक कि उन्हें राज्य मंत्री तक का दर्जा देने में भी दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है. सरकार उन्हें कैबिनेट सेक्रेटरी का दर्जा देना चाह रही है, जो इस स्तर के व्यक्ति के लिए अपमान से कम नहीं है. हालांकि, अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है. अभी भी इस पर मंथन जारी है. हमने नीति आयोग बना लिया है, लोग नियुक्त कर दिए हैं, लेकिन उन्हें करना क्या है, मालूम नहीं. सीवीसी की नियुक्ति एक देर से उठाया गया क़दम है. पार्टी के भीतर ही राम जेठमलानी, सुब्रह्मण्यम स्वामी इस सबसे खुश नहीं हैं. आरएसएस क्या सोच रहा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ख़बरें आ रही हैं कि वह भी कई बातों से नाखुश है. यह नरेंद्र मोदी के एक अच्छे प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में बड़ी रुकावट है.

नरेंद्र मोदी ने 282 जैसी संख्या के साथ बड़ा बहुमत हासिल किया है, जैसे 1971 में इंदिरा गांधी ने हासिल किया था. लेकिन, यहां एक बड़ा अंतर यह है कि इंदिरा गांधी अपनी नीतियों को लेकर स्पष्ट थीं या कम से कम उनके आसपास के लोग नीतियों को लेकर स्पष्ट थे. श्री मोदी के साथ ऐसा नहीं है. वह ज़्यादातर नौकरशाहों पर निर्भर रहते हैं और फिर उनके पास ऐसे एक्सपर्ट नौकरशाह भी नहीं हैं, जैसे इंदिरा गांधी के पास पीएन हक्सर जैसे नौकरशाह थे. यहां गुजरात के कुछ नौकरशाह लाए गए हैं, जो उनकी तरफ़ से काम कर रहे हैं. लोकतंत्र के लिए यह ख़तरनाक है. आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए, जो आपको बेहतर सुझाव दे सकें. बाद में जब इंदिरा गांधी कुछ ऐसा करना चाहती थीं, जो पीएन हक्सर के मुताबिक उचित नहीं था, तब हक्सर उनसे अलग हो गए. इसके बाद इंदिरा गांधी की हार हुई. 1980 में हालांकि वह विपक्ष की ग़लतियों की वजह से फिर सत्ता में आईं. मोदी को आडवाणी की इस अपेक्षाकृत नरम टिप्पणी से सीख लेनी चाहिए कि हालात ऐसे न बनाए जाएं, जिनसे लोकतंत्र की गरिमा को चोट पहुंचे.

पहलाज निहलानी सेंसर बोर्ड के चेयरमैन बने हैं. चेयरमैन ज़रूरी नहीं कि खुद हर एक फिल्म को देखे, लेकिन यहां भी विवाद शुरू हो गया है. फिल्म निर्माता कुछ नए मोरल कोड को लेकर शिकायत करने जा रहे हैं. हर पांच साल में सरकार बदलती है, न कि देश और क़ानून. क़ानून या संविधान की आधारभूत संरचना नहीं बदलती. यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, चाहे अमेरिका में हो या ब्रिटेन में या भारत में. लोकतंत्र की अच्छाई यह है कि सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन बुनियादी ढांचा नहीं बदलता. सेंसर बोर्ड को एक महत्वपूर्ण संस्था कैसे बनाया जा सकता है? एक मुक्त समाज में लोग अच्छी-बुरी या बहुत बुरी फिल्में बना सकते हैं. आपका काम सर्टिफिकेट जारी करना है. बोर्ड यूनिवर्सल या यू/ए या एडल्ट सर्टिफिकेट दे. आप किसी चीज पर फ़ैसला देने की कोशिश क्यों करते हैं? यह सब एक परिपक्व सरकार के लिए सही नहीं है.

पिछले दिनों सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे को लेकर सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी. जिन लोगों को इस मामले की जानकारी है, वे जानते हैं कि ललित मोदी ने क्या किया है? उनका बीसीसीआई के लिए क्या योगदान रहा है और उन्होंने बीसीसीआई और खुद को कितना नुक़सान पहुंचाया, सब जानते हैं. आख़िर एक जाने-माने औद्योगिक परिवार से आने वाले एक आदमी को लंदन में इतनी शर्मिंदगी क्यों उठानी पड़ रही है? ललित मोदी प्रवर्तन निदेशालय से नहीं भाग रहे हैं और न फेरा या फेमा से छिपते फिर रहे हैं. भारत में आप किसी को टार्चर नहीं कर सकते. आज अगर मुंबई पुलिस यह कहती है कि दाऊद इब्राहिम ललित मोदी से कोई हिसाब चुकता करना चाहते हैं, तो सरकार में, खासकर आईबी और रॉ को इसकी सारी जानकारी होगी. अगर आप ललित मोदी को मानवीय आधार पर कोई छूट देते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? उन्हें 15 दिनों के लिए पत्नी के साथ जाने की अनुमति दें, लेकिन यह सब पारदर्शी तरीके से होना चाहिए था. ललित मोदी को भारतीय उच्चायुक्त के यहां आवेदन करना चाहिए था, जिस पर उन्हें पुर्तगाल जाने की अनुमति मिलती और अगर वह वहां से फरार भी हो जाते, तो वापस लाया जा सकता था. लेकिन, जिस तरीके से यहां काम हुआ, उससे आपने खुद की आलोचना को निमंत्रण दे दिया. वसुंधरा और ललित मोदी का संबंध 30-35 साल पुराना है. हर किसी को मालूम है. अपने पहले मुख्यमंत्रित्व काल में वसुंधरा राजे ने खुले तौर पर ललित मोदी के लिए लैंड यूज चेंज में मदद की, जिसकी राजस्थान में सख्त आलोचना हुई. राजस्थान में इस सबके बारे में सबको पता है.

अब यह भी पता चल रहा है कि मॉरिशस रूट से पैसा वसुंधरा राजे के बेटे की कंपनी में निवेश किया गया है. यह सब वरिष्ठ राजनेताओं के लिए सही नहीं है. वसुंधरा राजे एक बार फिर पांच साल के लिए मुख्यमंत्री बनी हैं. वह ऐसे कामों में उलझने के बजाय राजस्थान को आगे ले जा सकती हैं. वह चंद्र बाबू नायडू की तरह राजस्थान में भी आईटी सिटी बना सकती हैं. राजस्थान में यह सेक्टर काफी फल-फूल सकता है. मुझे लगता है कि भाजपा को एक बेहतर प्रबंधन की ज़रूरत है. उसका प्रबंधन बिखर रहा है. प्रधानमंत्री खुद तो ठीक हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग उस क्षमता के नहीं हैं. पार्टी के मुख्यमंत्री भी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसा उन्हें करना चाहिए. मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मानकों के मुताबिक अच्छा काम कर रहे हैं. उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा आलोचना नहीं है. लेकिन, पूरे तौर पर नई सोच को लाने की ज़रूरत है, नए प्रतिमान गढ़ने की ज़रूरत है, अन्यथा सरकार पुराने ढर्रे पर ही चलती रहेगी. उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतर होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

## कुख्यात डाकू मुस्तकीम कैसे मारा गया-4

# आठ ने मिलकर मारे दो

फरवरी, 1979 में मुस्तकीम की ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया. चतेला गांव के रहने वाले एमए, एलएलबी, बीएड अजीज खां ने मुस्तकीम से संपर्क किया तथा उसे बदलने की कोशिश की. उसने मुस्तकीम को वर्तमान व्यवस्था का चरित्र समझाया. मुस्तकीम की समझ से प्रभावित होकर अजीज उसी के साथ रहने लगा तथा ऊंच-नीच, अमीर-ग़रीब आदि के बारे में समाजवादी व्याख्याएं बताने लगा. मुस्तकीम ने अजीज खां के निर्देशन में पिछड़े तबकों के जितने भी गिरोह थे, उन सबको धीरे-धीरे संगठित करना प्रारंभ किया, लेकिन जब यह प्रयास सफल नहीं हुआ, तो वह मल्लाहों, गड़रियों, काछियों तथा मुसलमानों के ग़रीब, बेरोज़गारों-नौजवानों से संपर्क कर एक सेना-सी बनाने लगा. अजीज को राठ पुलिस ने पकड़ कर चार दिन हवालात में रखा और बाद में गोली मार दी. इसके बाद मुस्तकीम ने मुस्लिम नाम के एक नौजवान को अपने गिरोह में शामिल किया, जो उसे समाचार, किताबें आदि पढ़कर सुनाता था.

मुस्तकीम अब जिस रास्ते पर चल रहा था, वह शायद उसे किसी किस्म के नक्सलवाद की ओर ले जाता. पुलिस व राजनीतिज्ञों ने यह ख़तरा महसूस किया कि यदि नक्सलवादियों ने मुस्तकीम से संपर्क कर लिया, तो एक नई मुसीबत हो जाएगी. इसलिए वे किसी भी क़ीमत पर मुस्तकीम का सफाया करना चाहते थे, यह तो ऊपर की रणनीति थी. नीचे का तबका तो मुस्तकीम से इसलिए नाराज़ था, क्योंकि उसने पुलिस को उसका हिस्सा देना बिल्कुल बंद कर दिया था. हमीरपुर पुलिस ने कुछ दिन पहले मुस्तकीम नाम के एक दूसरे आदमी को धोखे से मार दिया था. बताया जाता है कि मुस्तकीम व अजीज खां के विचारों से मलखान भी काफी प्रभावित हुआ तथा उसने भी अमीर-ग़रीब वाले सिद्धांत पर चलने की सलाह बाकी दस्यु दलों को दी. मलखान सिंह स्वयं बहुत ग़रीब घर का रहा है. बहरहाल, जबसे मुस्तकीम ने ऐसी ज़िंदगी अपनाई, उसे बाबा कहा जाने लगा. मुस्तकीम का अपना परिवार आज भी ग़रीब है और मज़दूरी पर ज़िंदा है. चंबल घाटी में पनपे इस नए रुझान को बिना समझे, केवल क़ानून-व्यवस्था की समस्या के आधार पर नई स्थिति की व्याख्या करना नासमझी होगी.

एक तरफ़ जहां डाकुओं का चरित्र बदल रहा है, पुलिस भी अब एक नए रूप में सामने आ रही है. इसका प्रमाण है, एनकाउंटर की घटनाओं में हाल में हुई वृद्धि. एनकाउंटर के बारे में पुलिस के बड़े अफसरों में दो प्रकार के मत हैं. कुछ का तो मानना था कि जहां तक संभव हो, डाकू को तत्काल मार देना चाहिए. पर दूसरों का मानना था कि यदि वादा किया जाता है, तो फिर उसकी जान नहीं लेनी चाहिए. लगभग सारा पुलिस प्रशासन समझता है कि गवाही आदि के अभाव में अदालतें प्रभावहीन-सी हो गई हैं, इसलिए एकमात्र इलाज जान से मार देना ही है. यहां यह सवाल पैदा होता है कि क्या सन् 72 का




आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

समर्पण ग़लत था? यदि वह उचित था और उसके अच्छे परिणाम आए, तो फिर उसी रास्ते पर क्यों नहीं चला गया? जो चंबल घाटी लगातार सात साल तक शांत बनी रही, उसे दोबारा सुलगाने की ज़िम्मेदारी नौकरशाहों व राजनीतिज्ञों की भी है. डाकू भी बंदूक का शासन चलाता है और पुलिस भी उसी रास्ते पर है. डाकू अपना क़ानून चलाते हैं, पुलिस भी संविधान से अलग अपना क़ानून चलाती है. यदि भारतीय संविधान व दंड संहिता इस कदर बेकार व अप्रासंगिक हो गए हैं, तो सरकार इसे खुलेआम क्यों नहीं स्वीकार करती और ज़रूरी संशोधन के लिए क्यों कार्यवाही नहीं करती?

### मुस्तकीम को मारना तो था ही

डाकू मुस्तकीम की हत्या थाना डेरापुर के सब-इंस्पेक्टर हरिराम पाल ने की. श्री पाल ने इस सिलसिले में एक लंबी बातचीत के दौरान यह स्वीकार किया कि मुस्तकीम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने की पूरी सुविधा थी, लेकिन उन्होंने उसे मार डालना ही बेहतर समझा. हरिराम पाल के वक्तव्य के अंश:-

मैंने मुस्तकीम को पकड़ लिया. उसने मेरी अंगुली चबा ली. फिर उसने मेरी बंदूक अपने दोनों हाथों से छीन ली. उसने दो बार निशाना साधकर फायर करने की कोशिश की, तो मैंने कहा....(गाली), इसमें....(शरीर का एक अंग) भी नहीं है. अपनी भाषा में मैंने कहा, इसमें कुछ भी नहीं है. खाली है. कारतूस मैंने फेंक दिए हैं. उसने जब देखा कि इसमें कुछ नहीं है, तो वही बंदूक दो-तीन बार मारी. फिर उसने दोहत्था पलट कर ऐसा मारा कि बंदूक टूट गई. टूटी बंदूक फिर मैंने ले ली और फेंक दी कि अब इसका करना क्या, यह बेकार हो गई. बस एक हाथ से उसे थाम लिया, यह हाथ छूटा नहीं. खूब जमकर एक घंटा मल्लयुद्ध हुआ. कभी हम नीचे, तो कभी वह. मैं पुकारता रहा, जल्दी चलो, बदमाश हैं, पर (गांव का) एक भी आदमी नहीं आया. एक आदमी गट्ठर लिए खड़ा था. मैंने उससे कहा, भलेमानुस, बोझ डाल दे, कुछ हमारी सहायता कर, यह बदमाश है. उसने गट्ठर साइकिल पर रख दिया, साइकिल चलाई और लंबा हुआ. इसके बाद काफी देर हो गई, तो हम फिर चिल्लाए, भइया, गांव वालों, चलो, बदमाश हैं, मारे डाल रहे हैं, बचाओ-बचाओ. इतने में यही डुकरा, सो भी खाली हाथ, आधी धोती पहने, आधी कंधा पर डाले आ गया. मैंने कहा, दद्दा ऐसा है, अंगौछा ही दे दो, जिससे हम इसके हाथ बांध दें. उसने कहा, अंगौछा है नहीं. तब तक उसका लौंडा आ गया. बाप ने उससे कहा कि सारे ने काट खाया हमें. बाप का बदला उसने ले लिया.

उसके बाद मुस्तकीम का हाथ बांध दिया गया. लोगों ने कहा, ढील दो, ढील दो, तो हमने कहा कि भाग जाएंगे. हाथ-पैर उन्होंने खोल लिए, बहुत तगड़ा था वह. फिर भाग लिया, हमने पीछा किया. तब तक दो सिपाही हमारे पास आ गए थे, लाठी लिए-निहत्थे थे बिल्कुल. हम लोगों ने पीछा किया, उसके पीछे भागे. गिरते जाएं, भागते जाएं, गिरते जाएं...मारपीट, पकड़-धकड़ चलता रहा. उसके बाद जब होश आ गया, तो उसको ले गए. मारना तो था ही. लेकिन वहां की पब्लिक के सामने यह कांड हो नहीं सकता था. कुछ छह सिपाही थे और हम दो थे. यानी कुल आठ थे हम लोग. उसे बाईं करवट लिटाया गया. पांच-छह गोली से तो मरा नहीं, पलटा दे गया. फिर और मारे. आठ लोगों ने दस-दस, पंद्रह-पंद्रह फायर किए. (जहां तक मुस्तकीम के साथ वाले आदमी को न मारने का वादा करके मारने की बात है तो) यह पुलिस वाले करते हैं. यही सिखाया जाता है पुलिस वालों को कि पॉलिसी से काम लीजिए. पॉलिसी से ही पुलिस बनती है. ■

*(29 मार्च, 1981)*

feedback@chauthiduniya.com

# जब तोप मुक़ाबिल हो


संतोष भारतीय



# सुषमा और वसुंधरा को सजा ज़रूर मिलनी चाहिए

"वसुंधरा राजे के पुत्र की कंपनी में जिस तरह से ललित मोदी ने पैसा लगाया, वह कहीं पर भी नैतिक नहीं लगता और सुषमा स्वराज की पुत्री को फीस के नाम पर जो रकम काले या सफेद में दी गई, वह रकम भी संदेह पैदा करती है. सवाल सिर्फ़ इतना है कि क़ानून को जानने वाले लोग ही जब क़ानून का मखौल उड़ाएं, तब उनके साथ कोई क्या करे."

श्रीमती सुषमा स्वराज देश की विदेश मंत्री हैं और वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं. इन दोनों को लेकर देश में सवाल पर सवाल उठ रहे हैं. सवाल ललित मोदी को लेकर उठ रहे हैं. दोनों अपने-अपने ढंग से उन सवालों के जवाब दे रही हैं. लेकिन ऐसा लग रहा है कि देश उन जवाबों से सच्चाई को समझ नहीं रहा है.

एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुषमा स्वराज पहले भी केंद्र में मंत्री रही हैं और वसुंधरा राजे राज्य में कई बार मुख्यमंत्री रही हैं. इसलिए यह तो नहीं माना जा सकता कि उन्हें क़ानून नहीं पता है. इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि उन्हें किसी सच्चाई नहीं पता है. इसलिए जब उन्होंने ललित मोदी की मदद करने का फ़ैसला किया, तो उन्हें अच्छी तरह पता था कि वे देश के क़ानून को तोड़ रही हैं. विषय को छिपाकर षड्यंत्रकारी अपराध कर रही हैं. अगर यह काम सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे खुलकर करतीं, तो यह माना जा सकता था कि वे अपने राजनीतिक मित्र या व्यापारिक मित्र की मदद कर रही हैं. पर उन्होंने इस सारी चीज को छिपाने का काम किया और इसे छिपाया भी. इसका मतलब यह कि उन्होंने जान-बूझकर देश के क़ानून के साथ खेल खेला. और, क़ानून और संविधान की शपथ लेकर सत्ता में जाने के बाद उस शपथ को तोड़ दिया. मैं मानता हूं कि इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अपने अध्यक्ष के साथ उन्हें बचाने में लगे हों, तो फिर किसी भी क़ीमत पर उनका कौन बाल बांका कर सकता है.

पर इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आख़िर वह कौन-सी डील थी, जिसने ललित मोदी को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह स्वयं यह खुलासा करें कि दोनों ने उनकी मदद करने का वादा किया था. अगर ललित मोदी स्वयं इस बात को न कहते, तो देश के सामने यह बात न आ पाती. एक परफेक्ट प्लान था ललित मोदी, सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे के बीच में, जो सामने ही नहीं आता, अगर ललित मोदी उसका खुलासा न करते. वे कौन-से वादे थे, जिन्हें श्रीमती सुषमा स्वराज और श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने तोड़ा. यह जानना ज़रूरी है और यह भी कोई और नहीं, ललित मोदी ही बताएंगे, क्योंकि ये दोनों महान नेत्रियां कुछ भी बताने से रहीं. इसका मतलब है कि कुछ तो ऐसा था, जो और ज़्यादा गंभीर था.

वसुंधरा राजे के पुत्र की कंपनी में जिस तरह से ललित मोदी ने पैसा लगाया, वह कहीं पर भी नैतिक नहीं लगता और सुषमा स्वराज की पुत्री को फीस के नाम पर जो रकम काले या सफेद में दी गई, वह रकम भी संदेह पैदा करती है. सवाल सिर्फ़ इतना है कि क़ानून को जानने वाले लोग ही जब क़ानून का मखौल उड़ाएं, तब उनके साथ कोई क्या करे.

सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुषमा स्वराज पहले भी केंद्र में मंत्री रही हैं और वसुंधरा राजे राज्य में कई बार मुख्यमंत्री रही हैं. इसलिए यह तो नहीं माना जा सकता कि उन्हें क़ानून नहीं पता है. इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि उन्हें किसी सच्चाई नहीं पता है. इसलिए जब उन्होंने ललित मोदी की मदद करने का फ़ैसला किया, तो उन्हें अच्छी तरह पता था कि वे देश के क़ानून को तोड़ रही हैं. विषय को छिपाकर षड्यंत्रकारी अपराध कर रही हैं. अगर यह काम सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे खुलकर करतीं, तो यह माना जा सकता था कि वे अपने राजनीतिक मित्र या व्यापारिक मित्र की मदद कर रही हैं.

यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फिर बात करने की इच्छा होती है. अभी सरकार का एक साल पूरा हुआ था और आपने कहा था कि हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ. प्रधानमंत्री जी, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? प्रधानमंत्री जी, क्या यह क़ानून के साथ छल नहीं है? क्या यह संविधान द्वारा ली गई शपथ का उल्लंघन नहीं है? और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी, अभी तो ये दो किस्से सामने आए हैं. जिस तरह आपसे पहले वाली सरकार में कुछ किस्से सामने आने के बाद किस्सों का सिलसिला शुरू हो गया था. हम आशा करते हैं कि वैसे सिलसिले अब शुरू नहीं होंगे. पर आप अगर इन दोनों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो आप देश के प्रधानमंत्री नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे. जैसे मनमोहन सिंह कांग्रेस के प्रधानमंत्री के नाते परिवर्तित हो गए थे. आपसे आशाएं हैं, आपसे कई नए कामों की अपेक्षा है, लेकिन आप विपक्षियों के उस आरोप की पुष्टि कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी समाधि में चले गए हैं. वह उन सवालों के ऊपर लंबी-लंबी बातें करते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं और जिन सवालों के जवाब देने चाहिए, उन पर खामोश रह जाते हैं. पर यह तो फ़ैसला आपको करना है प्रधानमंत्री जी.

मैं इस संपादकीय को यहीं समाप्त कर रहा हूं, इस सवाल के साथ कि अगर कोई अनजान आदमी, साधारण आदमी क़ानून तोड़े और अनजाने में क़ानून तोड़े, तो उसे कानून तोड़ने की सजा के बतौर जेल मिलती है. वह कितनी भी माफ़ी मांगे, उसे माफ़ नहीं किया जाता, लेकिन सत्ता के शिखर पर बैठे लोग जब जान-बूझकर क़ानून तोड़ते हैं, तो उसे उनकी मासूमियत मान लिया जाता है. फिलहाल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने तो ऐसा ही किया है. उन्होंने अपनी दो मासूम महिला नेताओं को बरी कर दिया है और किसी भी तरह की कार्रवाई करने से परहेज कर लिया है. तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी कांग्रेस की सरकार से बहुत अलग नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बहुत अलग नहीं हैं. हमें यह मान लेना चाहिए. ■

editor@chauthiduniya.com

# क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाएंगे

वर्ष 2013 तक यह गठबंधन अच्छी तरह से काम करता रहा. भाजपा एक आदर्श गठबंधन सहयोगी बनी रही. जब तक यह गठबंधन जारी रहा, संघ परिवार ने भी बिहार में कोई अप्रिय व्यवहार नहीं किया. उसके बाद 2013 के मध्य में नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया. वजह किसी से छिपी हुई नहीं थी. उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का पद त्याग दिया. फिर हमने मांझी को आते और जाते देखा. दरअसल, 2013 के मध्य से विकास का काम जदयू के अकेले के शासनकाल में बाधित रहा.


मेघनाद देसाई

विपक्ष को गठबंधन बनाने के लिए प्रेरित करना भाजपा- एनडीए की एक ऐसी उपलब्धि है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया. विपक्षी दलों को एक मंच पर एकत्र होकर गठबंधन बनाने की प्रेरणा भाजपा, आरएसएस एवं विहिप के अत्यधिक धार्मिक लहजे से मिली है. वे सेकुलरिज्म का बैनर लहराते हैं, जो उनके मुताबिक संघ परिवार के हिंदू राष्ट्रवाद के ठीक विपरीत है. यही तर्क उत्तर प्रदेश एवं बिहार के यादव गठबंधन का है, जिसने राजद, जदयू और समाजवादी पार्टी को इकट्ठा किया है. गठबंधन बनाने में आपसी अहंकार आड़े आ गया और एक लंबे समय तक किसी को पता नहीं था कि इस गठबंधन का क्या होने वाला है. लेकिन, अंततः मुलायम सिंह यादव की वरिष्ठता का लिहाज़ रखते हुए गठबंधन पर मुहर लग गई. अब ऐसा लगता है कि साल के बाकी बचे हिस्से के लिए या बिहार चुनाव तक नीतीश कुमार और लालू यादव ने अपने-अपने तीर अपने-अपने तरकश में छिपा लिए हैं. इस अफ़वाह के बावजूद कि सोनिया गांधी लालू यादव के हक़ में हैं, जबकि राहुल लालू को नहीं चाहते, कांग्रेस भी गिरते-पड़ते इसमें शामिल हो गई. ख्याल रहे कि यह वही राहुल हैं, जिन्होंने आवेश में आकर उस अध्यादेश को फाड़ दिया था, जिसके पारित होने की स्थिति में लालू यादव अपनी सदस्यता खोने से बच जाते. बहरहाल, इस वजह से लालू के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार स्वीकार करना आसान हो गया.

बिहार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के लिए जो सबसे दिलचस्प तथ्य है, वह है देश के अन्य भागों के एक बड़े हिस्से के विपरीत यहां हिंदू वर्ण व्यवस्था आज भी मतदान प्रणाली को प्रभावित करती है या कम से कम सेक्युलर पार्टियां तो यही



सोचती हैं. लिहाज़ा, उम्मीदवारों को टिकट देने से पहले ऊंची जाति, ओबीसी एवं दलित के समीकरण को सावधानीपूर्वक बैठाया जाएगा. बेशक मुस्लिम वोटों के लिए भी खेल होगा. इसलिए ब्राह्मण, यादव, मुस्लिम एवं दलित की जोड़-तोड़ चुनाव प्रचार पर हावी रहेगी. यहां न तो रोटी, कपड़ा, मकान का कोई मतलब है और न बिजली, पानी, सड़क का. यहां आपके लिए आपकी जाति अहम है और मुसलमानों के लिए उनकी धार्मिक पहचान. अब सवाल यह उठता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार आज भी जातिवाद की उलझन में क्यों फंसे हुए हैं? आज़ादी के 67 वर्षों बाद भी ये दोनों राज्य देश के अन्य राज्यों के मुक़ाबले पिछड़े क्यों हैं? देश की आबादी और पिछड़ेपन में इन राज्यों की बड़ी हिस्सेदारी है, जो मानव संसाधन विकास, प्रति व्यक्ति आय और न्याय के किसी भी मानक पर भारत की स्थिति कई पायदान नीचे गिरा देती है. देश में अब यही दोनों आख़िरी बीमारू राज्य क्यों बचे हैं?

ज़रा गौर कीजिए कि इन राज्यों पर कौन शासन कर रहा है. आज़ादी के बाद के पहले 43 वर्षों तक यहां कांग्रेस सत्ता में रही. बाकी देश में कांग्रेस का वर्चस्व स्थापित करने में यही दो राज्य सहायक थे. कांग्रेस ब्राह्मण-ठाकुर राज चला रही थी और पिछड़ी जातियों को नज़रअंदाज़ कर रही थी. इस दौरान उसने इन जातियों की लड़कियों की कौन कहे, लड़कों में भी साक्षरता फैलाने की कोशिश नहीं की और न आधारभूत सुविधाओं में किसी तरह का निवेश किया. ये दोनों राज्य धार्मिक अंधविश्वास, जातीय दमन और अभिजात्य वर्ग की सत्ता के पर्यायवाची बन गए. राजीव गांधी की ग़लतियों की वजह से कांग्रेस के वर्चस्व की समाप्ति के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप जो अवसर सामने आया, उसे यादव पार्टियों ने अपने हाथों से जाने नहीं दिया और अपनी जाति के लोगों को इन राज्यों को लूटने में लगा दिया. लालू दिलेरी से कहते रहे कि विकास नहीं, सम्मान चाहिए. मुलायम सिंह यादव ने तो यह भी नहीं कहा. उनके गांव सैफई के बाहर जैसे बाकी उत्तर प्रदेश ठहर गया. बिहार खुशकिस्मत था कि वर्ष 2005 में जदयू सत्ता में आ गया. भाजपा के साथ गठबंधन कर नीतीश कुमार ने विकास के सभी मोर्चों पर महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की, मुख्य रूप से लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में. पहली बार बिहार की विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से आगे थी. भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने राज्य के लिए एक संतुलित बजट पेश किया था.

वर्ष 2013 तक यह गठबंधन अच्छी तरह से काम करता रहा. भाजपा एक आदर्श गठबंधन सहयोगी बनी रही. जब तक यह गठबंधन जारी रहा, संघ परिवार ने भी बिहार में कोई अप्रिय व्यवहार नहीं किया. उसके बाद 2013 के मध्य में नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया. वजह किसी से छिपी हुई नहीं थी. उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का पद त्याग दिया. फिर हमने मांझी को आते और जाते देखा. दरअसल, 2013 के मध्य से विकास का काम जदयू के अकेले के शासनकाल में बाधित रहा. लिहाज़ा, जो गठबंधन अब बिहार में चुनाव लड़ने जा रहा है, राज्य की दुर्दशा में उसकी भागीदारी दो तिहाई है. अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में वापस आते हैं, तो उनके पास ऐसे सहयोगी होंगे, जिन्होंने बिहार को 58 वर्षों तक नुक़सान पहुंचाया है. उनका नारा होगा कि विकास नहीं, सेकुलरिज्म चाहिए. अगर वे चुनाव जीत जाते हैं और जदयू पिछड़ जाता है, तो क्या वे फिर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने देंगे? ■

feedback@chauthiduniya.com

उर्सुला को मॉस्को भेज दिया गया जहां उन्होंने बाकायदा सात महीने तक जासूसी का प्रशिक्षण लिया. प्रशिक्षण के दौरान रेडियो से सूचनाओं के आदान प्रदान में वे इतनी दक्ष हो गई थीं कि उनके प्रशिक्षक मानते थे वे रूस के लिए सबसे बेहतरीन जासूसों में से एक साबित होंगी. इसके बाद वे एक बार फिर चीन वापस चली गईं. चीन में वे उस इलाके में भेजी गईं जहां जापानी सेनाओं का आधिपत्य था. इन इलाकों से वे लगातार रूसी सेना को इस बात की जानकारी दिया करती थीं कि आखिरी जापानी मिलिट्री कैसे मूवमेंट कर रही है.

# कंजंक्टिवाइटिस से आंखों को बचाएं

मोनिशा भटनागर

बरसात का मौसम आने वाला है. यह मौसम ठंडक के साथ-साथ कई बीमारियां भी साथ लाता है. इस मौसम में होने वाली बीमारियों का मुख्य कारण है संक्रमण और इस संक्रमण के कारण होने वाली बीमारियों में से सबसे आम बीमारी है कंजंक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू. कंजंक्टिवाइटिस को बोलचाल की भाषा में आंख आना भी कहते हैं. आई फ्लू होने का मुख्य कारण वातावरण में बैक्टीरिया और वायरस का होना है, जो बारिश के मौसम में तेजी से बढ़ते हैं. ऐसे में ध्यान न देने पर आंखों में जल्दी इंफेक्शन हो जाता है. बारिश के इस मौसम में बरसात के तुरंत बाद तेज धूप और उमस में यह बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं. ये एक संक्रामक रोग है, जो एक व्यक्ति से दूसरे में बहुत तेजी से फैलता है. आम लोगों की सोच के अनुसार यह बात सही नहीं है कि आई फ्लू होने पर उस व्यक्ति की आंखों में देखने से यह रोग फैलता है, जबकि यह है कि उस व्यक्ति के इंफेक्टेड हाथों और उसके इस्तेमाल में लाए सामान का यूज करने से यह फैलता है. आई फ्लू वैसे तो ज्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन आंखों में होने के कारण ये काफी कष्टदायक होती है.

## कंजंक्विवाइटिस

इस संक्रमण की पहचान आंखों में तेज़ जलन होना है. आमतौर पर यह एक एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है लेकिन कई मामलों में बैक्टीरिया का संक्रमण भी इसके लिए जिम्मेदार होता है. नाक-कान अथवा गले में किसी तरह के संक्रमण के कारण वायरल कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है. इस संक्रमण की शुरुआत एक आंख से ही होती है, लेकिन जल्द ही दूसरी आंख भी इसकी चपेट में आ जाती है. यह एक बेहद संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे में बहुत तेज़ी से फैलती है. आंखों का ये संक्रमण आंखों की सफेद सतह की ऊपरी परत में होता है. इससे आंखें लाल हो जाती हैं,आंखों से पानी आने लगता है और तेज जलन होती है. पलकों पर पीला और चिपचिपा तरल जमा होने लगता है. आंखों में चुभन होती है और सूजन आ जाती है और तेज दर्द होता है. इस कारण आंखों में खुजली भी होती है. गौर करने की बात है कि हर व्यक्ति में यह लक्षण अलग-अलग या फिर गिने-चुने भी हो सकते हैं. अगर आपको इनमें से एक-दो लक्षण भी दिखें, तो बिना देर किए अच्छे आई-स्पेशलिस्ट को दिखाएं. कई बार इस संक्रमण के कारण बुखार भी हो जाता है. आमतौर पर ये परेशानी 2-3 दिन में ठीक हो जाती है लेकिन अगर 2-3 दिन में यह ठीक न हो तो तुरंत नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए. इसकी अनदेखी करने या गलत इलाज की वजह से ये रोग आंख की बाहरी परत यानी कॉर्निया में भी फैल सकता है. कंजंक्टिवाइटिस के कई प्रकार हैं. बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं, जबकि एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के लिए एंटीबायोटिक ड्रॉप डालने को दी जाती है और वायरल कंजंक्टिवाइटिस के मरीजों को बर्फ से आंखों को सेंकने की सलाह भी दी जाती है. बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई आंख में न डालें. ध्यान दें कि संक्रमण हो जाने पर कॉन्टेक्ट लैंस न लगाएं और काला चश्मा पहनें. ऐसे में संक्रमित व्यक्ति को घर से बाहर न जाने की भी सलाह दी जाती है ताकि बाहर की धूप और प्रदूषण से आंख का बचाव हो सके. साथ ही आंख पोछने के लिए मुलायम कपड़े या रुमाल का इस्तेमाल करें और इसे दुसरे लोगों की पहुंच से दूर रखें. जलन होने पर आंख न रगड़ें क्योंकि इससे दर्द और बढ़ सकता है. इस समय आंखों पर काफी जोर पड़ता है, इसलिए ठीक होने तक पढ़ना, टीवी देखना, ड्राइविंग वगैरह करने से बचें

**बारिश के इस मौसम में बरसात के तुरंत बाद तेज धूप और उमस में यह बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं. ये एक संक्रामक रोग है, जो एक व्यक्ति से दूसरे में बहुत तेजी से फैलता है. आम लोगों की सोच के अनुसार यह बात सही नहीं है कि आई फ्लू होने पर उस व्यक्ति की आंखों में देखने से यह रोग फैलता है, जबकि यह है कि उस व्यक्ति के इंफेक्टेड हाथों और उसके इस्तेमाल में लाए सामान का यूज करने से यह फैलता है.**

## बचाव

बरसात के मौसम में अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन से साफ करते रहें. खासकर खाना खाने से पहले या आंख पर हाथ लगाने से पहले हाथ ज़रूर धोएं. आंखों की साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखें और आंखों को ठंडे पानी से बार-बार धोएं. आंखों में सूखापन महसूस हो तो इन्हें बार-बार मसले नहीं बल्कि तीन-चार बार ठंडे पानी से धोएं. इसके साथ ही गंदगी और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें. मानसून के दिनों में आई मेकअप से परहेज करें क्योंकि धूल व अन्य प्रकार का प्रदूषण मेकअप से भी आंखों को नुकसान पहुंचता है. किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में खासकर उसके द्वरा इस्तेमाल की हुई चीज़ों के संपर्क में आने से बचें. संक्रमित व्यक्ति से हाथ न मिलाएं और उनकी चीजें जैसे चश्मा, तौलिया, तकिया आदि न छूएं. इस रोग के मरीज आंखों पर बार-बार हाथ न लगाएं. अगर संक्रमित आंख को छूएं तो हाथ को अच्छी तरह साफ करें. आंखों में बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा न डालें. ■

feedback@chauthiduniya.com

# हिटलर की तानाशाही के खिलाफ थीं उर्सुला

अरुण तिवारी

उर्सुला रूथ कुकजिंस्की एक जर्मन नागरिक थीं. वे एक उपन्यासकार होने के साथ-साथ जासूसी का काम भी किया करती थीं. दो शादियों और लगातार जासूसी के काम से जुड़ा होने के कारण विभिन्न स्रोतों के जरिये उर्सुला के कई नामों के उद्धरण मिलते हैं. उर्सुला के आलावा उन्हें रूथ वर्नर के नाम से भी जाना जाता है. उनके जीवन के आखिरी चार-पांच दशकों के दौरान उन्हें रूथ वर्नर के नाम से ही जाना जाता था. कुछ स्रोतों के अनुसार उन्हें उर्सुला मारिया ब्यूरटन के नाम से भी जाना जाता है. उर्सुला जाने माने अर्थशास्त्री रॉबर्ट रेने कुकजिंस्की की छठवीं संतान थीं. उनकी मां एक चित्रकार थीं. संभ्रांत परिवार में पैदा हुईं उर्सुला बचपन से होनहार बच्चों में गिनी जाती थीं. उनके सबसे बड़े भाई जुरगेन भी नामी अर्थशास्त्री और इतिहासकार रहे. उनका बचपन बर्लिन में बीता. जब वे मात्र 11 साल की थीं तभी उन्हें सिनेमा में एक छोटी बच्ची का किरदार निभाने का मौका मिला. इस फिल्म का निर्देशन जर्मनी के विख्यात निर्देशक रिचर्ड ओसवाल ने किया था.

उन्होंने स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही एक पुस्तक विक्रेता के साथ काम करना शुरू कर दिया. उन्होंने साल 1924 में वामपंथ से प्रभावित फ्री एम्प्लॉयज लीग ज्वाइन की. इसी साल उन्होंने यंग कम्यूनिस्ट संस्था और जर्मनी की रेड आर्मी भी ज्वाइन की. अपने 19वें जन्मदिन पर उर्सुला ने कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी ज्वाइन की.

इसके बाद उन्होंने लाइब्रेरियन का काम करना शुरू कर दिया और कई प्रकाशन घरो के साथ जुड़ गईं. लेकिन उन्हें प्रकाशन घरों से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने मई दिवस पर प्रदर्शन किया था. इसका एक कारण और था कि वे कम्यूनिस्ट पार्टी की सदस्य भी थीं. पार्टी से जुड़े होने के कारण उन्हें कई विरोध प्रदर्शनों में जाना पड़ता था और उसकी वजह से उनके कार्यालय का काम काज प्रभावित होता था. इसी दौरान कम्यूनिस्ट पार्टी के ही साथी के साथ उन्होंने विवाह कर लिया. पति के साथ वे 1930 में शंघाई शिफ्ट हो गईं. यहां उनके पति हैम्बर्गर, जो कि एक आर्किटेक्ट थे, काम के सिलसिले में आए थे. चीन में वे 1935 तक रही थीं. फिर उनकी मुलाकात एक पत्रकार से हुई जो सावियत इंटेलिजेंस के लिए काम किया करता था. ऐसा कहा जाता है कि उर्सुला के पति भी रूसी इंटेलिजेंस के लिए काम किया करते थे. लेकिन इस बात के स्रोत बहुत ही अपुष्ट हैं.

उर्सुला को मॉस्को भेज दिया गया जहां उन्होंने बाकायदा सात महीने तक जासूसी का प्रशिक्षण लिया. प्रशिक्षण के दौरान रेडियो से सूचनाओं के आदान प्रदान में वे इतनी दक्ष हो गई थीं कि उनके प्रशिक्षक मानते थे वे रूस के लिए सबसे बेहतरीन जासूसों में से एक साबित होंगी. इसके बाद वे एक बार फिर चीन वापस चली गईं. चीन में वे उस इलाके में भेजी गईं जहां जापानी सेनाओं का आधिपत्य था. इन इलाकों से वे लगातार रूसी सेना को इस बात की जानकारी दिया करती थीं कि आखिरी जापानी मिलिट्री कैसे मूवमेंट कर रही है. इस दौरान उर्सुला को एक रूसी एजेंट से प्रेम हो गया और इस बात की जानकारी रूसी अधिकारियों को लग गई. उन्हें मॉस्को बुला लिया गया. अधिकारियों को यह भय था कि अगर उर्सुला किसी सार्वजनिक स्थल पर पकड़ ली गईं तो उनकी पोल खुल सकती हैं. हालांकि उस दौरान चीन के जापान अधिकृत इलाकों में कई रूसी एजेंट तैनात थे लेकिन रेडियो पर सूचनाएं पहुंचाने के मामले में कोई भी उर्सुला का सानी नहीं था. उर्सुला का वहां पर पकड़े जाना रूस के लिए खतरनाक हो सकता है. रूसी अधिकारियों ने उर्सुला को इस बात की ताकीद की उनका प्रेम संबंध देश के लिए खतरनाक हो सकता है. उर्सुला ने अधिकारियों को इस बात का भरोसा दिया कि उनकी वजह से मिशन में कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी. वे चीन वापस भेज दी गईं. इस बार उर्सुला ने किया भी वही जिसका उन्होंने अधिकारियों से वादा किया था.

**उर्सुला ने एक खास तरह के नेटवर्क के जरिये नाजी अधिकारियों की गोपनीय जानकारियां लीक करने का सिलसिल कायम किया था. उनकी पहुंच जर्मनी की खुफिया एजेंसी गेस्टापो के अधिकारियों तक भी थी.**

इसके बाद उन्हें स्विट्जरलैंड भेज दिया गया जहां उन्होंने दो और रूसी एजेंटों के साथ मिलकर जर्मनी की नाजी सेना की इतनी गोपनीय जानकारियां लीक कीं कि जर्मनी के वरिष्ठ अधिकारी परेशान हो उठे. वे यह बात समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कैसे उनके सारे मिशन की जानकारी रूसी मिलिट्री को लग जाया करती है. उर्सुला ने एक खास तरह के नेटवर्क के जरिये नाजी अधिकारियों की गोपनीय जानकारियां लीक करने का सिलसिल कायम किया था. उनकी पहुंच जर्मनी की खुफिया एजेंसी गेस्टापो के अधिकारियों तक भी थी. दरअसल हिटलर ने यहुदियों के खिलाफ जो कार्रवाई की उर्सुला उसे दुर्भावनापूर्ण मानती थी इस वजह से उन्होंने नाजियों के खिलाफ काम करना शुरू किया. उनका मानना था कि यहुदियों के साथ हिटलर का बर्ताव अमानवीय था. जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई और इसमें जापान और जर्मनी की जबरदस्त पराजय हो गई तो वे वापस लौटकर एक बार अपने स्वेदश वापस लौट गईं. अब जर्मन बदल चुका था. वहां अब तानाशाही का अंत हो चुका था. इसके बाद उन्होंने अपने लेखन करियर की शुरुआत की जिसमें उन्होंने कुछ बेहतरीन किताबें लिखी. इनमें से कई किताबों में उनके जासूसी जीवन के अनुभवों को भी साझा किया गया. रूस की तरफ से बेहतरीन सेवायें देने के लिए उन्हें स्टालिन की बेहतरीन जासूस के नाम से भी जाना जाता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

## अमेरिका में अश्वेतों पर हमला

# भारत को नसीहत न दें ओबामा

**अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा भले ही भारत में ईसाइयों से संबंधित छिटपुट घटनाओं पर आतंकित होकर धार्मिक सहिष्णुता की सीख देते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि अमेरिका का खुद का श्वेतों और अश्वेतों के बीच नस्लीय हिंसा का रक्तरंजित इतिहास रहा है. अमेरिका में नस्लीय घटनाओं के कारण उन पन्नों को पलटकर देखने की फिर जरूरत महसूस होती है, जिनमें स्वतंत्र अमेरिका की इबारत लिखी गई थी. अमेरिका में आज भी श्वेत और अश्वेतों के बीच एक चौड़ी खाई मौजूद है. आज भी अश्वेतों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और यदि उन्हें भद्दा, गंवार या अनपढ़ के रूप में देखा जा रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया को उपदेश देने वाला और मानवाधिकार हनन करते हुए भी मानवाधिकारों की बातें करने वाला अमेरिका अभी भी उन मूल्यों को स्थापित नहीं कर पाया है, जिनकी अपेक्षा अब्राहम लिंकन एवं मार्टिन लूथर किंग ने की थी.**

राजीव रंजन

साल 2008 में बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद यह माना गया कि अमेरिका में श्वेतों और अश्वेतों के बीच की दूरी अब खत्म हो गई, लेकिन सप्ताह भर पहले अमेरिका के साउथ कैरोलिना के सबसे पुराने चर्च में संदिग्ध श्वेत हमलावर ने जिस तरह से गोलीबारी कर 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उसने फिर से एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि दुनिया को सभ्यता परोसने का दावा करनेवाले अमेरिका के अंदर इस असभ्य व्यवहार का कारण क्या है? क्या यह इतिहास की देन है या फिर नस्लीय सोच का. जिस तरह से अमेरिका में श्वेतों और अश्वेतों के बीच की लड़ाइयों में श्वेतों के पक्ष में न्यायिक निर्णय आता रहा है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि अमेरिका में न्याय भी श्वेत और अश्वेतों के बीच विभाजित है. वहां सार्वजनिक विचारों में भी एक विभाजन है. श्वेतों में भी रिपब्लिकनों में लगभग 70 प्रतिशत और डेमोक्रेट्स में लगभग 30 प्रतिशत ने इसे स्वीकार किया है. अफ्रीकी–अमेरिकियों के 86 प्रतिशत का यह मानना है कि अश्वेत एवं अन्य अल्पसंख्यकों को कानून के अंतर्गत समान ट्रीटमेंट नहीं मिलता, जबकि 54 प्रतिशत श्वेतों का कहना है कि अल्पसंख्यक समूहों के साथ समान व्यवहार होता है. कुल मिला कर अमेरिका में आज भी एक विभाजित समाज है और यह समाज तब तक बंटा रहेगा, जब तक कि श्वेत समुदाय अपनी बुनियादी सोच नहीं बदलती.

अभी कुछ ही महीने बीते हैं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि जिस तरह भारत में धार्मिक असहिष्णुता में इजाफा हुआ है, उसे देखकर महात्मा गांधी को भी सदमा लगता. ओबामा ने यह बयान अपनी भारत यात्रा के बाद स्वदेश वापसी के कुछ ही दिनों के अंदर दिया था. उस समय भारतीय जनता में भी यह सुगबुगाहट उठने लगी थी कि ओबामा ने हमारी मेहमाननवाजी की कद्र नहीं की और बेतुका बयान दे दिया. ओबामा के इस बयान पर भारतीय नौकरशाही ने भी आश्चर्य जाहिर किया था. यहां तक कि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का भी मानना था कि ओबामा ने अमेरिकी राजनीति में प्रभावशाली क्रिस्चियन लॉबी के चलते ऐसा बयान दिया था.

हम यह बात यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि समय–समय पर भारत में जो छिटपुट घटनाएं घटीं, जांच के बाद कोई ऐसे तथ्य नहीं मिले, जिसके आधार पर कोई यह कह सके कि इसमें भारत की धार्मिक सहिष्णुता खत्म हो रही है और अल्पसंख्यक हिंसा के शिकार हो रहे हैं. 2001 में बेंग्लुरु में दो चर्चों पर हमले हुए थे. तब भी यही कहा गया था कि तत्कालीन सरकार की सरपरस्ती की वजह से ही ये हमले संभव हुए. जांच में यह बात सामने आई कि हमले की इन वारदातों में दिनदार अंजुमन नामक एक पाकिस्तानी संगठन का हाथ था. इसी तरह झाबुआ में 4 ननों पर हमले को भी इसी तरह से प्रचारित किया गया था, पर जिन 18 लोगों पर आरोप साबित हुए वे सभी ईसाई थे. अगस्त 2009 में मैंगलोर में चर्च की संपत्ति नष्ट की गई. इस वारदात में पकड़े गए सभी आर–ोपी ईसाई थे, जिन्होंने यह स्वीकार किया कि उन्होंने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को अंजाम देने के लिए ही यह जघन्य कृत्य किया था. हमने इन घटनाओं को यहां इसलिए नहीं बताया कि हम यह कहना चाहते हैं कि देश में आगे किसी प्रकार की घटनाएं नहीं होंगीं, बल्कि हमारे कहने का यह मतलब है कि हर देश में छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उस देश को अपने नागरिकों के लिए कोई चिंता नहीं है और अमूक देश अपने ही नागरिकों पर हमले करा रहा है. अगर कोई देश ऐसा सोचता है, तो इसे उसके दिमाग का फितूर ही कहा जाएगा. अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि कोई देश सिर्फ दुष्प्रचार या राजनीति करने के लिए अल्पसंख्यकों का नाम लेकर अत्याचार की बात कहे या अन्य फिजूल बातें करे और पीड़ित देश पर आरोप मढ़े. ओबामा का भारत के असहिष्णुता को लेकर दिया गया यह बयान तथ्यों पर आधारित न होकर उस दुष्प्रचार पर आधारित था, जो सुनियोजित ढंग से भारतीय राज्य और समाज को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है. उन दिनों भारत में ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी, जिससे ओबामा या व्हाइट हाउस आतंकित हों. दिल्ली में चर्चों को लेकर जो घटनाएं घटीं थीं, उसे देखने पर पता चलता था कि हमले की ये घटनाएं सुनियोजित सामूहिक हमला न होकर, छिटपुट वारदातें थीं, जिसकी गारंटी दुनिया का कोई देश नहीं दे सकता कि उसके देश में ऐसी घटनाएं नहीं घट सकतीं या नहीं घटतीं. न कोई इन घटनाओं में हताहत हुआ था, न किसी की जानें गई थीं. इसलिए अगर यह कहा जाए कि हमले की उन घटनाओं में साजिश की बू ज्यादा नजर आती है, तो गलत नहीं होगा. यहां तक कि उन हमलों की किसी समूह ने जिम्मेदारी भी नहीं ली थी और न ही आगे किसी ने हमले की धमकी दी. क्या यह ईसाइत के प्रचार का शिगूफा था. यह कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि विश्व के ईसाई देश इस तरह के दांव खेलने में लगे हैं और इसीलिए दूसरे देशों में छोटी घटनाओं पर भी उस देश के हुक्मरान बयान देने में देर नहीं करते, जो सिर्फ और सिर्फ सामने वाले देश पर दबाव बनाने की नीति के तौर पर देखा जाता है. इसलिए हमले की ये घटनाएं दुष्प्रचार और ध्रुवीकरण की कोशिश के तहत किए गए प्रयास ही अधिक लगते हैं.

अमेरिका में भी आए दिन हिन्दू मंदिरों पर हमले होते रहे हैं. हमलावर मंदिरों में सिर्फ तोड़फोड़ ही नहीं करते, बल्कि अपनी भाषा में दीवारों पर संदेश भी लिख जाते हैं. हाल ही में उपद्रवियों ने ओल्ड लेक हाइलैंड्स, उत्तरी टेक्सस के मंदिर में दरवाजे पर स्प्रे पेंट से नंबर 666 और क्रॉस पेंट कर दिया था. वॉशिंगटन में भी दो मंदिरों की खिड़कियां तोड़ दी गई थीं और दीवारों पर फीयर लिख दिया गया था. हमलावरों ने केंट शहर के मंदिर की खिड़कियों पर ईंटों से हमला किया था. सिएटल के एक मंदिर की दीवारों पर गेट आउट और स्वास्तिक पेंट कर दिया गया था. क्या ओबामा इस बात को भूल गए कि अमेरिका में ही कुछ समय पहले कुरान जलाई गई थी. एक सिख पर सिर्फ इसलिए हमला हुआ था कि वह मुस्लिम जैसा दिखता था. वैसे इस तरह की घटनाओं की फेहरिस्त काफी लंबी है और इस तरह की घटनाएं केवल अमेरिका में ही नहीं होतीं, बल्कि यूरोप के अधिकांश देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी होती हैं. धार्मिक सहिष्णुता को लेकर बराक ओबामा ने भारत के ऊपर भले ही उंगली उठाई थी, लेकिन उनके देशों में हिन्दू मंदिरों में तोड़फोड़, मुस्लिम समुदाय के साथ दोहरे मापदंड और सिखों पर हमले की घटनाओं का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन ओबामा ने इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई जहमत नहीं उठाई. फलतः घटनाएं आज भी बदस्तूर जारी हैं.

हिन्दू, मुस्लिम और सिखों की बात अगर कुछ समय के लिए छोड़ भी दी जाए, तो अफ्रीकी–अमेरिकी ईसाइयों पर अमेरिका में क्यों जानलेवा हमले होते हैं, इस बात का जवाब है अमेरिका के पास. आज भी काले लोगों के साथ अमेरिका में जो व्यवहार होता है, वह लिंकन के सपनों की हत्या जैसा ही है. अगर आज लिंकन जिंदा होते तो वे इराक, सीरिया आदि हिस्सों में अमेरिकी कृत्यों पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे होते. भारत को अमेरिका से सांप्रदायिक सद्भाव और धर्मनिरपेक्षता पर सीख लेने की जरूरत नहीं है. अमेरिका की तरह भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी धार्मिक ग्रंथ पर हाथ रखकर शपथ नहीं लेते, वरन् संविधान पर हाथ रखकर सबक लेते हैं. बाइबिल पर हाथ रखकर तो अमेरिकी राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, इसलिए ओबामा को सबसे पहले अपने यहां के नस्लीय भेद की चौड़ी खाई को पाटनी चाहिए और ओबामा के लिए तो यह और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि ओबामा अमेरिका के पहले अश्वेत अफ्रीकी–अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, इसलिए अमेरिकी अश्वेतों को उनसे कुछ खास अपेक्षा है. जरूरी है कि ओबामा पहले अपना घर संभालें, हमें नसीहत न दें. ■

feedback@chauthiduniya.com

**धार्मिक सहिष्णुता को लेकर बराक ओबामा ने भारत के ऊपर भले ही उंगली उठाई थी, लेकिन अमेरिका में आए दिन हिन्दू मंदिरों पर हमले होते रहे हैं. हमलावर मंदिरों में सिर्फ तोड़फोड़ ही नहीं करते, बल्कि दीवारों पर अपने संदेश भी लिख जाते हैं. अमेरिका में मुस्लिम समुदाय के साथ दोहरे मापदंड और सिखों पर हमले की घटनाओं का भी लंबा इतिहास रहा है, लेकिन ओबामा ने इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई जहमत नहीं उठाई. फलतः घटनाएं आज भी बदस्तूर जारी हैं.**

### अमेरिकी जनसंख्या की नस्लीय संरचना

- 72.4 फीसदी श्वेत या यूरोपीय मूल के हैं.
- 12.6 फीसदी अश्वेत या अफ्रीकी मूल के हैं.
- 4.8 फीसदी एशियाई अमेरिकी हैं.
- 0.9 फीसदी अमेरिकन–इंडियन या अलास्का नेटिव हैं.
- 0.2 फीसदी हवाई मूल निवासी या अन्य प्रशांत द्वीपीय हैं.
- 6.2 फीसदी अन्य नस्ल के हैं.
- 2.9 फीसदी दो या अधिक नस्ल के हैं.

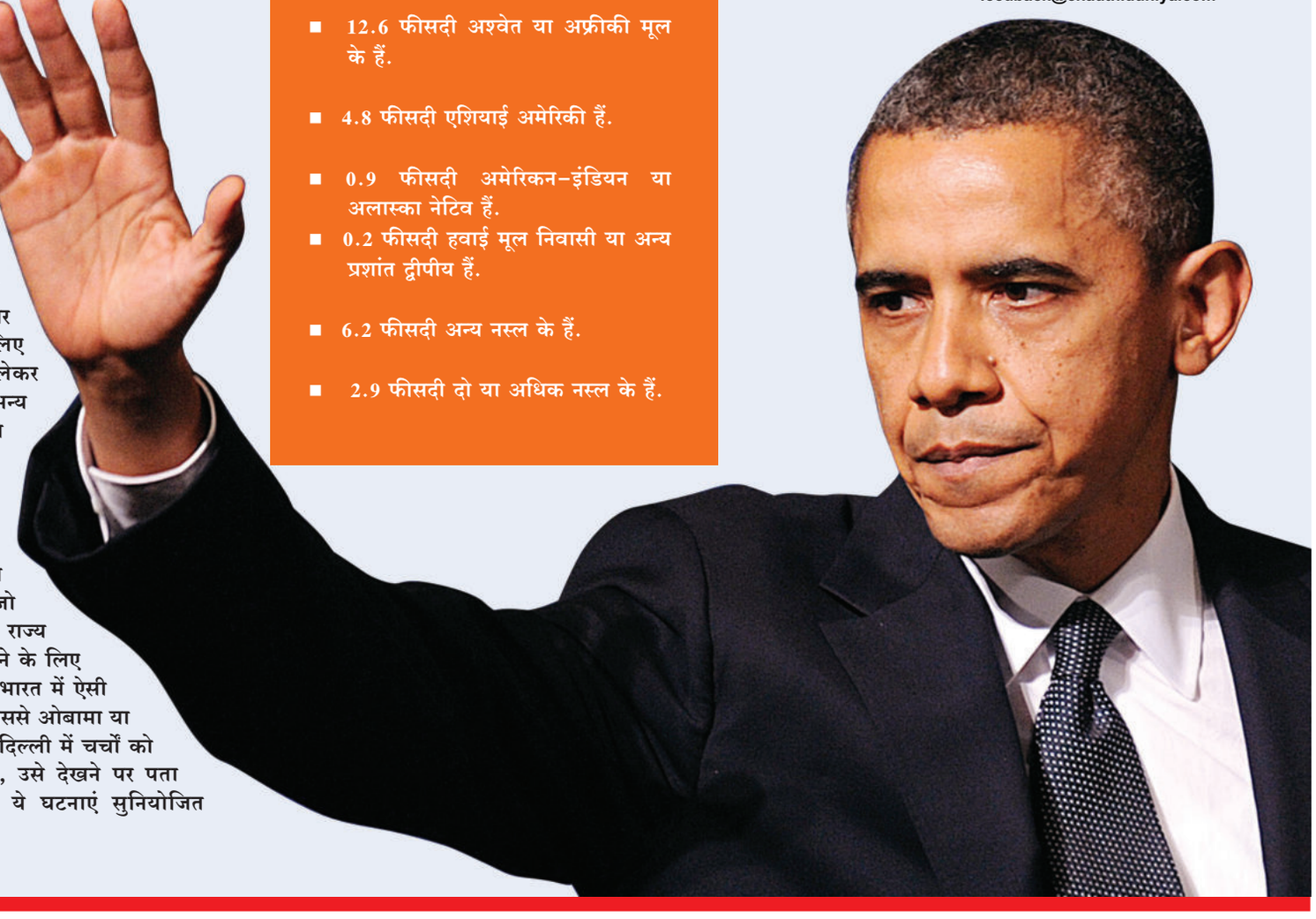

बातचीत होने लगी, कौन कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, किसकी झोली में क्या रखा है! एक यात्री ने बताया कि उसने अपनी पीछे की झोली में कुटुम्बियों और उपकारी मित्रों की भलाइयां भर रखी थीं और सामने की झोली में उन लोगों की बुराइयां रखी थीं. दूसरे ने आगे के झोले में अपने मित्रों और हितैषियों की अच्छाईयां लटका रखी थीं और उनकी बुराइयों की थैली पीछे लटका रखी थी, जिन्हें देख–देखकर अपनी सराहना करता और खुश होता.

# गुरु के बताए सन्मार्ग का अनुसरण करें

चौथी दुनिया ब्यूरो

**ईश्वर के प्रति समर्पण क्या अर्थ है?**

जब ईश्वर के प्रति कर्म, भक्ति, ज्ञान और इच्छा का समर्पण हो. कर्म भक्ति और ज्ञान के साथ–साथ जब तक इच्छा का भी समर्पण न किया जाए, तब तक समर्पण पूर्ण नहीं होता. म्हालसापति, काका साहेब दीक्षित आदि बाबा के उत्कृष्ट भक्तों के रूप में इसलिए जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बाबा के प्रति पूर्ण समर्पण किया था.

यह सत्य है कि मन बहुत जल्दी विचलित हो जाता है. विचलित में वि उपसर्ग है और चल धातु है, जिसका तात्पर्य है- विशेष रूप से चलायमान. मन का स्वभाव ही है-चंचल होना. वस्तुत: मन अपने मन में कुछ नहीं है. मन एक आधार चाहता है. आंख के जरिए, नाक के जरिए, कान के जरिए या सूक्ष्म शरीर में उसको आधार चाहिए. जिसके साथ वह जुड़ा, उसी के साथ लग जाता है. किसी वस्तप को आंखों से देखने पर मस्तिष्क के अंदर उसकी जैसी स्मृति आ गई. मन वहां चलना शुरू कर देता है. मन सदैव दौड़ता रहता है.

**श्री गुरु को पूर्ण समर्पण कैसे और कब करना चाहिए?**

गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण सुगम नहीं है. गीता में कहा गया है कि जो गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण कर देता है, वह स्वयं ही गुरु रूप हो जाता है. गुरु के सारे गुण और शक्तियां उसमें ढलने लगती हैं.

एक शिष्य को छोटी–छोटी बातों से शुरू करना चाहिए. प्रत्येक कार्य गुरु को मन में धारण करते हुए करें और गुरु द्वारा बताए गए सन्मार्ग का अनुसरण करें. ऐसा करने से वह धीरे–धीरे समर्पण की दिशा में अग्रसर होगा. अर्पण करने से अभिप्राय है कि अपने तन, मन, धन और आत्मा को गुरु के कार्य में लगाना. इसमें सफलता धीरे–धीरे ही मिलती है, परन्तु इस प्रयास को निरंतर करते रहना चाहिए.

### स्थिर भाव

**आपकी दृष्टि में आध्यात्मिक मार्ग सबसे बड़ी कठिनाई क्या है?**

मन का नियंत्रण कर भावों को स्थिर करना सबसे अधिक मुश्किल है. भाव की स्थिरता नहीं होगी तो व्यक्ति कभी भी इस मार्ग पर आगे नहीं जा पाएगा. मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता इसलिए है. जिसके भाव में स्थिरता नहीं होगी, उसके द्वारा इस मार्ग में जाना बहुत ही मुश्किल है–वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता. वह चाहे कितना सोचे, बुद्धि लगाए सारी किताबें पढ़े, दस आदमी को गुरु बनाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाव ही स्थिर नहीं है. इसलिए जब भाव स्थिर होगा तब मन स्थिर होगा. और जब मन स्थिर होगा तभी ईश–प्राप्ति संभव है. सब कुछ कृपा पर आधारित है. इसलिए बाबा की आरती में प्रार्थना की गई है–

करूनिया स्थिर मन पाहू गंभीर हे ध्यान.
साईंचे हे ध्यान. पाहू गंभीर हे ध्यान.
कृष्णनाथा दत्त साईं जडो चित्त तुझे पायी.
चित्त देवा पायी. जडो चित्त तुझे पायी.

–अपने मन को स्थिर करके गंभीर ध्यान को प्राप्त करें. श्री साईं का ध्यान करें. गंभीर ध्यान को प्राप्त करें. हमारा चित्त आपके चरणों में स्थिर हो हे देव. आपके चरणों में यह लीन हो. आपके चरणों में हमारा चित्त स्थिर हो.

**हमारा मन छोटी–छोटी बातों से विचलित हो जाता है, उसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है?**

यह सत्य है कि मन बहुत जल्दी विचलित हो जाता है. विचलित में वि उपसर्ग है और चल धातु है, जिसका तात्पर्य है–विशेष रूप से चलायमान. मन का स्वभाव ही है–चंचल होना. वस्तुत: मन अपने मन में कुछ नहीं है. मन एक आधार चाहता है. आंख के जरिए, नाक के जरिए, कान के जरिए या सूक्ष्म शरीर में उसको आधार चाहिए. जिसके साथ वह जुड़ा, उसी के साथ लग जाता है. किसी वस्तप को आंखों से देखने पर मस्तिष्क के अंदर उसकी जैसी स्मृति आ गई. मन वहां चलना शुरू कर देता है. मन सदैव दौड़ता रहता है. मन को वश में करना ही बहुत कठिन है. जो लोग कहते हैं कि मन को वश में कर लिया है. यही सबसे बड़ा झूठ है. यह भी मन की परिकल्पना है और कहलवाता भी मन है. झूठ को सच बनाकर. जिस दिन मन संपूर्ण रूप से शांत हो जाएगा, उस दिन वह आत्मा के अधीन हो जाएगा, जो कि निश्चल है.

मन के दो पहलू हैं या दो प्रधान गुण हैं–(1) बोध और (2) इच्छा. मन को नियंत्रित करने के लिए अपनी सीमाओं, अपनी कमियों को पहले समझना चाहिए. जो अपनी सीमाओं को समझेगा वह सीमाओं को लांघ जाएगा. मन को गलत भावना से बचाए रखो, उन प्राणियों से अलग रहो, जो खराब बातें कहते हैं.

सद्गुरु की शरण में जाने से, उनके प्रति दृढ़ आस्था–भाव एवं सर्वोपरि उनकी कृपा से ही मन की चंचलता को किसी सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है.

**श्रेष्ठ पुरुष के क्या लक्षण हैं?**

श्रेष्ठ पुरुष वह है जो पूर्णत: मुक्त है, अनाश्रित है और जिसने अपनी सभी दुर्बल एवं अधोमुखी प्रवृत्तियों अर्थात् लालसाओं, कामवासनाओं, क्रोध आदि पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो. वह सभी परिस्थितियों में अनासक्त हो और उसका अहंभाव समाप्त हो गया हो. यहां तक कि उसे अपने पुरुष भाव अर्थात पुरुष होने का अहंकार भी न हो. अनेक ऋषि–मुनिगण, जिन्हें पुरुष होने का अभिमान था, पूर्ण रूप से तभी विकसित हो सके जब उनका पुरुष–भाव भी समाप्त हुआ.

**हमारी चेतना की क्या स्थिति होनी चाहिए?**

हमारी चेतना अत्यंत पवित्र होनी चाहिए. यदि वास्तव में हम ईश्वर के सार्वभौमिक स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं, तो हमें अपनी सभी पुरानी स्मृतियों, अनुभवों, अवधारणों को ध्यान से निकाल देना होगा, अन्यथा हमारी चेतना में सार्वभौमिकता के स्थान पर सीमित अवधारणाएं निरंतर प्रतिबिम्बित होती जाएंगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

## साईं के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

## साईं भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@chauthiduniya.com

# पाठकों की दुनिया

## हिमालय से छेड़छाड़ न हो

आलेख-जब सामने से गुजरी मौत (11 मई-17 मई) पढ़ा. हिमालय को अस्थिर करने पर चीन तुला है. नेपाल काठमांडु की नई पीढ़ी नें कभी धरती हिलते नहीं देखा था, जो इस बार आए भीषण भूकंप में देख लिया. वर्षों बाद आए इतने बड़े भूकंप ने नेपाल में तबाही मचा कर रख दी. भूकंप आने के बाद घरों में फंसे लोग पानी के लिए तरसते रहे और बहुत से लोग गिरे हुए मकानों में दबे ही रह गए, जो बाहर ही नहीं आ सके. भूकंप के दहशत के कारण कोई पीछे मुड़कर नहीं देखा. भूगर्भशास्त्री पहले भी सचेत कर चुके थे कि पहाड़ों को खोदना और पर्यावरण से खिलवाड़ करना भयंकर भूल साबित होगा. हिमालय पर सड़क बनाना और पहाड़ो के नीचे से सुरंग बनाकर रेल लाइन बिछाना पर्यावरण के दृष्टिकोण से खतरनाक है. चीन भी चाहता है कि नेपाल तक वो रेल लाइन बिछाए. अगर आने वाले दिनों भी ऐसे ही हिमालय की खुदाई जारी रही है, तो इसके भयंकर परिणाम भूगतने होंगे.

*–अशोक कुमार ठाकुर, दरभंगा, बिहार.*

## गाय हो राष्ट्रीय पशु

भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, किन्तु केन्द्र सरकार बाघ की जगह शेर को राष्ट्रीय पशु घोषित करने पर विचार कर रही है. वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट के अनुसार ऐसा होने पर बाघों को बचाने का अभियान प्रभावित होगा. सरकार के दृष्टिकोण को यदि एक किनारे कर दें, तो भारत के अधिकतर लोग चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए. भारत जैसे कृषि प्रधान, धर्मप्राण, अहिंसावादी और संपूर्ण विश्व का कल्याण चाहने वाले देश का राष्ट्रीय पशु अगर किसी को घोषित करना है, तो गौमाता(गाय) को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए.

*–राजकिशोर पांडेय, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.*

## दलित तय करेंगे कौन होगा मुख्यमंत्री

बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है. सभी दलों में जंग को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गयी हैं. यहां तक कि पुराने समीकरणों को तोड़ नये समीकरण गढ़े जा रहे हैं. प्रमाण यह कि कभी एक-दूसरे के घोर प्रतिद्वंद्वी रहे लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक बार फिर से एक-दूसरे के साथ हैं. वहीं भाजपा भी गठबंधन के मौजूदा दौर में अकेली खड़ी नहीं है. स्वयं को समाजवादी और सामाजिक न्याय का पथिक कहने वाले रामविलास पासवान के अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी भाजपा की शरण में जा चुके हैं. सामाजिक न्याय का चोला ओढ़कर भाजपाई खेमे में आश्रय पाने वालों में जीतन राम मांझी का भी नाम शामिल हो गया है. यानी पूरी लड़ाई पिछड़ा बनाम अगड़ा के आधार लड़े जाने की संभावना है, जिसमें जीत का दारोमदार दलितों के कंधे पर होगा. कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि इस बार सत्ता की पालकी ढोने की जिम्मेवारी दलितों की होगी.

*–नवल कुमार, ई-मेल के द्वारा.*

## कांग्रेस को बोलने का हक नहीं

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा ललित मोदी की मदद मामले में प्रतिदिन नए खुलासे होते जा रहे हैं. अगर सुषमा स्वराज ने कानून के दायरे में रहते हुए मानवीय आधार पर ललित मोदी की मदद की है, तो यह कोई बड़ा गुनाह नहीं है, जिस पर इतना हो हल्ला मचाया जा रहा है. बिट्रेन ने ललित मोदी के बारे में लिए गए फैसले पर खुद कह चुका है कि सारे फैसले कानून तहत लिए गए हैं. कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, ऐसा लगता है कि उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है जिस पर मोदी सरकार की आलोचना कर सके. अगर नयूज चैनलों की बात करें, तो वे भी केवल टीवी रेटिंग के लिए इस मुद्दे को हवा देने में लगे हैं. कांग्रेस के नेता इस पर नहीं बोलते कि जब ललित मोदी देश छोड़कर गए, तो किसी सरकार थी. कांग्रेस के नेताओं को अपने मंत्रियों ए राजा, कनिमोझी, कलमाड़ी और जमाईराजा वाड्रा पर भी बोलना चाहिए. बलत्कार का आरोप झेल रहे आसाराम समेत कई ऐसे आरोपी जेल में बंद हैं, कोर्ट में जिनकी पैरवी सलमान खुर्शीद और कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेस के बड़े नेता करते हैं. केवल इस मामले पर राजनीति के तहत तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, जो गलत है.

*–रजनीश यादव, बक्सर, बिहार.*

## केन्द्रीय मंत्री की बदहवासी

कवर स्टोरी-अरबों के घोटाले की जांच को लेकर केंद्रीय मंत्री की बदहवासी, ऐसा है प्रधानमंत्री कार्यालय, दस्तखत जून का, भेज दिया मई में(15 जून -21 जून 2015) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. प्रभात रंजीन दीन ने बिल्कुल सही कहा है कि अरबों के घोटाले की जांच को लेकर केंद्रीय मंत्री की बदहवासी. इसे बदहवासी नहीं केहंगे, तो क्या कहेंगे कि पत्र मई का और दस्तखत जून का. इतने बड़े घोटाले में केन्द्रीय मंत्री की बदहवासी मंत्री की नीयत पर सवाल खड़े करती है. प्रधानमंत्री नेरन्द्र मोदी भ्रष्टाचार पर, तो खूब बड़ी-बड़ी बाते करतें हैं. प्रधानमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस घोटाले की सीबीआई से जांच करानी चाहिए. इस मामले में जो दोषी पाए उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

*–निर्मल सिंह, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

# तीन यात्री

चौथी दुनिया ब्यूरो

एक चौराहे पर तीन यात्री मिले. तीनों के कंधों पर दो–दो झोले आगे–पीछे लटके हुए थे. अपनी लंबी यात्रा से तीनों थके हुए थे, लेकिन एक यात्री के चेहरे पर प्रसन्नता और उत्साह का भाव था. दूसरा यात्री श्रम से थका हुआ तो था, लेकिन निराश नहीं था, परन्तु तीसरा बेहद मुरझाया हुआ और दुखी दिख रहा था. तीनों एक पेड़ की छाया में बैठ कर सुस्ताने लगे.

बातचीत होने लगी, कौन कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, किसकी झोली में क्या रखा है! एक यात्री ने बताया कि उसने अपनी पीछे की झोली में कुटुम्बियों और उपकारी मित्रों की भलाइयां भर रखी थीं और सामने की झोली में उन लोगों की बुराइयां रखी थीं. दूसरे ने आगे के झोले में अपने मित्रों और हितैषियों की अच्छाईयां लटका रखी थीं और उनकी बुराइयों की थैली पीछे लटका रखी थी, जिन्हें देख–देखकर अपनी सराहना करता और खुश होता. फिर तीसरे यात्री से उन दोनों ने पूछा, तुम्हारे झोलों में क्या भरा है? आगे का झोला तो काफी भारी लगता है, पीछे का झोला हल्का है. उसने बताया कि उसने भी अच्छाइयों की थैली आगे और बुराइयों की थैली पीछे लटका रखी है लेकिन पीछे की थैली में एक छेद है, इसलिए बुराइयां टिकती नहीं, एक–एक कर गिर जाती हैं और पीछे का वज़न हल्का हो जाता है. जिस यात्री ने आगे के झोले में अच्छाइयां और पीछे के झोले में बुराइयां भर रखी थीं, वह प्रसन्न था, क्योंकि चलते समय उसकी नजर हमेशा अच्छाइयों पर ही पड़ती थी और बुराइयों को वह भुला रहता था, जिसके थैले में छेद था वह उत्साह से भी भरा रहता था, क्योंकि चलते समय वह आगे लटकी अच्छाइयों को तो देखता ही था, उस पर बुराइयों का वज़न भी कम रहता था. वे रास्ते में धीरे–धीरे गिर जाती थीं लेकिन जिसने बुराइयों की थैली आगे और अच्छाइयों की थैली पीछे लटका रखी थी, वह हमेशा थका हुआ और निराश रहता था. यही जीवन यात्रा का सार तत्व है. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

# पत्रों से खुलते राज

अनंत विजय

हिंदी साहित्य के इतिहास में पत्र साहित्य की समृद्धशाली परंपरा रही है. हिंदी में पत्र साहित्य को अमूमन तीन भागों में बांटा जाता है, व्यक्तिगत पत्रों का संकलन, कई किताबों के परिशिष्ट आदि में उससे जुड़े पत्रों का संकलन और पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित पत्रों का संकलन. ये तीनों ही हिंदी के लिए बेहद अहम हैं, लेकिन व्यक्तिगत पत्रों के संकलन से कई बार ऐसे राज खुलते हैं, जो अब तक किसी के संज्ञान में न आए हों. माना यह जाता रहा है कि हिंदी का पत्र साहित्य नए पाठकों के साथ–साथ, अन्य विधाओं में रुचि रखने वालों को भी ज्ञान और अनुभव के ऐसे प्रदेश में लेकर जाता है, जो कि उनके लिए एकदम अनजाना होता है. हाल में मैंने एक ऐसे ही अनजाने प्रदेश में प्रवेश किया. आज की युवा पीढ़ी कल्याण पत्रिका के नाम से अनजान है, लेकिन वे लोग, जो अभी अपनी युवावस्था के उतरार्द्ध में हैं, उनके लिए कल्याण पत्रिका अनजानी नहीं है. एक जमाना था, जब कल्याण हर घर के लिए एक ज़रूरी पत्रिका हुआ करती थी. हमें याद है कि हर महीने की लगभग नियत तारीख को डाकिया एक खाकी कागज में लिपटी–मुड़ी हुई पत्रिका देकर जाता था. उस तारीख का घर में सबको इंतजार रहता था. कालांतर में कल्याण की प्रसार संख्या कम होती चली गई. यह भी शोध का विषय है कि कल्याण जैसी अत्यंत लोकप्रिय पत्रिका लगभग समाप्त कैसे हो गई? शोध तो इस बात पर भी होना चाहिए कि कल्याण को धार्मिक पत्रिका के तौर पर प्रचारित किसने और क्यों किया, इसके पीछे मंशा क्या थी? कल्याण में सामाजिक बुराइयों और धार्मिक पाखंड पर भी लेख छपते थे.

हम बात कर रहे थे हिंदी में पत्र साहित्य और उसके माध्यम से पाठकों के ज्ञान के अछूते संसार में प्रवेश की. कल्याण के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पत्रों के कुछ ऐसे ही राज खुल रहे हैं, जिनके बारे में अभी देश के कम ही लोगों को मालूम होगा. हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने गोविंद वल्लभ पंत को एक पत्र लिखा है, जिसमें वह उनके ही पत्र को उद्धृत करते हैं, आप इतने महान हैं, इतने ऊंचे महामानव हैं कि भारतवर्ष को क्या, सारी मानवी दुनिया को इसके लिए गर्व होना चाहिए. मैं आपके स्वरूप के महत्व को न समझ कर ही आपको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना चाहता था. आपने उसे स्वीकार नहीं किया, यह बहुत अच्छा किया. आप इस उपाधि से बहुत ऊंचे स्तर पर हैं. मैं तो हृदय से आपको नमस्कार करता हूं. अपने उसी पत्र में हनुमान प्रसाद पोद्दार ने यह भी लिखा है कि यह सब पढ़कर उनको संकोच हुआ है और अंत में लिखते हैं, आपके आदेशानुसार पत्र को जला दिया है, आप भी मेरे इस पत्र को गुप्त ही रखिएगा. इस पत्र से यह बात खुलती है कि गोविंद वल्लभ पंत, जो उस वक्त गृह मंत्री थे, ने उनको भारत रत्न देने का प्रस्ताव किया था. भारत रत्न देने का फ़ैसला तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की सहमति से हुआ था. गोविंद वल्लभ पंत को हनुमान प्रसाद पोद्दार से सहमति लेने का ज़िम्मा सौंपा गया था, लेकिन पोद्दार जी ने भारत रत्न लेने से विनम्रतापूर्वक इंकार कर दिया था. इस बात की पुष्टि डॉ. राजेंद्र प्रसाद के पुत्र मृत्युंजय प्रसाद की एक टिप्पणी से भी होती है, पूज्य पिताजी की यह आंतरिक अभिलाषा थी कि श्रीभाई जी को ( हनुमान प्रसाद पोद्दार को लोग भाईजी ही कहते थे) भारत रत्न की उपाधि से विभूषित करके उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व को राजकीय सम्मान प्रदान करने का अवसर मिले, परंतु ऐसे सम्मानों–अभिनंदनों के प्रति श्रीभाई जी की घोर उपरामता के कारण उनकी वह सात्विक अभिलाषा पूर्ण नहीं हो सकी.

अब अगर पंत को लिखे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पत्र और मृत्युंजय प्रसाद की टिप्पणी को आपस में जोड़ कर देखते हैं, तो यह बात साफ़ हो जाती है कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लेने से इंकार कर दिया था. अब ये तथ्य और प्रसंग कहीं अन्यत्र नहीं मिलते हैं. इस तरह के प्रामाणिक खुलासे साहित्य की इस विधा यानी पत्र साहित्य में ही संभव हैं. पत्रकारिता और पत्रकारों के सरोकारों से जुड़े एक बड़े नाम अच्युतानंद मिश्र के संपादन में निकली एक किताब–पत्रों में समय संस्कृति से इन तथ्यों पर से पर्दा हटा है. पत्रों में समय संस्कृति को प्रभात प्रकाशन ने छापा है. अच्युतानंद मिश्र के संपादन में निकली यह किताब पढ़ने के बाद उस दौर के साहित्य और साहित्यकारों के पुनर्मूल्यांकन का सवाल उठता है. हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पत्रों को पढ़ते हुए यह बात साफ़ तौर पर सामने आती है कि उस वक्त कल्याण में समाज के हर क्षेत्र और वर्ग के विद्वान लिखा करते थे. हनुमान प्रसाद पोद्दार का पत्र व्यवहार नंद दुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, कन्हैया लाल मिश्र एवं चतुरसेन शास्त्री आदि के साथ लगातार होता रहता था. तीन मार्च, 1932 का प्रेमचंद का एक पत्र है, जिसमें वह कहते हैं, आपके दो कृपा पत्र मिले. काशी से पत्र यहां आ गया था. हंस के विषय में आपने जो सम्मति दी है, उससे मेरा उत्साह बढ़ा. मैं कल्याण के ईश्वरांक के लिए अवश्य लिखूंगा. क्या कहें, आप काशी गए और मेरा दुर्भाग्य कि मैं लखनऊ में हूं. भाई महावीर प्रसाद बाहर हैं या भीतर, मुझे ज्ञात नहीं. उनकी स्नेह स्मृतियां मेरे जीवन की बहुमूल्य वस्तु हैं. वह तो तपस्वी हैं, उन्हें क्या ख़बर कि प्रेम भी कोई चीज है. इसी तरह के कई पत्र हैं, जिनसे उस वक्त के परिदृश्य से पर्दा हटता है, धुंध भी छंटती है.

**अच्युतानंद मिश्र जी द्वारा संपादित इस किताब में निराला जी का एक पत्र है 17 अक्टूबर, 1931 का, जिसमें वह लिखते हैं, प्रिय श्री पोद्दार जी, नमो नमः. आपका पत्र मिला. मैं कलकत्ता सम्मेलन में जाकर बीमार पड़ गया. पश्चात घर लौटने पर अनेक गृह प्रबंधों में उलझा रहा. कई बार विचार करने पर भी आपके प्रतिष्ठित पत्र के लिए कुछ नहीं लिख सका. क्या लिखूं, आपके सहृदय सज्जनोचित बर्ताव के लिए मैं बहुत लज्जित हूं.**

यह किताब पढ़ते हुए ज़ेहन में एक बात बार–बार कौंध रही थी कि वर्तमान समय को पकड़ने और उसे दर्ज कराने के लिए पत्र तो नहीं होंगे. इंटरनेट के फैलाव ने पत्रों की लगभग हत्या कर दी है. पत्रों की जगह ई–मेल ने ली है, पत्रों की जगह एसएमएस ने ले ली है. पत्रों के बजाय अब फेसबुक पर संवाद होने लगे हैं. तकनीक ने पत्रों के एहसास से हमें महरूम कर दिया. इन भावनात्मक नुक़सान के अलावा एक और नुक़सान हुआ है, वह यह कि पत्रों में एक वक्त का इतिहास बनता था. उस वक्त चल रहे विमर्शों और सामाजिक स्थितियों पर प्रामाणिक प्रकाश डाला जा सकता था, लेकिन पत्रों के ख़त्म होने से साहित्य की एक समृद्ध विधा तो लगभग ख़त्म हो ही गई है, इतिहास का एक अहम स्रोत भी ख़त्म होने की कगार पर है. अब अगर हम हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पत्रों की बात करें या मुक्तिबोध को लिखे पत्रों की बात करें, तो यह साफ़ तौर पर कह सकते हैं कि इन संग्रहों में उस दौर को जिया जा सकता है.

अच्युतानंद मिश्र जी द्वारा संपादित इस किताब में निराला जी का एक पत्र है 17 अक्टूबर, 1931 का, जिसमें वह लिखते हैं, प्रिय श्री पोद्दार जी, नमो नमः. आपका पत्र मिला. मैं कलकत्ता सम्मेलन में जाकर बीमार पड़ गया. पश्चात घर लौटने पर अनेक गृह प्रबंधों में उलझा रहा. कई बार विचार करने पर भी आपके प्रतिष्ठित पत्र के लिए कुछ नहीं लिख सका. क्या लिखूं, आपके सहृदय सज्जनोचित बर्ताव के लिए मैं बहुत लज्जित हूं. आपके आगे के अंकों के लिए कुछ–कुछ अवश्य भेजता रहूंगा. एक प्रबंध कुछ ही दिनों में भेजूंगा.

अब निराला के इन पत्रों या कल्याण में छपे निराला के लेखों का सामने आना शेष है. अगर मेरी स्मृति मेरा साथ दे रही है, तो नंद किशोर नवल द्वारा संपादित निराला रचनावली में न तो ये पत्र हैं और न कल्याण में छपी उनकी रचनाएं. निराला की राम की शक्ति पूजा और अन्य रचनाओं के आधार पर जिस तरह से उन्हें प्रगतिशीलता या जनवादिता का ताज पहना कर वामपंथी घूम रहे हैं, यह उनके रचना पक्ष का एक चेहरा है. जिस तरह से निराला को अनीश्वरवादी बताकर कुछ अज्ञानी आलोचक यश लूट रहे हैं, वह निराला के प्रति अन्याय है. जिस तरह से निराला ने अपने अभिवादन में नमो नमः का इस्तेमाल किया है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है. इसका यह मतलब कदापि नहीं निकाला जाना चाहिए कि निराला हिंदूवादी थे या निराला धार्मिक थे. अनुरोध इस बात का है कि अगर निराला के बारे में कुछ नए तथ्य सामने आए हैं, तो उनके समग्र मूल्यांकन में उन लेखों एवं तथ्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए. कहने का अर्थ यह है कि निराला के पत्रों के माध्यम से अगर साहित्यिक इतिहास सही किया जा सकता है, तो हमें बगैर किसी वाद–विवाद में पड़े संवाद के आधार पर उसे दुरुस्त कर देना चाहिए. ■

*(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)*
anant.ibn@gmail.com

# समाज की दरारों को आईना दिखाने की कोशिश

चौथी दुनिया ब्यूरो

कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है. आम तौर पर कविताएं स्वान्तः सुखाय होती हैं, लेकिन यदि इसके साथ ही उनमें समाज की चिंताएं समाहित हों, तो उनका दायरा व्यापक हो जाता है. कविताएं मन की पीड़ा को दर्शाती हैं. उस पीड़ा को स्रोत कुछ भी हो सकता है. जब तक समाज की पीड़ा लोगों के सामने नहीं आएगी, तब तक उसका इलाज भी नहीं किया जा सकता. समाज के शरीर पर वर्षों से मौजूद, पल या हाल ही में उपजे घावों से भी पर्दा हटाया जाना चाहिए, ताकि उन्हें नासूर बनने से रोका जा सके. यदि ऐसा नहीं होता है, तो अस्तित्व और पहचान का प्रश्न लोगों के समक्ष आ खड़ा होता है. समाज में पनप रही नई समस्याओं एवं चुनौतियों से मानवेंद्र सिंह यायावर भी अपने काव्य संग्रह–दरकती हवाएं में जूझते दिखे हैं. एक नौकरशाह ने कवि के रूप में अपनी चिंताएं जाहिर की हैं. एक नौकरशाह समाज के उन पहलुओं से भलीभांति वाकिफ़ होता है, जिनके बारे में लोग सार्वजनिक रूप से चर्चा करने में हिचकिचाते हैं.

**कवि यायावर का मानना है कि साहित्य सृजन बहुजन हिताय होना चाहिए. वह मानते हैं कि वर्तमान परिवेश या इस अर्थ युग में कोई साहित्यिक कृति क्रांति मचा दे, ऐसा संभव नहीं है. लेकिन, उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से आज के परिवेश, व्यवस्था, समाज और व्यक्ति के चरित्र में आई दरारों को दिखाने की कोशिश की है. उसी को उन्होंने दरकती हवा कहा है.**

समीक्ष्य कृति : दरकती हवाएं (काव्य संग्रह)
कवि : मानवेंद्र सिंह यायावर
प्रकाशक : प्रकाशन संस्थान, दरियागंज, नई दिल्ली
मूल्य : 80 रुपये

कवि यायावर का मानना है कि साहित्य सृजन बहुजन हिताय होना चाहिए. वह मानते हैं कि वर्तमान परिवेश या इस अर्थ युग में कोई साहित्यिक कृति क्रांति मचा दे, ऐसा संभव नहीं है. लेकिन, उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से आज के परिवेश, व्यवस्था, समाज और व्यक्ति के चरित्र में आई दरारों को दिखाने की कोशिश की है. उसी को उन्होंने दरकती हवा कहा है. दरकती हवाएं समय के साथ देश की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जूझते आम आदमी की पीड़ा की

ओर भी इशारा करती है. यायावर की कविताओं के अधिकांश पात्र हिंदी साहित्य से ही निकले हैं. उनकी नज़र में व्यवस्था आम आदमी की राह में सबसे बड़ी बाधा है. कविता– समय में उन्होंने यही बात बताई है:–

*प्रेमचंद का होरी*
*अज्ञेय का शेखर*
*निराला की पत्थर तोड़ती लड़की*
*दुनिया की रेलमपेल में*
*कसमसाता*
*मुक्तिबोध का मनु,*
*सब खुश हैं जी लेंगे*
*हम सब तो सिर्फ़*
*किसी न किसी व्यवस्था के शिकार थे.*
*अब समय है*
*बहुत माकूल*
*अव्यवस्था ने*
सबको आत्मसात कर मार्ग प्रशस्त किया है
हम सबको बराबर जीने का हक़ दिया है.

कवि की चिंताएं कुछ आधुनिक किस्म की हैं. उनकी चिंताओं में अंतरिक्ष यान का मलबा भी है, वह निजी अस्पतालों के अमानवीय एवं व्यवसायिक आचरण से भी दुःखी हैं. उन्हें लगता है कि भारतीय संस्कृति के स्थापित मूल्य बिखर रहे हैं, जिन्हें बचाए रखना बहुत ज़रूरी है. यायावर को इस बात की भी चिंता है कि किस तरह गुंडों, बलात्कारियों की पूछ–परख देश की राजनीति में बढ़ती जा रही है. कविता–मैं वोट हूं में उन्होंने अपनी यह पीड़ा इस तरह बयान की है:–

*मेरी गलियों के चक्कर तुम लगाते थे*
*मुझे विश्वास भी नहीं होता था*
*कि मेरी बेटी के जिस्म पर चढ़कर*
*तुम बलात्कारी, गुंडे बन जाओगे,*
*तब रातोंरात सियासी दलों में*
*महत्व पा जाओगे...*

काव्य संग्रह–दरकती हवाएं में संग्रहित अधिकांश कविताएं नब्बे के दशक की लिखी हुई हैं. यह वह दौर था, जब देश की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थितियां तेजी से बदल रही थीं. विज्ञान का छात्र होने की वजह से विज्ञान के प्रतिमान भी उनकी कविताओं में नज़र आते हैं. बानगी देखिए:–

*मैं हूं दहकता हुआ अंगारा*
*दूर हटो, वरना जल जाओगी*
*तुम स्व–अस्तित्व वंचिता*
*मेरे निज रेडियोएक्टिव*
*प्रकीर्णन के समक्ष*
*ठहर न पाओगी.* ■

feedback@chauthiduniya.com

इस एलईडी लाइट को श्याओमी कंपनी की ऑनलाइन वेबसाइट पर आसानी से खरीदा जा सकता है. अगर आप कभी कमरे में लाइट न होने के कारण अंधेरे में कम्प्यूटर या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, तो कीबोर्ड में एलईडी नहीं होने के कारण टाइप करने में काफी परेशानी होती है. ऐसे में आप श्याओमी की इस एलईडी लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह डिवाइस इतनी लचीली है कि इसे किसी भी तरह से मोड़कर इस्तेमाल किया जा सकता है. श्याओमी का यह एक सुविधाजनक डिवाइस है.

# फिलिप्स ने की नई बॉडी ग्रूमिंग श्रृंखला लांच

भारतीय पुरूषों को फेशियल हेयर का समाधान देने वाली कंपनी फिलिप्स इंडिया अब उन्हें शरीर के दूसरे अंगों पर बालों का समाधान दे रही है. ब्रैंड एम्बेसडर अर्जुन कपूर के साथ फिलिप्स इंडिया ने फिलिप्स बॉडी ग्रूमिंग रेंज़ लांच किया है. यह अनचाहे बाल से छुटकारा दिलाती है. फिलिप्स बॉडीग्रूमिंग श्रृंखला भारतीय पुरूषों की त्वचा के लिए तैयार की गई है. ब्रैंड एंबेसडर और युवा आईकन अर्जुन कपूर ने नई फिलिप्स रेंज़–फिलिप्स बॉडी ग्रूम सीरीज़ 1000 को लांच किया. फिलिप्स बॉडीग्रूम सीरीज़ 1000 छाती और कलाईयों की नियमित ग्रूमिंग के अलावा शरीर के अंदरुनी हिस्सों की ग्रूमिंग भी आसानी से कर सकती है. इन कॉम्पैक्ट टूल्स में बाई–डायरेक्शनल ट्रिमर होता है, जो 0.5 मिमी. तक की ट्रिमिंग करता है. ये खूबसूरत रंगों में उपलब्ध हैं और बैटरी द्वारा संचालित हैं. ये इस्तेमाल करने में काफी आसान हैं. यह बॉडीग्रूम बाज़ार में 3 वैरियंटस में उपलब्ध है, जिसकी क़ीमत 1295 रू से 1495 रूपये तक है. ■

# हीरो मोटोकॉर्प ने लॉन्च की नई पैशन प्रो

भारत की जानी–मानी दो पहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी स्टाइलिश मोटरसाइकिल पैशन का नया और ज्यादा शक्तिशाली वर्जन बाजार में लॉन्च किया है. 97.2 सीसी के एपीडीवी इंजन से लैस नई पैशन प्रो 6.15 केडब्लू ( 8.36 पीएस) एट 8000 आरपीएम का रोमांचक पॉवर आउटपुट और 8.05 एनएम एट 5000 आरपीएम का अधिकतम टॉर्क उपलब्ध करती है. नई बाइक में फ्लश टाइप ईंधन टंकी ढक्कन है, जो इसे सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के साथ ही इसके लुक्स को बेहतर बनाता है. नई पैशन प्रो पॉवर स्टार्ट, फ्रंट साइड काउल और डिजिटल–एनेलॉग काम्बो मीटर के साथ उपलब्ध है. बाइक आठ रंगों ब्लैक स्पोर्ट्स रेड, ब्लैक हैवी ग्रे, ब्लैक फ्रास्ट ब्लू, स्पोर्ट्स रेड, फोर्स सिल्वर, ब्रांज़ येलो और दो बिल्कुल नए रंगों–मैट ब्राऊन और मेजेस्टिक व्हाइट में पेश की गई है. इस नई पैशन प्रो की कीमत 47,850 रुपये रखी गई है. ■

**नई बाइक में फ्लश टाइप ईंधन टंकी ढक्कन है, जो इसे सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के साथ ही इसके लुक्स को बेहतर बनाता है. नई पैशन प्रो पॉवर स्टार्ट, फ्रंट साइड काउल और डिजिटल-एनेलॉग काम्बो मीटर के साथ उपलब्ध है.**

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

# डेल वेन्यू-8 दुनिया का सबसे पतला टैबलेट

कम्प्यूटर और लैपटॉप बनाने वाली मशहूर कंपनी डेल ने भारत में वेन्यू–8 टैबलेट समेत कई प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं. कंपनी का कहना है कि यह टैबलेट दुनिया का सबसे पतला टैबलेट है. इसकी खास बात यह है कि टैबलेट लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 5.0 लॉलीपॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. इस टैबलेट की स्क्रीन 8.4 इंच की फुल एचडी ओलेड है, जो 2560x1600 पिक्सल का रेजोल्यूशन देती है. इसमें 2.3 गीगाहर्ट्ज एटम जेड3580 का क्वाड–कोर प्रोसेसर है. इसमें 2 जीबी डीडीआर3 रैम दी गई है. यह टैबलेट 16 जीबी और 32 जीबी मेमोरी के दो वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 512 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. कंपनी ने इसमें 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 2 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया है. इसमें 5,900 एमएएच की बैटरी है. इसकी कीमत 34,999 रुपये है. ■

# श्याओमी की एमआई एलईडी लाइट

अपने स्मार्टफोन के जरिए भारत में नाम कमाने वाली कंपनी श्याओमी ने एमआई एलईडी लाइट लॉन्च किया है. इस एलईडी लाइट को श्याओमी कंपनी की आन लाइन वेबसाइट पर आसानी से खरीदा जा सकता है. अगर आप कभी कमरे में लाइट न होने के कारण अंधेरे में कम्प्यूटर या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, तो कीबोर्ड में एलईडी नहीं होने के कारण टाइप करने में काफी परेशानी होती है. ऐसे में आप श्याओमी की इस एलईडी लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह डिवाइस इतनी लचीली है कि इसे किसी भी तरह से मोड़कर इस्तेमाल किया जा सकता है. श्याओमी का यह डिवाइस एक सुविधाजनक हैं. यह भारतीयों के लिए किसी तोहफे से कम नही हैं. लैपटॉप से लेकर यूएसबी चार्जर और पावर बैंक तक में लगाकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. श्याओमी की इस एलईडी लाइट की कीमत है 199 रुपये, लेकिन अगर आप साइट से 500 रुपये से कम का सामान खरीदते हैं, तो आपको 50 रुपये अलग से भुगतान करने होंगे. ■

# रेनॉ ने लॉजी प्रीमियम के दो वेरिएंट पेश किए

रेनॉ ने भारतीय बाजार में कार के प्लेटफॉर्म पर विकसित अपनी मल्टी पर्पज व्हीकल (एमपीवी) लॉजी को लॉन्च किया है. रेनॉ ने लॉजी प्रीमियम के दो वेरिएंट लॉजी आरएक्सजेड 110 पी(8 सीट) और लॉजी आरएक्सजेड 110पी (7 सीट) लॉन्च की है. कंपनी ने इनमें 1.5 लीटर क्षमता का के9के(कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन) इंजन दिया है. यह भारत की पहली क्रॉसओवर एमपीवी (कार के प्लेटफॉर्म पर विकसित मल्टी पर्पज व्हीकल) है. लॉजी का इंजन 1461 सीसी का है, जिससे 108 बीएचपी की ताकत और 245एनएम टॉर्क पैदा होता है. रेनॉ की लॉजी प्रीमियम में ऐंटि–लॉक ब्रेक, ब्रेक असिस्ट, डायवर और यात्रियों के लिए एयरबैग, पीछे वायपर और डीफॉगर, पार्किंग का सेंसर, पीछे देखने का कैमरा, सेंट्रल लॉकिंग, पावर स्टीयरिंग और पावर विंडो शामिल हैं. कार का बूट वॉल्यूम 207 लीटर है और इसका फ्यूल टैंक वॉल्यूम 50 लीटर है. इसकी कीमत 11.9 लाख रुपये से 12.29 लाख रुपये रखी है. ■

**यह भारत की पहली क्रॉसओवर एमपीवी (कार के प्लेटफॉर्म पर विकसित मल्टी पर्पज व्हीकल) है. लॉजी का इंजन 1461 सीसी का है, जिससे 108 बीएचपी की ताकत और 245एनएम टॉर्क पैदा होता है.**

# स्टीव स्मिथ क्रिकेट का सुपरमैन

**ऑस्ट्रेलिया ने विश्व क्रिकेट को सर डॉन ब्रैडमैन से लेकर रिकी पांटिंग तक कई महान खिलाड़ी दिए हैं. ऑस्ट्रेलिया के नई पीढ़ी के क्रिकेटरों में स्टीव स्मिथ भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आज वह दुनिया के नंबर एक टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं.**

चौथी दुनिया ब्यूरो

ऑस्ट्रेलिया के भावी कप्तान स्टीव स्मिथ हर दिन सफलता के शिखर पर चढ़ते जा रहे हैं. साल 2010 में एक स्पिन गेंदबाज के रूप में लॉर्डस के ऐतिहासिक मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट पदार्पण करने वाले स्टीव आज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का सबसे चमकता सितारा हैं. एक औसत दर्जे का स्पिन गेंदबाज अचानक से ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम की बल्लेबाजी रीढ़ बन जायेगा, ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था. उनके नाम जितने टेस्ट विकेट(15) हैं उससे ज्यादा शतक और अर्धशतक हैं. इस तरह की अनहोनी कोई सुपरमैन ही कर सकता है. अपने पदार्पण टेस्ट मैच में वह आठवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे और दो पारियों में 8 और 12 रन बनाये थे. मैच की पहली पारी में उन्हें गेंदबाजी का मौका नहीं मिला था लेकिन दूसरी पारी में वह 3 विकेट लेने में सफल हुए थे. करियर की शुरूआत स्टीव ने जीत के साथ की थी. इसके बाद सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में उन्होंने 77 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी और ऑस्ट्रेलिया को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था. पहली पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम महज 88 रनों पर ढ़ेर हो गई थी. साल 2010–11 में उन्हें ऐशेज सीरीज के दौरान तीन टेस्ट खेलने का मौका मिला था. लेकिन इस बार उन्हें टीम में बतौर बल्लेबाज जगह दी गई थी, उन्होंने इस बार छठवें नंबर पर बल्लेबाजी की. सीरीज में उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा और उन्होंने दो अर्धशतक लगाये. इसके बाद अगले 2 साल तक स्मिथ को टेस्ट टीम में जगह नहीं मिल सकी. तीन साल के अंतराल में वह केवल पांच टेस्ट खेल सके थे. साल 2013 के भारत दौरे के लिए उन्हें टीम में शामिल किया गया. यह दौरा उनके करियर का अहम पड़ाव साबित हुआ. मोहाली में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट मैच में स्मिथ ने 92 रनों की पारी खेली. इसके बाद स्मिथ टीम ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के नियमित सदस्य बन गए और एक विशुद्ध बल्लेबाज के रूप में खेलने लगे. 2013 की ऐशेज के आखिरी टेस्ट में उन्हें करियर का पहला टेस्ट शतक बनाने में कामयाबी मिली, इसके बाद स्मिथ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. छोटे से करियर में जिन ऊंचाइयों को स्मिथ ने छुआ है वह काबिले तारीफ है. इसी वजह से आज वह आईसीसी रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंचने में सफल हुए हैं.

स्टीव स्मिथ जैसा कारनामा दो दशक पहले श्रीलंका के खब्बू बल्लेबाज सनथ जयसूर्या भी कर चुके हैं. एक स्पिन गेंदबाज के रूप में क्रिकेट करियर की शुरूआत करने वाले सनथ जयसूर्या ने 1996 के विश्वकप में धमाका कर दिया था. श्रीलंका को विश्व चैंपियन का खिताब दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले जयसूर्या को विश्व कप का मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था. इसके बाद उनके खेल का तरीका ही बदल गया. उन्होंने क्रिकेट के अनगिनत कीर्तिमान अपने नाम किए थे. स्टीव जयसूर्या के दौर की ही याद दिलाते हैं, भले ही उनकी बल्लेबाजी का तरीका जयसूर्या से जुदा है, लेकिन रन बनाने के मामले में वह उनसे कतई पीछे नहीं है. हमवतन स्टीव वॉ ने भी अपने करियर की शुरूआत बतौर गेंदबाज ही की थी, लेकिन समय के साथ वह भी एक बेहतरीन बल्लेबाज बनकर उभरे थे. आज उन्हीं के नक्शेकदम पर स्मिथ चल रहे हैं.

अन्य ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों की तरह आक्रामकता स्टीव का रग–रग में भरी है लेकिन वह

**विश्वकप के बाद वेस्टइंडीज दौरे पर भी स्टीव का बेहतरीन फॉर्म जारी रहा. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ किंग्सटन में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में 199 और 54 रनों की शानदार पारी खेली. इसके बाद वह आधिकारिक रूप से आईसीसी रैंकिंग में कुमार संगकारा को पीछे छोड़ दुनिया के नंबर एक टेस्ट बल्लेबाज बन गए. आईसीसी रैंकिंग में नंबर एक पर पहुंचने वाले वह दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं. सबसे कम उम्र में आईसीसी रैंकिंग में नंबर एक पोजिशन पर सचिन तेंदुलकर पहुंचे थे.**

इस आक्रामकता का इजहार बल्लेबाजी से करते हैं. वे न तो आसानी से हार मानते हैं और न ही अपने प्रतिद्वंद्वियों को कोई मौका देते हैं. पिछले साल स्टीव स्मिथ ने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया. भारत के खिलाफ विश्व कप से पहले खेली गई टेस्ट सीरीज उनके करियर का सबसे अहम मोड़ साबित हुई. पहले तो उन्हें टीम का उप कप्तान बनाया गया. लेकिन माइकल क्लार्क के घायल होने के बाद सीरीज के बाकी तीन टेस्ट मैचों के लिए उन्हें कार्यवाहक कप्तान बना दिया गया. हाथ आए मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए स्मिथ ने टीम का नेतृत्व सामने से किया. उनके खिलाफ भारतीय गेंदबाज पूरी तरह असहाय नज़र आये. पूरा सीजन उनके नाम रहा. स्मिथ ने सीरीज में खेले गए चार टेस्ट मैचों में 128 की औसत से 769 रन बनाये. जिसमें चार शतक शामिल थे. भारत के खिलाफ सफलता के झंडे गाड़ने के बाद उनका शानदार फॉर्म विश्व कप में भी जारी रहा. उन्होंने विश्व कप में आठ मैचों में 67 की औसत से 402 रन बनाये और ऑस्ट्रेलिया को पांचवीं बार विश्व विजेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की.

विश्वकप के बाद वेस्टइंडीज दौरे पर भी स्टीव का बेहतरीन फॉर्म जारी रहा. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ किंग्सटन में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में 199 और 54 रनों की शानदार पारी खेली. इसके बाद आधिकारिक रूप से आईसीसी रैंकिंग में कुमार संगकारा को पीछे छोड़ दुनिया के नंबर एक टेस्ट बल्लेबाज बन गए. आईसीसी रैंकिंग में नंबर एक पर पहुंचने वाले वह दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं. सबसे कम उम्र में आईसीसी रैंकिंग में नंबर एक पोजिशन पर सचिन तेंदुलकर पहुंचे थे. सचिन ने यह उपलब्धि 25 साल 279 दिनों में हासिल की थी, जबकि स्मिथ को यह उपलब्धि हासिल करने में 26 साल, 12 दिन का समय लिया. स्मिथ की यह उपलब्धि उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए काफी है जो उन्हें उनके पिछले सीजन के प्रदर्शन के आधार पर दुनिया का नंबर एक बल्लेबाज मानने से कतरा रहे थे. वह वर्ष 2012 के बाद आईसीसी रैंकिग में पहले पायदान पर पहुंचने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं. उनसे पहले माइकल क्लार्क साल 2012 में टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचे थे.

ऑस्ट्रेलिया में जिस खिलाड़ी को टीम का उप–कप्तान बनाया जाता है, उसमें भविष्य का कप्तान देखा जाता है. स्मिथ भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी इस परीक्षा में सफल रहे. उन्होंने तीन टेस्ट में कप्तानी की. बतौर कप्तान अपने पहले टेस्ट मैच में स्मिथ ने शतक भी बनाया और जीत भी हासिल की. स्मिथ से पहले ऑस्ट्रेलिया के उप–कप्तान की जिम्मेदारी ब्रैड हैडिन के पास थी, लेकिन कप्तान के रूप ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ताओं ने 37 वर्षीय हैडिन की जगह 25 बरस के स्मिथ पर भरोसा जताया. वह किम ह्यूज के बाद ऑस्ट्रेलिया के सबसे युवा कप्तान हैं. किम ने वर्ष 1979 में 25 बरस 57 दिन की उम्र में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी संभाली थी. स्टीव स्मिथ ने माइकल क्लार्क की अनुपस्थिति में टेस्ट में और जॉर्ज बेली की अनुपस्थिति में वन–डे मैच में बतौर कप्तान पहले ही मैच में शतक लगाने का अनोखा रिकॉर्ड स्थापित किया. इसके अलावा उन्होंने चार टेस्ट मैचों में चार शतक लगाने का अनोखा कारनामा भी कर दिखाया. जिनमें से तीन शतक बतौर कप्तान बनाये थे, ऐसा करने वाले वह पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान हैं.

पिछले छह टेस्ट मैचों में दायें हाथ का यह बल्लेबाज पांच शतक और तीन अर्धशतक बना चुका है. पिछली बारह टेस्ट पारियों में उनका औसत 131.5 रहा है. स्मिथ अब तक 28 टेस्ट मैचों की 54 पारियों में 56.23 की औसत से 2,587 रन बना चुके हैं, जिसमें 9 शतक और 11 शतक शामिल हैं. अब वह ऑस्ट्रेलिया के लिए नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हैं. उन्हें टेस्ट टीम में जगह दिलाने वाली गेंदबाजी कहीं पीछे छूट गई है. वेस्टइंडीज में नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए रोक पाना लगभग नामुमकिन था. ऑस्ट्रेलिया के इस भावी कप्तान ने अपनी सफलता का श्रेय हमेशा शांतचित रहने और मैदान–ए–जंग के लिये हमेशा तैयार रहने को दिया है. धैर्य और तैयारी स्मिथ की सफलता का केंद्र बिंदु है, वह हर मैच के लिए तकरीबन एक जैसी तैयारी करते हैं और अधिकांशत: अपने मजबूत पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं. साल 2014 में स्टीव स्मिथ विरोधी टीमों के लिए सबसे कीमती विकेट थे. इस साल उन्होंने 81.86 की औसत से 1,146 रन बनाये. साल 2014 के प्रदर्शन के लिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित क्रिकेट पुरस्कार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया.

एकदिवसीय करियर की शुरूआत स्मिथ ने साल 2010 में मेलबर्न में वेस्टइंडीज के खिलाफ की थी. अपने पदार्पण मैच में स्टीव को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने 9.5 ओवर में 78 रन देकर 2 विकेट लिए थे. अपने पहले एकदिवसीय शतक के लिए स्टीव को 39 वें मैच तक इंतजार करना पड़ा. साल 2014 में शारजाह में स्मिथ ने अपना पहला एक दिवसीय शतक लगाया. अब तक वह 58 एकदिवसीय मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 40.76 की औसत से 1549 रन बनाये हैं. जिसमें 4 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं. साथ ही उन्होंने 27 विकेट भी लिए हैं. स्टीव ने अंतराष्ट्रीय करियर में 13 शतक लगाये हैं. इनमें से एक भी मैच ऑस्ट्रेलियाई टीम नहीं हारी है. वह अपारंपरिक रूप से बल्लेबाजी करते हैं, वह खेल के दौरान पिच पर चहल कदमी करते रहते हैं. उनके खेल का तरीका कुछ–कुछ वेस्टइंडीज के शिवनारायण चंद्रपॉल से मिलता है. भले ही स्मिथ तकनीकी रूप से परिपक्व खिलाड़ी नहीं हैं लेकिन अपने बेहतरीन फुटवर्क, हैंड–आई कॉर्डिनेशन से इसकी भरपाई कर देते हैं. शुरूआत में उन्हें सीमित ओवरों का खिलाड़ी समझा जाता था लेकिन अब वह बेहतरीन टेस्ट खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो चुके हैं. 25 साल की उम्र में ही विश्व चैंपियन का खिताब उनके सिर पर सज चुका है. ऐसे में उनके पास खोने को कुछ नहीं है, स्टीव स्मिथ एक महान खिलाड़ी बनने की राह पर हैं. ऐसे में अगले एक दशक दशक तक वह दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए चुनौती बने रहेंगे.■

navinonline2003@gmail.com

# बॉलीवुड ख़बरें

## सलमान का नया किरदार

**बजरंगी भाईजान में सलमान नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेगम बने दिखाई देंगे, जो कि अपने आप में देखना बेहद दिलचस्प होगा.**

ईद के मौके पर रिलीज होने वाली फिल्म बजरंगी भाईजान में सलमान खान बड़े ही दिलचस्प किरदार में नजर आएंगे. सलमान इस फिल्म में एक महिला के किरदार में भी नजर आएंगे. सलमान ने अब तक के अपने फिल्मी करियर में ऐसा रोल कभी नहीं किया है. बजरंगी भाईजान में सलमान नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेगम बने दिखाई देंगे, जो कि अपने आप में देखना बेहद दिलचस्प होगा. बजरंगी भाईजान फिल्म का आधा हिस्सा पाकिस्तान पर आधारित है. इसलिए उस हिस्से की शूटिंग के लिए सलमान को नवाजुद्दीन की बेगम बनकर बुरका पहनना पड़ा है. सलमान की हर फिल्म की तरह इस फिल्म का भी दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है.■

## बिग-बी का एनीमेटेड अवतार

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अब छोटे पर्दे पर नजर आएंगे. अमिताभ एनिमेटेड सीरीज एस्ट्रा फोर्स में एक सुपर हीरो का किरदार निभाते नजर आएंगे.यह कार्यक्रम डिजनी चैनल पर प्रस्तुत होगा. वैसे तो बिग बी ऐनिमेटेड अवतार में फिल्म महाभारत थ्री–डी में काम कर चुके हैं जिसमें उन्होंने भीष्म पितामह की आवाज़ दी थी, लेकिन अब वो छोटे बच्चों के लिए कार्टून बनने के लिए तैयार हो गए हैं. इसमें एस्ट्रा फोर्स 52 एपिसोड की सीरिज है, यह एक सुदूर दुनिया के एक काल्पनिक नायक की कहानी है, जो लाखों साल पहले हुए अंतरिक्ष युद्ध के बाद धरती में फंस जाता है. यह सीरीज जो कॉमडी, एक्शन और रोमांच से भरपूर होगी. बिग–बी ने बताया कि मुझे यह विचार पसंद आया. मैंने तभी सुनकर हामी भर दी. क्योंकि यह किरदार मेरे जीवन का सबसे अलग किरदार है. आज तक मैंने ऐसा कोई किरदार नहीं किया है. बिग–बी के एनिमेटेड अवतार को देखने के लिए साल 2017 तक इंतजार करना होगा. बिग बी ने कहा कि बच्चों से जुड़ने का यह अच्छा तरीका है.■

## रजनीकांत के साथ काम करेंगी विद्या बालन

**विद्या रजनीकांत की आगामी फिल्म हीरोइन में काम कर सकती हैं. इस फिल्म केलिये उनसे संपर्क किया जा चुका है लेकिन विद्या की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है.**

अभिनेत्री विद्या बालन को लेकर खबरें आ रही हैं कि वे जल्दी ही सुपरस्टार रजनीकांत के साथ काम करती नजर आ सकती हैं. हाल ही में उनकी फिल्म हमारी अधूरी कहानी रिलीज हुई है. इस फिल्म में विद्या के अलावा इमरान हाशमी और राजकुमार राव भूमिका में नजर आए हैं. खबरों के अनुसार विद्या रजनीकांत की आगामी फिल्म हीरोइन में काम कर सकती हैं. इस फिल्म के लिये उनसे संपर्क किया जा चुका है लेकिन विद्या की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है. रजनीकांत इससे पहले दीपिका पादुकोण, सोनाक्षी सिन्हा और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ काम कर चुके हैं. विद्या बालन का कहना है कि वे गंभीर फिल्मों में ज्यादा सहज हैं और उन्हें अब तक हास्य फिल्मों में सफलता पाने का फॉर्मूला नहीं मिला है. वह हमारी अधूरी कहानी में एक गंभीर भूमिका में नजर आई हैं, उनका कहना है कि भावनात्मनक फिल्में करने में उन्हें ज्यादा मजा आता है.■

# दिलीप कुमार को भारत रत्न?

**केंद्र सरकार इस महान अभिनेता को पुरस्कार देकर देश के अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अपनी छवि को बेहतर करने का प्रयास कर रही है. संभव है कि अधिक उम्र और खराब स्वास्थ्य के कारण दिलीप कुमार पुरस्कार लेने राष्ट्रपति भवन तक न जा सकें.**

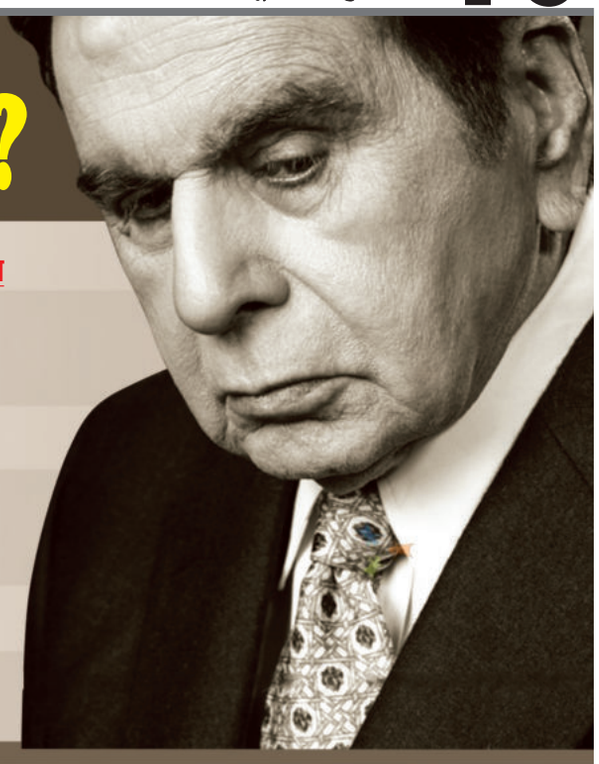

हिंदी सिनेमा के सर्वकालिक सुपरस्टार कहे जाने वाले दिलीप कुमार को भारत रत्न दिए जाने की चर्चा जोरों से चल रही है. फिल्म इंटस्ट्री के लोग इसे लेकर काफी उत्साहित हैं. ऐसा माना जा रहा हैं कि केंद्र सरकार इस महान अभिनेता को पुरस्कार देकर देश के अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अपनी छवि को बेहतर करने का प्रयास कर रही है. संभव है कि अधिक उम्र और खराब स्वास्थ्य के कारण दिलीप कुमार पुरस्कार लेने राष्ट्रपति भवन तक न जा सकें. तो उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह घर पर ही अवॉर्ड से नवाजा जा सकता है. दिलीप कुमार को साल 1991 में पद्म भूषण, साल 1994 में दादा साहब फाल्के और 2015 में पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा जा चुका है.■

# सोनम का जलवा

**इटली में हाइ एन्ड फैशन ब्रांड की लॉन्चिंग में सोनम ने अपने जलवे बिखेरे. इंटरनेशनल ब्रांड बल्गारी ने अपना हाइ जूलरी कलेक्शन रिलीज किया है.**

अभिनेत्री सोनम कपूर का सुर्खियों से पुराना नाता रहा हैं. सोनम के रहन–सहन और फैशन सेंस का बॉलीवुड के साथ–साथ सारा देश फैन है. लोग सोनम को अंतरराष्ट्रीय फैशन आइकन भी मानते हैं. इटली में हाइ एन्ड फैशन ब्रांड की लॉन्चिंग में सोनम ने अपने जलवे बिखेरे. इंटरनेशनल ब्रांड बल्गारी ने अपना हाइ जूलरी कलेक्शन रिलीज किया है. इस मौके पर बल्गारी ग्रुप के सीईओ ज्यां क्रिस्टोफ बेबिन और कार्ला ब्रूनी मौजूद थीं. फ्लोरेंस के विला–डी–मेआनो में गाला डिनर के दौरान जूलरी लॉन्च की गई. इतालवी ऐक्ट्रेस इजाबेल फरारी और जानी मानी हस्तियों के बीच सोनम अकेली भारतीय अभिनेत्री थीं.■

## संजय दत्त की जिंदगी पर फिल्म

बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त की निजी जिंदगी पर एक फिल्म बनने वाली हैं. जिसका निर्देशन राजकुमार हिरानी करेंगे. इस फिल्म में मुख्य भूमिका रणबीर कपूर निभाएंगे. रणबीर ने बताया किसी के जीवन पर आधारित फिल्म में काम करना काफी कठिन होता है. एक बड़े आदमी की असल जिंदगी को दर्शाना होता है. लेकिन मैं संजय दत्त के असली जीवन की कहानी को लेकर काफी उत्साहित हूं और खुश हूं कि इस फिल्म में मेरा अहम रोल होगा और यह अपनें आप में चुनौतीपूर्ण भी है. मेरा रोल काफी दिलचस्प है लेकिन अभी कुछ पक्का नहीं है. अभी हिरानी संजय दत्त की जिंदगी पर पटकथा लिख रहे हैं. इस फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरु होगी.■

## अपना डीएनए बेचेंगी फराह अब्राहम

टीन मॉम की स्टार फराह अब्राहम अपना डीएनए बेचने जा रही हैं. एक खबर के मुताबिक, सेलिब्रिटीजेन डॉट कॉम के साथ साझेदारी करते हुये 24 वर्षीय अभिनेत्री शीशी में अपना डीएनए 99 डॉलर में बेच रही हैं, जिसे गले में पहना जा सकता है. उन्हें डीएनए के नमूने के लिए 30,000 डॉलर अग्रिम राशि दी गई है. और ब्रिकी के बाद इसमें से दस प्रतिशत राशि काट ली जाएगी. अब्राहम की योजना अपनी आमदनी की आधी राशि ऑपरेशन अंडरग्राउंड रेल रोड परमार्थ संस्था को देने की है जो अपहरण किए गए बच्चों को दासत्व से बचाने में मदद करती है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

# चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

## बिहार -झारखंड

29 जून -05 जुलाई 2015 Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

# माननीयों की सदस्यता ख़तरे में!

**हाईकोर्ट में मिथिलेश सिंह की तरफ से याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ वकील दीनू कुमार का कहना है कि राज्यपाल कोटे से जिस तरह से 12 लोगों का मनोनयन हुआ है, उसे कानून के नजरिये से सही नहीं ठहराया जा सकता है. जिस तरह से राजनीति से जुड़े लोगों का मनोनयन हुआ है वह संविधान के अनुच्छेद 175-5 की मूल भावना का उल्लंघन है. दीनू बाबू कहते हैं कि मंत्रिपरिषद को भारत के संविधान में मुख्यमंत्री के अधीन पावर डिलिगेट करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है. अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद ही मनोनयन के लिए अनुशंसा करने के लिए अधिकृत है. दीनू बाबू कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 172 -2 के तहत 12 में से केवल चार चार सदस्यों का हर दो वर्ष के अंतराल में मनोनयन होना चाहिए न कि एक बार ही सभी 12 सदस्यों का मनोनयन. इसलिए अदालत से प्रार्थना की गई है कि इन 12 सदस्यों के मनोनयन को रद्द कर दिया जाए.**

सरोज सिंह

बिहार में राज्यपाल के कोटे से मनोनीत हुए 12 विधान पार्शदों की सदस्यता पर ग्रहण लगने के आसार हैं. मिथिलेश सिंह ने हाई कोर्ट में एक याचिका के माध्यम से इन 12 सदस्यों के मनोनयन को चुनौती दी है. गौरतलब है कि 24 मई को विजय कुमार मिश्रा, राम लखन राम, सम्राट चौधरी, राणा गंगेश्वर सिंह, जावेद इकबाल अंसारी, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, शिवप्रसन्न यादव, संजय कुमार सिंह, ललन कुमार सर्राफ, रणवीर नंदन, रामचंद्र भारती और प्रो. रामवचन राय का मनोनयन बिहार विधान परिषद के लिए राज्यपाल कोटे से किया गया. मिथिलेश सिंह ने हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि नियमों के अनुसार राज्यपाल कोटे से विधान परिषद के लिए मनोनयन में राजनीतिक लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता. ऐसे मनोनयन में साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन और सामाजिक सेवा से जुड़े लोगों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है. उल्लेखनीय है कि दस एमएलसी की सीट नौ मई 2012 से ही खाली पड़ी थी जबकि दो सीट प्रेम कुमार मणि की सदस्यता रद्द होने तथा शंभू शरण श्रीवास्तव के इस्तीफे से खाली हुई थी. इस संबंध में 13 अप्रैल 2012 को ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सूचित कर दिया था. इसके बावजूद इन खाली सीटों को नहीं भरा गया और एक साथ ही सारी सीटों को भरने का फैसला किया गया. इस मामले में एक तथ्य यह भी है कि 19 अप्रैल 2012 को ही मंत्रिपरिषद ने मद संख्या 20 अन्यान्य में यह निर्णय लिया था कि एमएलसी की रिक्त सीटों को भरने के लिए सीएम नीतीश कुमार को अधिकृत किया जाता है. वह इसकी अनुशंसा राज्यपाल को भेज सकते हैं. लेकिन लगभग दो साल तक यह मामला लटका रहा और एक बार फिर 22 मई 2014 को मंत्रिपरिरषद की बैठक में मद संख्या 17 अन्यान्य में मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को राज्यपाल को सिफारिश भेजने के लिए अधिकृत कर दिया गया. इसी आलोक में जीतनराम ने उपरोक्त 12 लोगों की सिफारिश राज्यपाल से की और राज्यपाल ने इसे स्वीकार करते हुए इनका मनोनयन कर दिया. पूरी कार्रवाई में संलग्न नामांकन की पृष्ठभूमि में 12 सदस्यों के नाम के सामने साहित्य, सहकारिता, समाज सेवा और विज्ञान की पृष्ठभूमि बताई गई है, जो सादे कागज पर टाइप किया गया

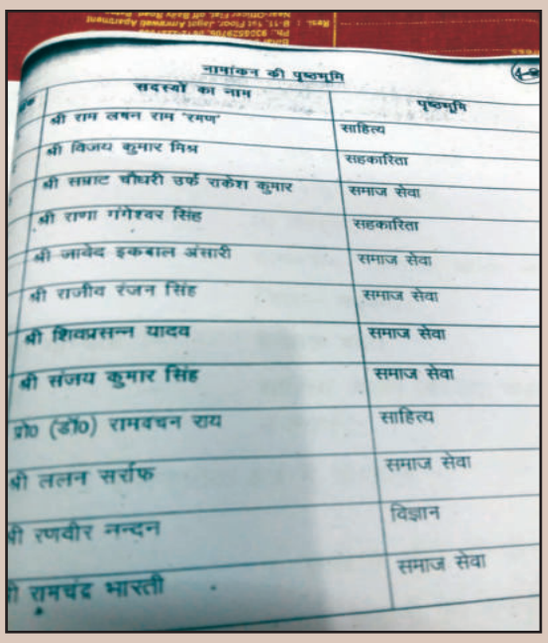

नामांकन की पृष्ठभूमि

| सदस्यों का नाम | पृष्ठभूमि |
|---|---|
| श्री राम लखन राम 'रमण' | साहित्य |
| श्री विजय कुमार मिश्र | सहकारिता |
| श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार | समाज सेवा |
| श्री राणा गंगेश्वर सिंह | सहकारिता |
| श्री जावेद इकबाल अंसारी | समाज सेवा |
| श्री राजीव रंजन सिंह | समाज सेवा |
| श्री शिवप्रसन्न यादव | समाज सेवा |
| श्री संजय कुमार सिंह | समाज सेवा |
| प्रो (डॉ०) रामवचन राय | साहित्य |
| श्री ललन सर्राफ | समाज सेवा |
| श्री रणवीर नन्दन | विज्ञान |
| श्री रामचंद्र भारती | समाज सेवा |

है और इस पर किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है. अपने जीवनवृत्त में अधिकांश नेताओं ने इस बात का जिक्र नहीं किया है कि वह अपने करियर में किस-किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं. उल्लेखनीय है कि उपरोक्त 12 में से रामचंद्र भारती और रणवीर नंदन को छोड़कर बाकी सारे सदस्य एमपी या एमएलए रह चुके हैं. इन बातों का जिक्र बायोडेटा में नहीं दिया गया है. हाईकोर्ट में मिथिलेश सिंह की तरफ से याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ वकील दीनू कुमार का कहना है कि राज्यपाल कोटे से जिस तरह से 12 लोगों का मनोनयन हुआ है, उसे कानून के नजरिये से सही नहीं ठहराया जा सकता है. जिस तरह से राजनीति से जुड़े लोगों का मनोनयन हुआ है वह संविधान के अनुच्छेद 175-5 की मूल भावना का उल्लंघन है. दीनू बाबू कहते हैं कि मंत्रिपरिषद को भारत के संविधान में मुख्यमंत्री के अधीन पावर डिलिगेट करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है. अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद ही मनोनयन के लिए अनुशंसा करने के लिए अधिकृत है. दीनू बाबू कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 172 -2 के तहत 12 में से केवल चार चार सदस्यों का हर दो वर्ष के अंतराल में मनोनयन होना चाहिए न कि एक बार ही सभी 12 सदस्यों का मनोनयन. इसलिए अदालत से प्रार्थना की गई है कि इन 12 सदस्यों के मनोनयन को रद्द कर दिया जाए. इस संबंध में याचिकाकर्ता मिथिलेश सिंह का कहना है कि एमपी एमएलए और मंत्री रह चुके नेताओं ने तथ्यों को अपने बायोडेटा में छिपाया है. अगर ऐसे ही लोग राज्यपाल के कोटे से मनोनीत होते रहेंगे तो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों का क्या होगा. आखिर ऐसे लोगों को सरकार कैसे सम्मानित करेगी या फिर इनका हौसला कैसे बढ़ाएगी? हमने अदालत से प्रार्थना की है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत इस पर ध्यान दिया जाए ताकि समाज में एक मिसाल कायम हो सके. मिथिलेश सिंह कहते हैं कि अभी हाल में ही यूपी के गर्वनर ने सरकार की सूची को लौटाकर एक उदाहरण पेश किया है. वह कहते हैं कि अदालत पर मेरा पूरा भरोसा है और इस मामले में मुझे न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है.■

## कोसी में पप्पू को मुंहतोड़ जवाब देंगे रणवीर यादव

कोसी के इलाके में पप्पू यादव के बढ़ते प्रभाव को रोकने और उनकी हर बयानबाजी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जदयू व राजद गठबंधन ने रणवीर यादव को आगे कर दिया है. मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और पूर्णिया सहित कोसी और सीमांचल के कई जिलों में गहरी पैठ रखने वाले रणवीर यादव और पप्पू यादव एक-दूसरे के लिए नए नहीं हैं. मंडल आंदोलन के दौरान जब पप्पू यादव और आनंद मोहन एक दूसरे के जान के प्यासे बने हुए थे तो उस दौरान रणवीर यादव ने मौके की नजाकत को समझते हुए दोनों के बीच तनाव को काफी कम करवा दिया था. पप्पू यादव ने जब राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा तो उस समय भी रणवीर यादव ने उनकी काफी मदद की. लेकिन जैसे ही पप्पू यादव ने राजद का दामन छोड़ा रणवीर यादव के साथ भी उनके रास्ते अलग हो गए. रणवीर यादव कहते हैं कि पप्पू यादव मंडल की धारा से अलग होकर कमंडल की धारा में चले गए हैं. नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने पिछले दो दशकों से जिस धारा का शोषण किया पप्पू यादव इसी में छेद करने का प्रयास कर रहे हैं. आज अगर समाज के अंतिम पायदान में बैठा आदमी जगा है तो इसका सारा श्रेय लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को जाता है. रणवीर यादव का आरोप है कि पप्पू यादव भाजपा के पे रोल पर काम कर रहे हैं. भाजपा के इशारे पर नाचने वाले पप्पू यादव को यदुवंशी समाज कभी माफ करने वाला नहीं है. रणवीर यादव कहते हैं कि पप्पू वैचारिक विचारधारा से दूर जा चुके हैं और ऐसे शख्स को भरोसे के काबिल नहीं समझा जा सकता है. रणवीर यादव कहते हैं कि कोसी और सीमांचल में सारा यदुवंशी समाज लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के साथ है. आगामी चुनावों में इसका प्रमाण भी लोगों को मिल जाएगा. अपने खुद के बारे में रणवीर यादव कहते हैं कि अगर जनता परिवार का आदेश हुआ तो मैं विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकता हूं. रणवीर का दावा है कि बिहार में अगली सरकार जनता परिवार की ही बनेगी. वे कहते हैं कि जनता परिवार को कम से कम 175 सीटों पर सफलता मिलेगी. उनका आरोप है कि पप्पू यादव को राजनीतिक लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते. जबसे वह सांसद बने हैं कोसी के इलाके में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ गया है. लोगों का जीना मुश्किल हो गया है. लगता है पप्पू यादव अपनी पूरानी कहानी को एक बार फिर दोहरा रहे हैं. रणवीर यादव कहते हैं कि कोसी और सीमांचल की धरती पर यदुवंशियों का वह किसी भी कीमत पर अपमान नहीं होने देंगे. जिस लालू प्रसाद ने पप्पू यादव को आगे बढ़ाया, लोकसभा का टिकट दिया और चुनाव जीतवाया, वह अब उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं. जब पप्पू यादव लालू प्रसाद के नहीं हुए तो वह आम यदुवंशियों के क्या होंगे? ■


feedback@chauthiduniya.com

## एक नज़र

### लालू-नीतीश की होगी हार



भाजपा के वरिष्ठ नेता वरुन सिंह ने कहा है कि बिहार विधान पार्षद चुनाव में सिमांचल के साथ-साथ पूरे राज्य की 24 सीटों पर जीतना तय है. जुलाई में होने वाले इस चुनाव में एनडीए आपसी तालमेल के साथ लड़ रही है और जीत ही नहीं हासिल करेगी बल्कि विरोधियों का सूपड़ा भी साफ कर दिया जायेगा. साथ में उन्होंने कहा की अक्टूबर-नवम्बर में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी, नरेन्द्र मोदी के कार्य, सुशासन और बेहतर प्रशासन के आधार पर बिहार की जनता के सामने जायेगी, और नीतीश कुमार ने जो धोखा हमारे साथ किया है उसका जवाब उन्हें हरा कर और एनडीए का साथ देकर करेगी. वरुण ने कहा कि इस बार का चुनाव पहले के चुनावों से भिन्न है और सभी धर्मनिरपेक्ष दलों द्वारा जदयू और इसके घटक दलों को पराजित करने के लिए सशक्त उम्मीदवार खड़ा किया जा रहा है. **– भारती**

### पंचायतों में लगेंगे बीस-बीस हजार पौधे



मनरेगा के तहत वृक्षारोपण योजना को सफल करने के लिए ढाका प्रखण्ड मनरेगा कार्यालय में एक बैठक एनजीओ ट्राई एण्ड प्रोटेक फीड संस्था के अधीन हुई जिसकी अध्यक्षता मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी शाहनवाज रहमत ने की. बैठक को संबोधित करते हुऐ ट्राई संस्था के जिला समन्वयक कुमार गौरव ने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर मनरेगा के तहत प्रत्येक पंचायतों में 20 हजार पौधे लगाये जायेंगे. यह कार्य तीन फेज में होगा. 6 हजार पौधे सड़क के किनारे, 8 हजार पौधे सामुदायिक भूमि पर और 6 हजार पौधे निजी भूमि पर लगाए जाने का प्रावधान है. इसके लिए प्रत्येक 200 पौधों पर दो वनपोषको का चयन करना है जिन्हें मनरेगा के तहत पांच वर्षो तक 14 सौ रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जायगा. साथ ही पांच वर्षों के उपरान्त दोनों वनपोषक दो सौ में से 50-50 पौधों के फल और तना के आजीवन इत्तराधिकारी भी होंगे. बैठक में मनरेगा के कनीय अभियन्ता नागेन्द्र राम, पीटीए शैलेश कुमार, मुखिया उमाशंकर यादव, राजेश तिवारी, हैदर अली, फारूक आजम, फारूक आलम, जईमुर्रहमान, ओशैद आलम, जौआद हुसैन, नगीना बैठा, एकरामुल हक, विनोद गिरि व अन्य शामिल थे.

### गुमराह कर रहे हैं शाहनवाज



युवा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष ई. शबीह अहमद खां उर्फ मासूम खां ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन पर अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का आरोप लगाया है और कहा है कि किसी भी कीमत पर अल्पसंख्यक समाज भाजपा का साथ नहीं देगा. एक बयान में शबीह अहमद ने कहा कि महागठबंधन के साथ अल्पसंख्यक समाज काफी मुस्तैदी से रहेगा और आगामी चुनाव में भाजपा को यह समाज सबक सिखायेगा. उन्होंने शाहनवाज हुसैन के बयान को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर इतनी पकड़ है तो पटना या मोतिहारी के गांधी मैदान में एक सम्मेलन कराकर देख लें ताकि सभी भ्रम खत्म हो जायें. इस दौरान उन्होंने महागठबंधन की प्रत्याशी कलावती देवी के पक्ष में मतदान करने की अपील अल्पसंख्यक समाज से की है.■

**– इन्तेजारुल हक**




दांत में दर्द

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.



डॉ. सुबोध BDS, PATNA (Dentist)

दांत में दर्द कई कारणों से होता है । कई बार कुछ गलत खाने से भी दांत में दर्द हो जाता है, तो कई बार दांतों की ठीक से सफाई न करने या कीड़े लगने के कारण दांतों में दर्द होने लगता है. दांतों में दर्द का कारण कोई भी हो, लेकिन इसकी पीड़ा आपके लिए बेहद कष्टकारी बन जाती है. मसलन किसी तरह के संक्रमण से या पैरिया की वजह से या इन्फेक्शन के कारण, इन सारी परेशनियों पर अपना विचार रखा है पटना के दंत चिकित्सक डॉ. सुबोध ने। उन्होंने बताया कि मसूढ़े से खून आना दांतों की ठीक से सफाई न करना, एवं किसी दुर्घटना में चोट लगने से भी दांत में दर्द होने का एक कारण हो सकता है । मसूढ़े के उपरी भाग का घिस जाना या फिर चोट के कारण सूजन से भी दांत में दर्द होने की सम्भावना अधिक होती है। ऐसे में डॉ. सुबोध बताते है कि उन मरीजों को अल्ट्रा सोनिक स्केल मशीन से दांतों की सफाई जरुर करनी चाहिए। नियमित सुबह-शाम मुँह की सफाई करनी चाहिए तथा तीन महीने के भीतर अपना टूथ ब्रश को भी अवश्य बदलते रहना चाहिए । इन सब के आलावा नजदीकी डॉ. से परामर्श लें घरेलू और सबसे उत्तम सलाह है कि नियमित रूप से सरसों के तेल में हल्दी और नमक मिलाकर दांतों की मालिश करने से दांत में दर्द की समस्या से आराम मिलता है । आपको चुटकी भर हींग को मौसमी के रस में मिलाकर उसे रुई में लेकर अपने दर्द करने वाले दांत के पास रखने से दांत दर्द से तुरंत आराम मिलता है। एक अन्य घरेलू उपचार में लौंग को उस दांत के पास रखा जाता है जिसमें दर्द होता है। लेकिन दर्द कम होने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है इसलिए इसमें धैर्य की जरुरत होती है। लौंग में औषधीय गुण होते हैं जो बैक्टीरिया एवं अन्य कीटाणु (जर्मस, जीवाणु) का नाश करते हैं। डॉ. सुबोध बताते हैं कि यदि आप कोई भी प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो दर्द की जगह पर गर्म पानी के सेंक देने से भी आपको आराम मिल सकता है।■ रजनीकान्त पाण्डेय



Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.
A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil
Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg
Acoba Syp.
Methylocobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

दरभंगा

# बहादुरपुर विधान सभा क्षेत्र

# मदन सहनी के दावों को हरिनंदन ने नकारा

कुमार विनोद

चुनाव की तैयारी को लेकर मिथिलांचल की धरती पर राजनीतिक बहस शुरू हो चुकी है. 2008 के परिसिमन में 37 पंचायत को मिलाकर बहादुरपुर विधानसभा का गठन किया गया था. इस क्षेत्र में भले ही सभी पार्टियां विकास न होने के नाम पर वोट मांगती हैं, लेकिन इसके पीछे जातीय समीकरण से ये साफ नजर आता है कि महागठबंधन के कारण जातीय वोट बैंक के जो नए ध्रुवीकरण इस क्षेत्र में होगें, उनमें कुछ पुराने दिग्गजों को टिकट कटने की चिंता भी सताने लगी है. परन्तु बहादुरपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक जदयू नेता मदन सहनी अपनी टिकट के लिए पूर्ण आश्वस्त हैं. 2010 के चुनाव मे मदन सहनी राजद के दिग्गज नेता हरिनंदन यादव को हराकर विधानसभा में पहुंचे. विधायक मदन सहनी का कहना है कि पांच वर्षों में हमने जो काम किए हैं, उन्हें लेकर जनता के पास जायेंगे.

उन्होंने बताया कि नीमा बांध, भटानी घाट, मुस्तफापुर (गोठियारी), नेयाम, विशनपुर रुपौली पथ, पिड़री घाट, कोठिया बलुआही कोंकट के पास पुल का निर्माण किया गया, जिससे जनता को एक पंचायत से दूसरे पंचायत में जाने में जो असुविधा होती थी उसकी समाप्ति हुई. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लहेरियासराय जेल से खराजपुर, प्रेम जीवटचौक से कामरान हाई स्कूल, इस्मामठ से कोंकट तक सड़क का निर्माण करवाया.





**हनुमान नगर और इघरा में 2.77 करोड़ की लागत से एक ही विधानसभा क्षेत्र में दो मॉडल स्कूल का निर्माण किया जाएगा. मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत लगभग 10 करोड़ की राशि से 12 पथों का निर्माण करवाया गया. सहनी का कहना है कि जनता से लगातार संपर्क में रहने के कारण हमेशा समाज की भलाई का कार्य किया है. बिहार विधानसभा में भी राज्य की सामाजिक समस्या को रखा गया है, कन्या विवाह योजना में 5000 रुपये से 25000 हजार रुपये करने की मांग की. मल्लाह, नोनिया, बेलदार एवं अन्य कई जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से विधानसभा में प्रश्न किया.**

उन्होंने कहा कि समाज के विकास के लिए आधारभूत संरचना का होना आवश्यक है, इसलिए इस विधानसभा में शिक्षा के विकास पर ध्यान दिया गया. हनुमान नगर और इघरा में 2.77 करोड़ की लागत से एक ही विधानसभा क्षेत्र में दो मॉडल स्कूल का निर्माण किया जाएगा. मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत लगभग 10 करोड़ की राशि से 12 पथों का निर्माण करवाया गया. सहनी का कहना है कि जनता से लगातार संपर्क में रहने के कारण हमेशा समाज की भलाई का कार्य किया है. बिहार विधानसभा में भी राज्य की सामाजिक समस्या को रखा गया है, कन्या विवाह योजना में 5000 रुपये से 25000 हजार रुपये करने की मांग की. मल्लाह, नोनिया, बेलदार एवं अन्य कई जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से विधानसभा में प्रश्न किया. शिवधारा को प्रखण्ड बनाने की दिशा में प्रयास किया गया तो दूसरी तरफ सैदनगर में खुदरा मछली मंडी निर्माण के लिए गैर सरकारी संकल्प के तहत विधान सभा में प्रश्न उठाया.

इस विकास कार्य के साथ इस कर्याकाल में कुछ और न कर पाने का अफसोस भी है. हनुमान नगर में जल समस्या का समाधान पर्णतः नहीं किया जा सका जबकि दो साल पूर्व सोरमारहाट हायाघाट तटबंध पर पंचफूटिया स्थल पर हेड रेगुलेटर लगाने का आदेश दिया जा चुका था. इस विधान सभा में फेकला चौक में सौन्दर्यीकरण करना था संग ही भोला पासवान शास्त्री की मूर्ति लगानी थी, जिसे इस कार्यकाल में नहीं कर सका.

इस विधानसभा क्षेत्र के जदयू के विरोधी ने इस विकास को एकदम नकार दिया. 2010 चुनाव के आरजेडी प्रत्याशी हरिनंदन यादव ने कहा कि किस्मत से विधायक बन गये हैं, इसलिए सिर्फ उन्होंने अपना विकास किया है इसी चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. मुरारी मोहन झा ने कहा कि इस क्षेत्र में विकास की कोई बात नहीं है. यह महागठबंधन भी विकास के नाम पर न होकर जाति के नाम पर हुआ.■

feedback@chauthiduniya.com

# फतुहा में यादवी महाभारत के आसार

रजनीकांत पांडेय

बिहार में चुनावी हलचल को देखते हुए सभी उम्मीदवार अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं. फतुहा विधानसभा यादव बहुल क्षेत्र है. मौजूदा विधायक रामानंद यादव अपनी जीत के लिए सम्पर्क साधने में जुटे हैं. इसी को देखते हुए फतुहा विधानसभा क्षेत्र से कर्मठ एंव युवा उम्मीदवार सुजीत कुमार यादव अपनी जीत को निश्चित बनाने के लिए अपने क्षेत्र के मतदाताओं के बीच लगातार जनसम्पर्क अभियान चला रहे हैं. इस विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग दो लाख है. जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए यहाँ के उम्मीदवार अपनी जीत के लिए मतदाताओं के बीच अपनी गुहार लगाते रहे हैं. इस बार इस क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण एंव जातीय समीकरण पहले की अपेक्षा थोड़ी बदली है. ऐसे में यहां से युवा एवं अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हो रहे सुजीत कुमार यादव अपने क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में पूरा ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं .

इस विधानसभा क्षेत्र में इस बार यादव वोट पर कांटे की टक्कर होने की संभावना है. जिस तरह से युवा नेता सुजीत कुमार यादव जनसभाएं कर रहे हैं उससे मौजूदा विधायक रामानंद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. फतुहा विधानसभा क्षेत्र में जातीय वोट के समीकरण से ही पार्टियों व नेताओं को सफलता मिलती रही है . लेकिन कोई दल या नेता जननेता के रूप में अपनी विशिष्ट छवि नहीं बना सके है. इस विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग दो लाख है, जिसमें यादव जाति का वोट लगभग एक लाख पच्चीस हजार है.

वहीं अन्य बिरादरी के वोटों की संख्या में राजपूत तीस हजार हैं, अनुसूचित जाति का वोट पन्द्रह हजार है, अतिपिछड़ा (मुसहर) के तीन हजार वोट हैं, वहीं ठाकुर, कहार के दो- दो हजार वोट है, धानुक के पांच हजार तो साव जाति के वोट लगभग सोलह हजार हैं, तथा अन्य बिरादरी के करीब दो हजार के लगभग वोट हैं. अब ऐसे में यहां जातीय उम्मीदवार और जननेता के तौर पर ही प्रत्याशी के जीतने की संभावना है. सुजीत के साथ फतुहा विधानसभा क्षेत्र के गणमान्य लोग जन भागीदारी में साथ खड़े हैं उससे सुजीत की छवि को काफी बल मिलता दिख रहा है. सुजीत के साथ पासवान बिरादरी से लाल बाबू पासवान (सोनारू फतुहा), दिलीप पासवान, लोजपा नेत्री विमला देवी (महारानी चौक फतुहा) कमलेश पासवान (समसपुर फतुहा) हैं . वहीं यादव जाति से राज नारायण सिंह यादव, विन्नी यादव, शिवशंकर प्रसाद (फतुहा) है. तो दलित बिरादरी से अनिल राम (संसपुर फतुहा) और मोजिपुर के वार्ड सदस्य ब्यास जी हैं. इसके आलावा सुजीत को राजनितिक सफर का काफी लम्बा अनुभव रहा है और जनहित में भी देखा गया है. सुजीत किसान परिवार से आते हैं जिससे वह किसानों की हित की बात अधिक करते हैं . सबसे खास बात इनकी यह है की इन्होनें अपने कम से फतुहा विधानसभा क्षेत्र में अच्छी पकड़ बना रखी हैं. 2005 में जदयू के सक्रिय सदस्य रह कर पार्टी और क्षेत्र में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है. 2010 के चुनाव में जदयू के सीट के होड़ में सबसे आगे नाम सुजीत का था. लेकिन पार्टी ने इनका टिकट काट कर अजय कुमार सिंह को मैदान में उतारा था जिससे जदयू को फतुहा विधानसभा सीट गवानी पड़ी थी.■





feedback@chauthiduniya.com

# अन्य ख़बरें

### रवि महोत्सव का आयोजन



सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में रवि महोत्सव का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन बीडीओ नीरज आनंद ने किया. मौके पर कार्यशाला में किसानों को धान खेती की नवीनतम जानकारी दी गयी. मौके पर बीएओ रवींद्र कुमार चौधरी, अनिल कुमार सिंह, आशुतोष कुमार पाठक, प्रेमचंद, सुधीर कुमार व पंसस भूपेंद्र नारायण सिंह समेत अन्य थे. **– विभा**

### नौ साल बाद भी नहीं टपका पानी



गर्मी का मौसम परवान पर है. तपती धूप व पछुआ हवा में भी जलमीनार से लोगों के हलक को पानी नसीब नहीं हो पा रहा है. वर्ष 2006-2007 में पीएचईडी विभाग द्धारा लाखों रुपये की लागत से प्रखंड मुख्यालय में जलमीनार का निर्माण कर महेशखूंट-अगुवानी पीडब्लूडी सड़क के किनारे बाजार सहित रहीमपुर मोड़ आदि प्रखंड मुख्यालय के इर्द गिर्द पाइप लाइन, जल स्तम्भ आदि लगाकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पानी की तरह पैसे बहाये गये. लेकिन विडंबना यह है कि निर्माण कार्य शुरू होने के नौ साल बाद भी जलमीनार से प्यासे हलक तर नहीं हो रहे हैं. यह सिर्फ जलमीनार का ही सवाल नहीं है. विभाग द्धारा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में लगाए गए चापाकल बन्द होकर मिस्त्री का इन्तजार कर रहे हैं. लोक स्वास्थ्य अभिकरण विभाग द्धारा जगह-जगह बड़े व मोटे अक्षरों में लिखे गए स्लोगन जल ही जीवन है यहां जलमीनार को देखकर दिवा स्वप्न बनकर रह गया है. **– गीता कुमार**

### हेल्थ शिविर का आयोजन




गया के आईएमए हॉल में अयोजित हेल्थ शिविर में 125 लोगों का इलाज किया गया. इस शिविर में डायबिटिज, हाई बल्ड प्रेशर, हाइपर टेंशन ,हृदयाघात जैसी बीमारी से ग्रसित लोगों का इलाज किया गया. मरीजों का वीएमडी टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट, फिजियोथयोरपी, ईसीजी आदि जांच भी हुई. इसके अलावा दांत व आंख के मरीज का भी इलाज किया गया. इस शिविर के संयोजक थे डॉ. विजय करण, इसमें डॉ. पीके सिन्हा, डॉ. आर कुमार, डॉ एल एल अरुण, डॉ. रामभजन प्रसाद, डॉ सरिता कुमारी, डॉ रविन्द्र कुमार, डॉ एल एम सिंह, उमेश वर्मा अदि ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया. **– सुनील सौरभ**

# गोविन्दगंज विधानसभा क्षेत्र

# दावेदारों में टिकट को लेकर संशय

**गोविन्दगंज विधान सभा क्षेत्र को ब्राह्मण बहुल क्षेत्र माना जाता रहा है. यही कारण है कि लगभग सभी पार्टियां यहां ब्राह्मण उम्मीदवार को तरजीह देती रही हैं. 1951 से 2010 तक हुए 16 विधानसभा चुनाव में 13 बार ब्राह्मण उम्मीदवारों ने जीत हासिल की हैं, लेकिन अब स्थिति बदलने लगी है. अन्य जातियों की संख्या बढ़ी है. चुनाव में भी इनकी भागीदारी बढ़ी है. अरेराज, पहाड़पुर और संग्रामपुर प्रखण्ड से निर्मित इस क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 4,20,057 है. मतदाताओं की संख्या 2,35,122 है, जिसमें पुरुष 1,28,710 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 1,06,410 है.**

राकेश कुमार

गोविन्दगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनावी समर में उतरने के लिए कई दिग्गज कवायद कर रहे हैं, लेकिन पार्टियों के गठबंधन के बाद सभी अपनी उम्मीदवारी को लेकर सशंकित नजर आ रहे हैं. वर्तमान में गोविन्दगंज की विधायक जदयू की मीना द्विवेदी हैं. उनके अलावा जदयू के टिकट के अन्य दावेदार भी हैं. भाजपा के दो पूर्व एवं वर्तमान जिलाध्यक्ष सहित वरिष्ठ एवं युवा नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं. इस सीट पर साल 2000 के चुनाव में एक बार लोक जनशक्ति पार्टी का भी कब्जा रहा है. यही कारण है कि भाजपा इस सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है. कांग्रेस के भी दो दावेदार चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. जबकि राजद से टिकट के लिए दो दावेदार ताल ठोंकते नजर आ रहे हैं. गोविन्दगंज विधान सभा क्षेत्र को ब्राह्मण बहुल क्षेत्र माना जाता रहा है. यही कारण है कि लगभग सभी पार्टियां यहां ब्राह्मण उम्मीदवार को तरजीह देती रही हैं. 1951 से 2010 तक हुए 16 विधानसभा चुनाव में 13 बार ब्राह्मण उम्मीदवारों ने जीत हासिल की हैं, लेकिन अब स्थिति बदलने लगी है. अन्य जातियों की संख्या बढ़ी है. चुनाव में भी इनकी भागीदारी बढ़ी है.

अरेराज, पहाड़पुर और संग्रामपुर प्रखण्ड से निर्मित इस क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 4,20,057 है. मतदाताओं की संख्या 2,35,122 है, जिसमें पुरुष 1,28,710 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 1,06,410 है.

क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी के साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य मूल समस्या है. गंडक नदी के कारण बाढ़ की समस्या से एक बड़ा क्षेत्र प्रभावित रहता है. क्षेत्र की जनता मानती है कि उन्हें हमेशा जनप्रतिनिधियों ने ठगा ही है. वर्तमान विधायक मीना द्विवेदी ने भी क्षेत्र के विकास में कुछ खास योगदान नहीं किया है. वर्तमान विधायक जदयू की हैं और सेटिंग-गेटिंग के आधार पर टिकट को लेकर आश्वस्त हैं, जबकि जदयू का ही दूसरा गुट मानता है कि पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण उनके टिकट पर संशय बना हुआ है. उधर रतन सिंह जदयू की जोरदार दावेदारी में लगे हैं. वे गुजरात मे निर्माण कम्पनी चलाते हैं, जहां क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं को रोजगार मुहैया कराया है. आम जनता के सुख-दुख में शामिल रहने के कारण लोकप्रिय हैं. उन्हें जदयू-राजद गठबंधन के स्थानीय नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है. बकौल रतन सिंह अगर पार्टी से टिकट नहीं मिलता है, तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे.





















भाजपा से पूर्व जिलाध्यक्ष चन्द्रकिशोर मिश्र दावेदारी कर रहे हैं. वर्तमान में प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य चन्द्रप्रकाश ने अपनी दावेदारी को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, प्रदेश प्रभारी अनंत सिंह और धर्मेंद्र प्रधान से भेंट कर अपनी दावेदारी रखी है. उन्होंने बताया कि पूर्वी चम्पारण में 7.95 प्रतिशत ब्राह्मण हैं, अगर इस बार भी टिकट नहीं मिलता तो ब्राह्मण भाजपा का साथ छोड़ देंगे. वही शांत स्वभाव और पार्टी में साफ सुथरी छवि के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता भी चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं. लेकिन पार्टी नेताओं के अनुसार चलने वाले राजेंद्र अभी चुप हैं और नेतृत्व के फैसले के इंतजार में हैं. अरेराज के प्रमुख अनिल राय भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. रढ़िया राय टोला निवासी अनिल राय की सभी वर्ग में अच्छी पकड़ है. लम्बे समय से समाजिक कार्यों में जुटे रहने के कारण उन्हें जमीनी नेता माना जाता है. इधर भाजपा के युवा नेता मुन्ना गिरि भी चुनावी दंगल में ताल ठोंकने के मूड में नजर आ रहे हैं. नगदाहा सेवा समिति के संस्थापक मुन्ना प्रत्येक वर्ष गरीब कन्याओं के सामुहिक विवाह का आयोजन करते हैं. वर्तमान जिला अध्यक्ष सुनील मणि तिवारी भी पूर्व से ही गोविन्दगंज सीट से चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं.

अरेराज नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष व वर्तमान वार्ड पार्षद धर्मेंद्र कुमार दूबे उर्फ मन्टू दूबे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं. नगर परिषद में रहते हुए क्षेत्र में कराये गये विकास कार्यों के कारण वे खासे लोकप्रिय हैं. वे किस पार्टी का दामन थामेंगे अभी तक इसका खुलासा नहीं किया है. जानकारों की मानें तो राजद एव हम पार्टी में उनकी मजबूत पकड़ है. क्षेत्र में कांग्रेस हासिये पर है लेकिन वरिष्ठ कांग्रेसी जय प्रकाश पाण्डेय भी चुनाव की तैयारी में लगे हैं. साफ-सुथरी छवि के जय प्रकाश तीन बार चुनाव लड़ चुके हैं. उन्होंने बताया कि अगर पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो जनता की मांग पर वे निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं. इधर कांग्रेस नेता ई. शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय भी पार्टी टिकट के दावेदार हैं. राजद से कृष्ण मिश्र पार्टी के प्रबल दावेदार है. वे राजद के बड़े नेताओं के करीबी माने जाते हैं. वे तीन बार से लगातार मलाही से जिला पार्षद हैं. गोविन्दगंज से लोक जनशक्ति पार्टी के राजन तिवारी साल 2000 के विधान सभा चुनाव में विजयी हुए थे. फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005 के चुनाव में वे जदयू की मीना द्विवेदी से हार गये. वे भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. गठबंधन के कारण पार्टियों के भावी प्रत्याशियों में टिकट की होड़ मची हुई है. लेकिन इतना तो तय है कि टिकट नहीं मिलने की स्थिति में कई नेता बगावत पर उतरेंगे और निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या में इजाफा होगा. वहीं आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच होने वाले संभावित गठबंधन की ओर भी कई नेता देख रहे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

# हिंदू हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं हम

*बिहार में चुनावी हलचल को देखते हुए सभी दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं. इस हलचल में अखिल भारत हिन्दू महासभा एक लंबे अंतराल के बाद पुनः बिहार में अपने संगठनात्मक प्रसार के लिए प्रयास करती दिख रही है. अखिल भारत हिन्दू महासभा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी. उक्त बातें अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्री उपाध्यक्ष राकेश रंजन ने कही है, कि प्राचीनतम राजनैतिक संगठनों में से एक हैं, एवं भारत की प्रथम राजनैतिक दल अखिल भारत हिन्दू महासभा के लिए बिहार सदैव दृष्टि केंद्र में रहा है परंतु कालचक्र के क्रम में संगठन अपेक्षाकृत संकुचित हो गया था, जिसका कुपरिणाम बिहार में अत्याधिक प्राबल्य के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है. राकेश रंजन ने बताया कि सूबे में हिंदुओं की बहुसंख्या के उपरांत भी यहां की क्षेत्रीय राजनीति हिंदू जनता को जातियों में बांट कर आपस में लड़ा रही है,और उसका सीधा सीधा लाभ तथाकथित अल्पसंख्यक शक्तियां उठा रही है. हिन्दू महासभा इसकी मुखर रूप से निंदा करती है. उनका मानना है कि बहुसंख्यक होने के बावजूद हिंदुओं के हित प्रभावित हो रहे हैं. प्रस्तुत है राकेश रंजन से बातचीत के कुछ अंश*

रजनीकांत पाण्डेय



**आप हिन्दू हित की अनदेखी की बात कह रहे हैं, और यहां स्वयं को हिन्दू राष्ट्रवादी कहने वाली भाजपा नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक सत्ता मे रही है, क्या वो हिन्दुओं का हित नहीं बचा पाए?**

सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि स्वयं को हिन्दुवादी कहने वाली और हिन्दू मतों पर एकाधिकार समझने वाली भाजपा के संविधान तक में हिन्दूहित का कोई उल्लेख नहीं है. वह हिन्दूहित की रक्षा क्या करेगी? भाजपा हिंदुओं को मूर्ख समझती है, उसे हिंदुओं का मत चाहिये, हिंदुओं से मोटा चंदा चाहिये पर उसे हिन्दूहित में कोई कार्य नहीं करना है. वो अन्य राजनीतिक दलों से भी अधिक संवेदना शून्य एवं सेक्युलर हो जा रही हैं. एक तरफ वो हिंदुओं को लगातार झूठे आश्वासन देती रहती है, पर करती कुछ भी नहीं है और दूसरी तरफ मजहब-ए-खास के अक़लियतों को हर प्रकार के सुविधाओं से नवाजा जाता है चाहे वो हिंदुओं के अधिकार छिन कर ही क्यों न दिया जाए बिहार कि बात करें तो उसी भाजपा की भागीदारी वाली सरकार ने यहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा खोल दी पर हिन्दू ज्ञान विज्ञान और दर्शन के लिए क्या किया? बिहार सरकार ने अरबी फ़ारसी जैसी विदेशी भाषा एवं संस्कृति के लिए अलग से विश्वविद्यालय खोला और हिंदुओं द्वारा दिये गए कर से उनका पोषण किया परंतु वेद, धर्म एवं दर्शन की शिक्षा के लिए क्या किया?

**राम मंदिर के विषय में हिन्दू महासभा का क्या दृष्टिकोण है? क्या आप भाजपा के साथ नहीं है?**

राम जन्म भूमि के मुकदमे में अखिल भारत हिन्दू महासभा तो पक्षकार पार्टी है और उसके विपक्ष में सुन्नी वक्फ बोर्ड है. भाजपा न तो इस केस में पार्टी है. 1947 के पहले भी और आजादी के बाद भी रामलला विराजमान की पैरोकार केवल और केवल हिन्दू महासभा रही है. उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में तीन न्यायाधीशों का निर्णय हिन्दू महासभा के पक्ष मे आया था पर उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता था. सर्वोच्च न्यायालय मे भी केवल अखिल भारत हिन्दू महासभा ही पार्टी है. संघ परिवार का कोई सदस्य वहाँ नहीं है. हिंदुओं को यह समझना होगा की भाजपा केवल हिंदुओं को मूर्ख बना कर उनके आस्था का दोहन कर चुनाव जीतती रही है, न तो उसने राम मंदिर के पक्ष में आज तक किसी प्रकार का सार्थक संघर्ष किया है और न उसकी इच्छा मंदिर निर्माण की है.

**इसका अर्थ यह नहीं है कि आप बिहार मे हिन्दु महासभा के पक्ष में अर्थात भाजपा के खिलाफ एक अभियान चालने वाले हैं.**

हिन्दू महासभा कभी नकारात्मक राजनीति नहीं करती है और न हीं अन्य दलों की तरह सत्ता प्राप्ति के लिए ओछी राजनीति करती है, अतः हम भाजपा के खिलाफ अभियान नहीं चला रहे अपितु सत्य से अवगत करा रहे है. अगर उजागर करने लगें तो भाजपा के हिन्दू द्रोह कि सूची बहुत लंबी है.

यह समय कि मांग है और बिहार के हिंदुओं कि मांग है कि अखिल भारत हिन्दु महासभा बिहार विधान सभा के निमित होने वाले निर्वाचन मे समस्त सीटों पर चुनाव लड़े अतः हमारी केंद्रीय कार्यकारणी ने सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया है कि पार्टी बिहार विधान सभा के सभी सीटों पर अखिल भारत हिन्दु महासभा के प्रत्याशी ला कर मतदाताओं को सत्य के पक्ष मे एक विकल्प प्रदान करेंगी और उन्हे लालू-नीतीश के जंगल राज के साथ साथ भाजपा के पाखंड से भी मुक्ति दिलायेगी. इस प्रक्रिया में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश कौशिक के नेतृत्व मे प्रदेश के पदाधिकारियों को साथ ले कर एक कार्य समिति का गठन किया गया है और प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गयी है, कुछ 27-28 सीटों पर उचित प्रत्याशी का चयन भी हो गया है जिसकी घोषणा आगामी कुछ दिनों में कर दी जाएगी शेष सभी सीटों पर निर्णय चरणबद्ध प्रक्रिया के अंतर्गत शीघ्र ले लिया जाएगा.■

## एक नज़र

### भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन




सीतामढ़ी जिले में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है. पिछले दिनों बाजपट्टी व रुन्नीसैदपुर प्रखंड मुख्यालय में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के मौके पर पार्टी नेताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए लोगों से भाजपा के पक्ष में एकजुट होने की अपील की. उच्च विद्यालय बाजपट्टी में प्रखंड भाजपा अध्यक्ष संजय मिश्र की अध्यक्षता एवं विधानसभा प्रभारी संजीव चौधरी के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के शाहनवाज हुसैन, देवेशचंद्र ठाकुर व देवेंद्र साह समेत हजारों पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे. वहीं रुन्नीसैदपुर में सरस्वती शिशु मंदिर में मंडल अध्यक्ष युगल किशोर गुप्ता की अध्यक्षता व विकास शर्मा के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में गोपालगंज के सांसद जनक चमार, सोनपुर विधायक विनय कुमार सिंह, प्रो. वीरेंद्र प्रसाद सिंह, घनश्याम ठाकुर, उमेश यादव, विधानसभा समन्वयक प्रबोध कुमार सिंह, अरविंद ठाकुर, पल्लवी प्रियदर्शी, शशिनाथ सिंह, गिरिजानंदन प्रसाद यादव, ब्रह्म प्रसाद शाही, मुखिया रामबाबू सहनी, मुनींद्र साह, अरुण कुमार गुप्ता, रंजन कुमार सिंह, विजय सिंधिया, सुधीर रंजन वर्मा व अजय कुमार समेत अन्य थे.

**– अभिलाषा**

### बस स्टैंड चालू करने की मांग तेज



गोगरी अनुमंडल स्थित महेशखूंट बस स्टैण्ड चालू करने की मांग तेज होने लगी है. महेशखूंट आसाम रोड चौंक पर वाहन की ठोकर लगने से एक साइकिल सवार युवक की मौत घटनास्थल पर हो जाने से फिर एक बार महेशखूंट के स्थायी बस स्टैण्ड को चालू करने की मांग जन प्रतिनिधियों ने उठाना शुरू कर दिया है. कांग्रेस सेवादल के जिलाध्यक्ष प्रकाश मिश्रा, भाजपा नेता सुजीत कुमार राणा एवं जदयू नेता चंदन कश्यप के अलावा विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों ने कहा कि महेशखूंट में स्थायी बस स्टैंड उपलब्ध है लेकिन प्रशासन के उदासीनता के कारण इसे चालू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रषासन की इदासीनता के कारण आज छोटे व बड़े वाहनों का ठहराव आसाम रोड चौक पर किया जा रहा है. जिस कारण हमेषा दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है. बस स्टैंड चालू करने के लिए कई बार डीएम एवं एसडीओ द्वारा निरीक्षण भी किया गया है. लेकिन आज तक बस स्टैंड चालू करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है. अगर बस स्टैंड चालू हो जाता है तो आसाम रोड चौक पर दुर्घना की भय से लोगों को निजात मिल जाती. वहीं एसडीओ संतोष कुमार ने कहा कि प्रशासनीय स्तर पर बस स्टैंड चालू करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है. ■

**– गीता कुमार**

पिछले अंक से आगे

**SBI PO PHASE 1 REASONING TEST**



सुबोध कुमार, Director
S.T.C., Motihari

1. शहर D शहर F के पूर्व में है. शहर B शहर D के उत्तर में है. शहर H शहर B के दक्षिण में है. शहर F के संबंध में शहर H किस दिशा में है. :-
a) पूर्व b) दक्षिण-पूर्व c) उत्तर-पूर्व d) डाटा अपर्याप्त e) इनमे से कोई नहीं

2. अशोक दक्षिण की तरफ चलना प्रारंभ करता है. 50 मीटर चलने के बाद वह दाई तरफ मुड़ता है तथा 30 मीटर चलता है. उसके बाद वह दाई तरफ मुड़ता है तथा 100 मीटर चलता है. वह फिर दाई तरफ मुड़ता है तथा 30 मीटर चल कर रूक जाता है. वह अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में तथा कितनी दूर है. :
a) पचास मी. दक्षिण b) 150 मी. उत्तर c) 180 मी. पूर्व d) 50 मी. उत्तर e) N-t-

3. एक निश्चित कूट भाषा में TEMPORAL को OLDSMBSP लिखा जाता है. उसी कूट भाषा में CONSIDER को कैसे लिखा जायेगा.
a) RMNBSFEJ b) BNMRSFEJ c) RMNBJEFS d) TOPDQDCH e) N-t

4. एक निश्चित कूट भाषा में how many goals scored को 5397 लिखा जाता है, many more matches को 982 लिखा जाता है तथा he scored Five को 163 लिखा जाता है. उस कूट भाषा में goals को कैसे लिखेंगें:
a) 5 b) 7 c) 5 या 7 d) डाटा अपर्याप्त e) n-t

5. **कथन:** सभी कप बोतल है. कुछ बोतल जग है. कोई जग प्लेट नहीं है. कुछ प्लेट मेज है.
**निष्कर्ष:** i) कुछ मेज बोतल है. ii) कुछ प्लेट कप है. iii) कोई मेज बोतल नहीं है. IV) कुछ जग कप है.
a) केवल I अनुसरण करता है. b) केवल II अनुसरण करता है. c) केवल III अनुसरण करता है. d) केवल IV अनुसरण करता है. e) या तो I या III

6. **कथन:**- सभी पक्षी घोड़े हैं. सभी घोड़े बाघ हैं. कुछ बाघ शेर हैं. कुछ शेर बंदर हैं.
**निष्कर्ष.** (I)- कुछ बाघ घोड़े हैं. (II) कुछ बंदर पक्षी हैं. (III) कुछ बाघ पंक्षी हैं. (IV) कुछ बंदर घोड़े हैं.
a) केवल I और III अनुसरण करते हैं. b) I, II और III अनुसरण करते हैं. c) II, III और IV अनुसरण करते हैं. d) I, II, III और IV अनुसरण करते हैं. e) उपरोक्त में से कोई नहीं.

7. **कथन:**- कुछ कुर्सियां हैंडल हैं. सभी हैंडल बर्तन हैं. सभी बर्तन चटाईयां है. कुछ चटाईयां बसें हैं.
**निष्कर्ष**- (I)-कुछ बसें हैंडल हैं. (II)- कुछ चटाईयां कुर्सियां हैं. (III)- कोई बस हैंडल नहीं हैं. (IV)- कुछ चटाईयां हैंडल है.
a) I, II, IV अनुसरण करते है. b) II, III, IV अनुसरण करते हैं. c) या तो I या III और II अनुसरण करते है. d) या तो I या III और IV अनुसरण करते है. e) या तो I या III और II और IV अनुसरण करते है.

8. कुछ घड़ियां लैंप हैं. कुछ फूल लैंप हैं. कुछ लैंप परिधान हैं. सभी परिधान कमीजें हैं.
**निष्कर्ष**- (I)- कुछ कमीजें घड़ियां हैं. (II)- कुछ कमीजें फूल हैं. (III)- कुछ फूल घड़ियां हैं. (IV)- कुछ परिधान घड़ियां है.
a) कोई अनुसरण नहीं करता b) केवल I अनुसरण करता है. c) केवल II अनुसरण करता है. d) केवल III अनुसरण करता है. E) केवल IV अनुसरण करता है.

A, B, C, D, E, F, G और H एक संस्था के आठ कर्मचारी हैं. जो तीन विभागों यथा कार्मिक, प्रशासन व विपणन विभाग में इस तरह काम करते हैं कि किसी एक विभाग में तीन से ज्यादा नहीं है. इनमे से प्रत्येक को फुटबाल, क्रिकेट, बालीबाल, बैडमिंटन, लान टेनिस, बास्केट बाल और टेबुल टेनिस में से कोई एक भिन्न खेल पसंद है. लेकिन जरूरी नहीं कि उसी क्रम में.
D प्रशासन में काम करता है और फुटबाल या क्रिकेट पसंद नहीं करता. F कार्मिक विभाग में केवल A के साथ काम करता है, जिसे टेबुल टेनिस पसंद है. E व H उस विभाग में काम नहीं करते जिसमें D करता है. C को हाकी पसंद है और वह विपणन में काम नहीं करता. G प्रशासन में काम नहीं करता और न तो क्रिकेट न ही बैडमिंटन पसंद करता है. इनमे से एक जो प्रशासन में काम करता है, उसे फुटबाल पसंद है. जिसे वालीबाल पसंद है, वह कार्मिक में काम करता है. प्रशासन में काम करने वालों में से किसी को भी बैडमिंटन या लान टेनिस पसंद नहीं है. H को क्रिकेट पसंद नहीं है.

9. निम्न में से कर्मचारियों का कौन सा समूह प्रशासन विभाग में काम करता है.
a) EGH b) AF c) BCD d) BGD e) डाटा अपर्याप्त

10) E किस विभाग में काम करता है.
a) कार्मिक b) विपणन c) प्रशासन d) डाटा अपर्याप्त e) n-t ■

शेष अगले अंक में

## सीतामढ़ी-समस्तीपुर

# संकट में अच्छे दिन के सिपाही

**करीब एक साल पहले देश की आम-आवाम को अच्छा दिन आने का सुनहरा सपना दिखाने वाली भाजपा का अब खुद ही बुरे वक्त से पाला पड़ने वाला है. ऐसा नहीं कि जनता ने पार्टी नेतृत्व को नकार दिया है, बल्कि इसलिए कि पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की मनमानी से समर्पित कार्यकर्ताओं की भावना अब आह भरने लगी है. सीतामढ़ी व समस्तीपुर के स्थानीय निकाय से विधान परिषद के पार्टी समर्थित प्रत्याशी को लेकर दोनों ही जिले की राजनीति में मचे धमाल से इस बात के साफ संकेत आने लगे हैं कि अब इन जिलों में भाजपा के बुरे दिन आने लगे हैं. प्रदेश नेतृत्व पर आम पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनमानी राजनीति का आरोप लगाते हुए आसन्न चुनाव में सबक सिखाने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है. राजनीतिक चौपालों पर चल रही चर्चा में अगर तनिक भी सच्चाई है तो निश्चित तौर पर आसन्न चुनाव से भाजपा के लिए संकट का दौर शुरू होने वाला है.**

वाल्मीकि/अमृता

पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी सभाओं में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी रहे नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को भरोसा दिया था कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं. चुनाव बाद बहुमत की बदौलत केंद्र में सरकार की कमान थामने वाली भाजपा महज कुछ ही महीनों में राज्यों की सत्ता पर अपनी उम्मीद भरी नजरें जमानी शुरू कर दी. आनन-फानन में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी नेताओं ने धुआंधार चुनावी पारी खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन जो नतीजे आए, उसने उम्मीदों पर पानी फेर दिया. अब बारी बिहार में होने वाली विधान परिषद व विधानसभा चुनाव की है. विधानसभा चुनाव में तो अभी विलंब है, लेकिन विधान परिषद चुनाव सिर पर है. बिहार में वैसे तो दलगत आधार पर विधान परिषद चुनाव की परंपरा नहीं रही है, मगर हाल के दशक में अब इसे भी पार्टी समर्थित चुनाव बना दिया गया है. नतीजा है कि सभी दल से प्रत्याशियों की लंबी कतारें लगने का दौर भी शुरू हो गया है. राजनीतिक दलों के गठबंधन का आलम यह है कि अब कई दलों के संभावित प्रत्याशियों को अपने अरमानों की बेवक्त अर्थी सजानी पड़ रही है. इसका असर गठबंधन दल के घोषित प्रत्याशियों के चुनाव पर पड़ने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है.

**समस्तीपुर जिला का सवाल है तो यहां की स्थिति भी भाजपा के लिए खतरनाक संकेत दे रहा है. बताया जाता है कि भाजपा की ओर से पार्टी कार्यकर्ता राजीव रंजन कुमार लंबे समय से अपनी दावेदारी को लेकर जिले के अलग-अलग स्थानों पर विकास कार्यों का श्रीगणेश कर लोगों के बीच मजबूत पहचान बनाने का हर संभव प्रयास किया है, लेकिन हाल में कांग्रेस के पूर्व विधान पार्षद हरि नारायण चौधरी को भाजपा में आयात कर उन्हें समस्तीपुर से स्थानीय निकाय चुनाव में प्रत्याशी घोषित कर दिया गया. नतीजतन पार्टी के बागी प्रत्याशी के रूप में राजीव रंजन ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में ताल ठोंकना शुरू कर दिया है. बताया जाता है कि पार्टी नेतृत्व के इस फैसले से जिले के भाजपा कार्यकर्ता दो खेमे में बंट गए हैं. एक खेमा आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी की खातिर चुप है तो दूसरा खेमा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राजीव की चुनावी नैया पार लगाने में जी-जान से लग गया है.**

सीतामढ़ी जिला में भाजपा के निवर्तमान विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद लंबे समय से विधानसभा चुनाव में इस बार भाग्य आजमाने की मंशा से विधान परिषद का चुनाव नही लड़ने की योजना पर अग्रसर रहे हैं. अंतिम समय में हां और ना के बाद प्रदेश नेतृत्व ने भाजपा विधायक सुनील कुमार पिंटू के करीबी माने जा रहे डुमरा प्रखंड प्रमुख देवेंद्र साह को चुनाव मैदान में उतार दिया है. इसे लेकर अब चर्चा यह होने लगी है कि जिला में पार्टी की खराब स्थिति और अपने खिलाफ माहौल से घबरा कर श्री प्रसाद ने ऐसा निर्णय लिया है. सच्चाई चाहे जो हो, लेकिन इतना तो तय है कि भाजपा के वर्तमान प्रत्याशी के लिए चुनावी राह आसान नहीं है. कारण कि पार्टी के अंदर चल रही पूर्व की गुटबाजी भी इस चुनाव में अपनी औकात दिखाने से बाज नहीं आएगी.

अब प्रत्याशियों पर की जा रही चर्चा से कई बातें सामने आने लगी हैं. चर्चा है कि सीतामढ़ी से स्थानीय निकाय के विधान परिषद चुनाव के भाजपा समर्थित प्रत्याशी ने हाल के वर्षों में ही पार्टी की विधिवत सदस्यता ग्रहण की है, लेकिन आर्थिक स्तर पर उन्हें काफी मजबूत माना जा रहा है, जिसके कारण उनकी दावेदारी पर पार्टी का प्रदेश नेतृत्व ने मुहर लगा दी है, जबकि जदयू से पूर्व घोषित प्रत्याशी राजेश चौधरी को पार्टी के गठबंधन धर्म की रक्षा की खातिर अपनी दावेदारी की शहादत देनी पड़ी है, लेकिन उनके समर्थक अंतिम क्षण तक साथ निभाने का संकल्प व्यक्त कर रहे हैं. उनकी जगह पर राजद के प्रदेश युवा उपाध्यक्ष दिलीप राय को राजद-जदयू-कांग्रेस गठबंधन से चुनावी समर में उतारा गया है. हाल यह है कि गठबंधन के निर्णय से जदयू के कार्यकर्ता फिलहाल खफा हैं. राजनीतिक स्तर पर इनके जख्म पर मरहम लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है. अब राजद गठबंधन प्रत्याशी अपनी चुनावी नौका पार लगाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं. इनके अलावा बतौर निर्दलीय प्रत्याशी अमिताभ गुंजन भी अपनी जीत सुनिश्चित कराने को लेकर कुछ भी करने को तैयार हैं. अब कौन कितना वोट बटोर पाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं. चर्चा चल रही है कि चुनाव के दौरान वोटों की खरीद-फरोख्त को लेकर तकरीबन सभी प्रत्याशियों ने अपनी तिजोरी खोल दी है.

जहां तक समस्तीपुर जिला का सवाल है तो यहां की स्थिति भी भाजपा के लिए खतरनाक संकेत दे रहा है. बताया जाता है कि भाजपा की ओर से पार्टी कार्यकर्ता राजीव रंजन कुमार लंबे समय से अपनी दावेदारी को लेकर जिले के अलग-अलग स्थानों पर विकास कार्यों का श्रीगणेश कर लोगों के बीच मजबूत पहचान बनाने का हर संभव प्रयास किया है, लेकिन हाल में कांग्रेस के पूर्व विधान पार्षद हरि नारायण चौधरी को भाजपा में आयात कर उन्हें समस्तीपुर से स्थानीय निकाय चुनाव में प्रत्याशी घोषित कर दिया गया. नतीजतन पार्टी के बागी प्रत्याशी के रूप में राजीव रंजन ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में ताल ठोंकना शुरू कर दिया है. बताया जाता है कि पार्टी नेतृत्व के इस फैसले से जिले के भाजपा कार्यकर्ता दो खेमे में बंट गए हैं. एक खेमा आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी की खातिर चुप है तो दूसरा खेमा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राजीव की चुनावी नैया पार लगाने में जी-जान से लग गया है. नतीजतन पार्टी के बागी प्रत्याशी के रूप में राजीव रंजन ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में ताल ठोंकना शुरू कर दिया है. बताया जाता है कि पार्टी नेतृत्व के इस फैसले से जिले के भाजपा कार्यकर्ता दो खेमे में बंट गए हैं. एक खेमा आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी की खातिर चुप है तो दूसरा खेमा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राजीव की चुनावी नैया पार लगाने में जी-जान से लग गया है. सभी अपनी जीत सुनिश्चित कराने को लेकर हर संभव प्रयास कर रहे हैं. अब देखना है कि इस चुनाव में विकास का मार्ग प्रशस्त होता है अथवा वोटों की खरीद-फरोख्त के बीच फिर से विकास योजनाओं के व्यापारी को एक मौका मिलता है. चुनावी चौपालों पर जाति-पार्टी से लेकर अन्य मसलों की चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है.■

feedback@chauthiduniya.com

## गया

# राजद-जदयू से भाजपा को मिलेगी कड़ी चुनौती

**पिछले चुनाव में जदयू-भाजपा गठबंधन ने दस मे से नौ पर कब्जा जमा लिया था, सिर्फ एक सीट पर राजद को सफलता मिली थी, लेकिन वर्तमान राजनीतिक समीकरण में भी गया जिले के जदयू के कब्जे वाले विधानसभा क्षेत्र में तो भाजपा को कड़ी चुनौती मिलेगी ही, वहीं भाजपा के कब्जे वाले विधानसभा क्षेत्रों पर भी राजद-जदयू-कांग्रेस गठबंधन से पार्टी को कड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद है. जदयू के कब्जे वाले इमामगंज, शेरघाटी, बाराचट्टी, टिकारी, अतरी क्षेत्रों में तो भाजपा को एक-एक वोट के लिए काफी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी. इमामगंज से विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, शेरघाटी से विनोद यादव (मंत्री), बाराचट्टी से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की समधिन ज्योती देवी, अतरी से कृष्ण नंदन यादव जदयू के विधायक हैं.**

सुनील सौरभ

बिहार विधानसभा चुनाव की समय सीमा जैसे-जैसे निकट आ रही है राजनीतिक दलों में बेचैनी बढ़ती जा रही है. इस चुनाव से पहले तो बिहार राज्य में कई नए राजनीतिक दल बने हैं लेकिन मुख्य चुनावी मुकाबला तो बड़े राजनीतिक दलों के बीच ही होने की उम्मीद है.

साल 2010 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव मे गया जिले के दस विधानसभा क्षेत्रों में से पांच पर जदयू, चार पर भाजपा तथा एक पर राजद की जीत हुई थी. तब भाजपा का जदयू से तो राजद का लोजपा से तालमेल था. इस बार समीकरण उल्टा हो गया है. इस बदले समीकरण में दोनो गंठबंधन में कौन मजबूत होगा, यह तो विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा, लेकिन जो स्थिति बन रही है उसमें गया जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को राजद-जदयू-कांग्रेस गठबंधन से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा.

पिछले चुनाव में जदयू-भाजपा गठबंधन ने दस मे से नौ पर कब्जा जमा लिया था, सिर्फ एक सीट पर राजद को सफलता मिली थी, लेकिन वर्तमान राजनीतिक समीकरण में भी गया जिले के जदयू के कब्जे वाले विधानसभा क्षेत्र में तो भाजपा को कड़ी चुनौती मिलेगी ही, वहीं भाजपा के कब्जे वाले विधानसभा क्षेत्रों पर भी राजद-जदयू-कांग्रेस गठबंधन से पार्टी को कड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद है. जदयू के कब्जे वाले इमामगंज, शेरघाटी, बाराचट्टी, टिकारी, अतरी क्षेत्रों में तो भाजपा को एक-एक वोट के लिए काफी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी. इमामगंज से विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, शेरघाटी से विनोद यादव (मंत्री), बाराचट्टी से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की समधिन ज्योती देवी, अतरी से कृष्ण नंदन यादव जदयू के विधायक हैं. टिकारी से जदयू के अनिल कुमार हैं, जो अब जीतन राम मांझी पार्टी हम में हैं. बेलागंज से मगध सम्राट के नाम से मशहूर डॉ. सुरेन्द्र प्रसाद यादव राजद विधायक 1990 से लगातार जीत रहे हैं. जबकि बोधगया से भाजपा के श्याम देव पासवान, गुरुआ से सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, गया नगर से डॉ. प्रेम कुमार, वजीरगंज से भाजपा के वीरेन्द्र सिंह विधायक हैं. इन सभी सीटों पर भाजपा को काफी परेशानी होगी. जीतन राम मांझी की हम पार्टी के भाजपा के साथ आ जाने के कारण भाजपा को मांझी वोट मिलने की संभवना है. गया जिले में राजद-जदयू-कांग्रेस में कई बड़े नेता हैं जिनमें उदय नारायण चौधरी व राजद के सुरेन्द्र प्रसाद यादव एक मजबूत स्तंभ माने जाते हैं, लेकिन भाजपा-लोजपा-रालोसपा में डॉ. प्रेम कुमार एक मजबूत नेता हैं. दिक्कत यह है कि प्रेम कुमार का उनकी पार्टी में ही बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है. वे जनाधार के कारण नही जीतते हैं.

वैसे तो गया के भाजपा सांसद हरि मांझी, औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, विधान पार्षद कृष्ण कुमार सिंह, जहानाबाद के सांसद डॉ. अरुण कुमार राजग की मजबूत कड़ी माने जा रहे हैं, लेकिन पूर्व सांसद रामजी मांझी, पूर्व सांसद राजेश कुमार मांझी, कांग्रेस के पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह, जय कुमार पालित समेत राजद के कई पूर्व विधायक गया में चुनाव के समय बड़ी अहमियत रखते हैं. ऐसे में यह कहना गलत नहीं होग कि गया जिले के सभी दस विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा गठबंधन को राजद-जदयू-कांग्रेस गठबंधन से कड़ी चुनौती का समाना करना पड़ेगा, क्योंकि स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक मतदाताओं का झुकाव भी राजद-जदयू-कांग्रेस गठबंधन की ओर होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

# बदलूंगा चकाई की तस्वीर- नेपाली सिंह

तरुण मिश्रा

बिहार विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही चकाई में भी राजनीति गरमाने लगी है.एक तरफ जहां वर्तमान विधायक सुमित कुमार सिंह का भाजपा के साथ मिलने के कारण उत्साह बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, वहीं अन्य उम्मीदवार अपने वायदों का पिटारा लेकर मैदान में कूदने लगे हैं.

इसी सिलसिले में पिछले चुनाव में राकपा के उम्मीदवार नेपाली सिंह ने अपने वादों का पिटारा खोला. जहां एकतरफ उन्होंने पहले के विधायकों पर विकास नहीं करने का आरोप लगाया, वहीं दूसरी ओर वर्तमान विधायक पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चकाई को चंडीगढ़ बनाने की बात करने वाले पहले चकाई के लोगों की मूलभूत असुविधाओं को दूर करें. उन्होंने कहा कि यहां के किसानों की एक इंच भी जमीन को सिंचित बनाने का प्रयास नहीं किया गया. साथ ही वरनार जलाशय योजना पर यहां के नेताओं ने केवल राजनीति की है और अगर मुझे इस क्षेत्र में सेवा करने का अवसर मिला तो मैं इस योजना को मंजिल तक पहुंचा कर ही दम लूंगा.

पिछले चुनाव में आठ हजार से अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार नेपाली सिंह पूरे जोश एवं उत्साह में दिखाई पड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इस बार परिवारवाद एवं जातिवाद के दलदल से निकल कर वोट देगी. गौरतलब है कि चुनाव की आहट के साथ ही पूर्व प्रत्याशियों की मजबूत आहट चकाई विधानसभा क्षेत्र में सुनाई देने लगी है. इसके साथ ही साथ अन्य प्रमुख उम्मीदवारों को हल्के में आंकने की भूल आत्मघाती साबित हो सकती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

# चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

29 जून –05 जुलाई 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

## उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

सभी फोटो – विनय गुप्ता

### स्वास्थ्य निदेशालय अग्निकांड: बाबू सिंह कुशवाहा और प्रदीप शुक्ला को बचाने की साजिश तो नहीं!

# साक्ष्य जलकर ख़ाक

प्रभात रंजन दीन

स्वास्थ्य भवन में पिछले दिनों लगी भीषण आग में बड़ी तादाद में महत्वपूर्ण फाइलें और दस्तावेज जल कर राख हो गए. यह आगजनी पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और वरिष्ठ आईएएस प्रदीप शुक्ला को बचाने की साजिशों का नतीजा तो नहीं! सवाल के लहजे में लिखी हुई यह बात दरअसल अग्निकांड के रहस्यों के जवाब में स्वास्थ्य विभाग के ही आला अधिकारियों की फुसफुसाहटों पर आधारित है. नेशनल रूरल हेल्थ मिशन (एनआरएचएम) के हजारों करोड़ के घोटाले में फंसे पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और वरिष्ठ नौकरशाह प्रदीप शुक्ल समेत कई लोग जेल में हैं. लेकिन कुशवाहा और शुक्ला सत्ता के खास हैं और मुलायम के प्रिय हैं. एनआरएचएम घोटाले के सिलसिले में लखनऊ के कई सीएमओ की हत्या हो चुकी है और एक डिप्टी सीएमओ को तो जेल में ही मार डाला गया था. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कहते हैं कि स्वास्थ्य भवन में लगी या लगाई गई आग में स्वास्थ्य विभाग के अन्य घोटालों के अलावा एनआरएचएम घोटाले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज भी खाक हो गए. स्वास्थ्य निदेशालय में लगी भीषण आग में एनआरएचएम घोटाले के दस्तावेजों के स्वाहा होने की खबर भड़के और सीबीआई से इसकी जांच की मांग हो, उसके पहले ही सरकार ने मामले की स्पेशल टास्क फोर्स से जांच की घोषणा कर दी, लेकिन सरकार भी जानती है कि खाक हो चुके और फायर ब्रिगेड की बौछार में बह चुके मलबे के निशान पर लकीर पीटने के अलावा एसटीएफ को कुछ भी नहीं मिलने वाला.

लखनऊ के कैसरबाग स्थित स्वास्थ्य भवन की दूसरी मंजिल पर पांच अहम कमरों में 14 जून की रात भीषण आग लगी. आग ने उन पांच कमरों को इस तरह अपनी चपेट में ले लिया कि एक दर्जन से अधिक दमकलकर्मी भी देर रात तक आग नहीं बुझा पाए. इस रहस्यमय अग्निकांड में चिकित्सा अनुभाग और वित्त अनुभाग में रखी महत्वपूर्ण फाइलें, घोटालों और इससे जुड़ी अदालती कार्यवाहियों के दस्तावेज, कम्प्यूटर और उसमें रखे जरूरी रिकॉर्ड्स जल कर राख हो गए. जल कर खाक हुई फाइलों में एनएचआरएम घोटाले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज होने की पूरी आशंका है. स्वास्थ्य भवन के दूसरे माले पर स्वास्थ्य विभाग का महत्वपूर्ण वित्त और लेखा विभाग है. विचित्र किंतु सत्य यह है कि स्वास्थ्य निदेशालय बंद रहने पर उसकी बिजली की सप्लाई भी बंद कर दी जाती है. 14 जून की रात को निदेशालय में आग लगी. उस दिन रविवार था. शनिवार 13 जून को भी दफ्तर में छुट्टी थी. जब बिजली से आग लगने की कोई गुंजाइश ही नहीं, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आग लगी नहीं, बल्कि लगाई गई थी. किसी ने कहा कि घटनास्थल पर रविवार की रात को दो लोग आए थे, लेकिन इस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य भवन में लगी आग की जांच एसटीएफ को सौंप दी है. यह रेखांकित करने वाला तथ्य है कि अग्निकांड की जांच का आदेश घटना के तीन दिन बाद 17 जून को जारी हुआ. इसकी सफाई में मुख्यमंत्री सचिवालय के एक अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आग लगने के अगले ही दिन आग लगने के कारणों की जानकारी मांगी थी, लेकिन तीन दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया. इसके बाद मुख्यमंत्री ने 17 जून को मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी.

सरकार को यह पता ही नहीं कि स्वास्थ्य भवन में लगी आग में कौन-कौन सी फाइलें जलीं. स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक इस सम्बन्ध में आधिकारिक तौर पर कोई भी सूचना नहीं दी है कि इस आग में कितनी फाइलें नष्ट हुईं और वे कितनी महत्वपूर्ण थीं. जबकि विभाग के ही अधिकारी कहते हैं कि कोई फाइल बची ही नहीं. कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि जान बूझकर एक षडयंत्र के तहत आग लगाई गई थी, जिससे स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार से जुड़ी सारी फाइलें नष्ट हो जाएं. कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार से एनआरएचएम घोटाले से सम्बन्धित फाइलों और दस्तावेजों की अद्यतन स्थिति के बारे में जवाब देने को कहा है. स्वास्थ्य निदेशालय के कुछ कर्मचारी कहते हैं कि आगजनी में तबादले और तैनातियों के साथ-साथ भर्ती से जुड़ी सैकड़ों फाइलें भी जलकर खाक हो गई हैं. भर्ती घोटाले की तमाम फाइलों का पता नहीं चल रहा है. प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने विभागीय अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य भवन में लगी आग का जायजा लेने की औपचारिकता पूरी की. उन्होंने विभागीय अफसरों से सवाल भी पूछे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. स्वास्थ्य मंत्री के साथ स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार और सीएमओ डॉ. एसएनएस यादव समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद थे. स्वास्थ्य विभाग की निदेशक डॉ. विजय लक्ष्मी ने बाद में कहा कि अग्निकांड की तीन स्तर से जांच कराई जा रही है. मामले की पुलिस छानबीन कर ही रही है, साथ ही फाइलों की सूची व आग लगने के कारण का पता लगाने के लिए एक विभागीय जांच कमेटी भी बनाई गई है. फायर ब्रिगेड भी मामले की जांच कर रहा है. लेकिन बाद में मुख्यमंत्री ने घटना की सम्पूर्ण जांच एसटीएफ को सौंप दी.

एक अधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य निदेशालय में लगी आग में फार्मासिस्टों का रिजल्ट और अदालत में लंबित चल रहे कई घोटालों की फाइलें और दस्तावेज जल कर नष्ट हो गए. यह स्पष्ट रूप से षडयंत्र की तरफ इशारा करती है. स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्टों की भर्ती के लिए काउंसलिंग के बाद रिजल्ट तैयार किया गया था. सोमवार 15 जून को ही रिजल्ट घोषित किया जाना था, लेकिन रविवार को ही उस कमरे में भी आग लगी जिसमें रिजल्ट और काउंसलिंग के दस्तावेज रखे थे. इस आशंका में बल है कि फार्मासिस्ट भर्ती में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया था और सबूत मिटाने के लिए आग लगाई गई. इसके अलावा अन्य कमरों में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज और एनआरएचएम समेत कई अन्य घोटालों से जुड़ी वे पत्रावलियां भी खाक हो गईं, जिनकी सुनवाई अदालत में लंबित है. आग लगने से पत्रावलियों, दस्तावेजों और फाइलों के अलावा कम्प्यूटर भी जलकर राख हो गए, जिनमें कई संवेदनशील रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए थे. ■


feedback@chauthiduniya.com


## घोटाले करो, आग लगाओ

पिछले आठ महीने में राजधानी लखनऊ स्थित चार महत्वपूर्ण महकमों में आग लगने की घटना घटी, जिसमें सारे जरूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड्स जल कर खाक हो गए. अभी 14 जून को स्वास्थ्य निदेशालय में लगी आग सुर्खियों में है, लेकिन पिछले ही महीने 10 मई को बहुमंजिला मिनी सचिवालय जवाहर भवन स्थित बाल विकास पुष्टाहार विभाग के दफ्तर में आग लगी थी. यह विभाग भी भ्रष्टाचार का केंद्र माना जाता है. लिहाजा, दस्तावेजों और फाइलों के नष्ट होने का मतलब और उसकी वजह के बारे में आप समझ ही सकते हैं. इसी साल 29 मार्च को छावनी स्थित भारतीय स्टेट बैंक की सदर शाखा में लगी भीषण आग ने ग्राहकों का दिल दहला दिया था. बैंक के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स और कम्प्यूटर में दर्ज आंकड़े नष्ट हो गए. बैंक के कर्मचारी ही कहते हैं कि लोन से सम्बद्ध घोटालों और अन्य अनियमितताओं के दस्तावेज अग्निकांड में नष्ट हो गए. बीते साल 12 अक्टूबर 2014 को लखनऊ के निशातगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय के दफ्तर में लगी आग आज भी लोगों की पेशानी पर बल देती है. उस अग्निकांड में भी क्या-क्या जला और क्या-क्या बचा, इसका आधिकारिक ब्यौरा आज तक नहीं मिल पाया. ■

## बसपा-काल के घोटालेबाज आज सपा के करीबी

एनआरएचएम घोटाले के अभियुक्त वरिष्ठ आईएएस प्रदीप शुक्ला और उनकी पत्नी आईएएस आराधना शुक्ला सपा नेता मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी हैं. इस घोटाले के अन्य अभियुक्त पूर्व बसपा नेता बाबू सिंह कुशवाहा भी मुलायम के इतने करीबी हो गए थे कि उनकी पत्नी सुकन्या कुशवाहा को उन्होंने न केवल समाजवादी पार्टी में शामिल कराया, बल्कि उन्हें गाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दे दिया था. सपा नेता शिवपाल सिंह डासना जेल में बंद प्रदीप शुक्ला और बाबू सिंह कुशवाहा से कई बार जेल जाकर मुलाकात भी कर चुके हैं. दोनों की जेल से रिहाई की कोशिशें भी समानान्तर चलती रही हैं. स्वास्थ्य निदेशालय अग्निकांड में एनआरएचएम घोटाले से सम्बद्ध दस्तावेजों के भी स्वाहा होने की चर्चा है. एक बार फिर से याद करते चलें कि उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत करीब 5500 करोड़ रुपये के घोटाले को अंजाम दिया गया था. घोटाले में पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, अनंत कुमार मिश्रा, आईएएस अफसर प्रदीप कुमार शुक्ला, पूर्व डीजी हेल्थ एसपी राम, पैक्सफेड के एमडी वीके चौधरी, चीफ इंजीनियर एमएम त्रिपाठी, इंजीनियर एके श्रीवास्तव, सौरभ जैन समेत कुछ अन्य नेता और वरिष्ठ अधिकारी सक्रिय रूप से शामिल थे. इस घोटाले में कई लोगों की हत्याएं भी हुईं. हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर इसकी जांच सीबीआई को दी गई. पूर्व सरकार की मुख्यमंत्री और ऐसा कोई मंत्री नहीं था, जिसने इस घोटाले में कमाई नहीं की. सीबीआई कोर्ट ने इस घोटाले के प्रमुख सूत्रधार पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और वरिष्ठ आईएएस प्रदीप शुक्ला समेत नौ लोगों पर आरोप तय किए. एनआरएचएम के तहत सीबीआई ने 76 एफआईआर दर्ज की. इनमें करीब 52 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं. पांच मामलों में प्रदीप शुक्ला व बाबू सिंह कुशवाहा अभियुक्त हैं. बाबू सिंह कुशवाहा, प्रदीप शुक्ला के अलावा पूर्व स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. एसपी राम, दवा कारोबारी सौरभ जैन, सुनीत सिंघल, एसएम त्रिपाठी, विपुल कुमार गुप्ता, अतुल श्रीवास्तव और वीके चौधरी भी आरोप पत्र में शामिल हैं. सभी आरोपियों पर करोड़ों रुपये की दवा व मेडिकल उपकरण की खरीद फरोख्त में घोटाला करने का आरोप है. सभी अभियुक्तों पर भारतीय दंड विधान की धारा 120-बी, 420, 467, 468, 471, 13 (2) और 13 (1) (डी) के तहत मुकदमा चल रहा है. ■

## कबूलनामा है डीजी हेल्थ का पत्र

अग्निकांड के बाद स्वास्थ्य निदेशालय अपनी झेंप मिटाने की कोशिशों में हास्यास्पद हरकतें कर रहा है. स्वास्थ्य महानिदेशक का एक हास्यास्पद आदेश पत्र भी ऐसी ही हरकतों में शुमार है. अग्निकांड में घपलों-घोटालों से जुड़े दस्तावेजों और फाइलों के अलावा अनुशासनिक कार्रवाइयों से सम्बद्ध दस्तावेज भी जल कर नष्ट हो गए. अब स्वास्थ्य महानिदेशक प्रदेशभर के स्वास्थ्य कर्मचारियों को पत्र लिख कर अनुशासनिक कार्रवाइयों के कागज मांग रहे हैं. जिन कार्रवाइयों के प्रमाण खाक हो गए, उनके ब्यौरे देकर कर्मचारी क्या अपनी ही शामत फिर से बुलाएं? स्वास्थ्य महानिदेशक के इस निर्देश पर विभाग के कर्मचारी ही यह बात कर रहे हैं. कितनी विचित्र स्थिति है कि जो दस्तावेज जल गए, उन्हें फिर से जुटाने की कवायद के नाम पर ऐसे निर्देश जारी किए जा रहे हैं. महानिदेशक की तरफ से यह पत्र प्रदेश के सभी अतिरिक्त निदेशक, सीएमओ, स्वास्थ्य प्रधानाचार्य, परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, सीएमएस महिला व पुरुष जिला अस्पताल, अपर निदेशक मलेरिया, अपर निदेशक राज्य विधि विशेषज्ञ, संयुक्त निदेशक मातृ व शिशु कल्याण परिवार निदेशालय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, संयुक्त निदेशक राज्य स्वास्थ्य संस्थान उप्र लखनऊ, बलरामपुर, लोहिया, रानी लक्ष्मी बाई, लोकबंधु, टीबी अस्पताल सहित कई अन्य सम्बद्ध महकमों को भी लिखा लिखा गया है. पत्र में कहा गया है कि अज्ञात कारणों से लगी आग से अभिलेख जल गए हैं. कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावलियां फिर से बनाए जाने के लिए उनसे जुड़े अभिलेख तैयार किए जाएं और कोर्ट केस व उनसे जुड़ी कार्यवाही का ब्यौरा भी तैयार किया जाए. कर्मचारियों की नियुक्ति आदेश से लेकर अब तक की सारी कार्रवाई से जुड़ी पत्रावलियां भी फिर से बनवाने को कहा गया है. यानी, स्वास्थ्य महानिदेशक ने इस पत्र के जरिये यह स्वीकार कर लिया है कि अग्निकांड में समस्त सरकारी दस्तावेज जल कर खाक हो गए. यह आने वाले दिनों में स्वास्थ्य महकमे में पसरने वाली भयावह अराजकता का संकेत है. जलाए गए दस्तावेजों में केवल एनआरएचएम घोटाले के ही नहीं बल्कि नियुक्तियों से लेकर खरीद-बिक्री, ठेका, निर्माण कार्य, ट्रांसफर-पोस्टिंग्स समेत तमाम घोटालों और अनियमितताओं के दस्तावेज और रिकॉर्ड्स थे. हाल ही में विभाग की तरफ से ऑनलाइन सर्विस डायरी के लिए नियुक्ति से लेकर कार्यभार आदेश और पद प्रवर्तन संबंधी जानकारियां मांगी गई थीं. उन रिकॉर्ड्स के अलावा वर्ष 1989 में हुई नियुक्तियों के भारी घोटाले के दस्तावेज भी नष्ट दस्तावेजों के मलबे में शामिल हैं. विभाग में कई जगहों पर कर्मचारियों को तैनात तो कर दिया गया था, लेकिन उनकी नियुक्ति का आदेश नहीं था. इसके ब्यौरे भी नष्ट हो गए. अब महकमे को यह पता ही नहीं कि कौन कर्मचारी असली है और कौन नकली. ■


उत्तर प्रदेश की खबरें इंटरनेट पर पढ़ने के लिए www.up.chauthiduniya.com लॉगऑन करें.

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

# महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है यूपी

नलिनी छाबड़ा

महिला और अपराध का हमारे समाज में चोली दामन का साथ होता जा रहा है. अपराध की संख्या में सबसे ज्यादा मामले महिलाओं से ही जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश अपराधों का प्रदेश बनता जा रहा है. पिछले एक दशक में अपराध की बढ़ती संख्याओं के जो आंकड़े सामने आये हैं. उनमें बलात्कार और हत्या के मामले सबसे अधिक हैं. हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति कितनी सुरक्षित है, ये आंकड़े उसकी सच्चाई बयान करते हैं. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकडों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में बच्चियों से बलात्कार के मामलों में 336 फीसदी की वृद्धि हुई है. पिछले एक वर्ष में मासूमों के साथ दुष्कर्म के 2000 मामले दर्ज हुए. जिसमें सबसे अधिक कानपुर में 71 बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ. वर्ष 2001 से 2011 के बीच उत्तर प्रदेश में ऐसी 5,949 घटनायें सामने आयीं. 2005 से 2012 तक कुल 4 लाख 4 हजार एक सौ छियासी अपराधिक घटनायें उत्तर प्रदेश में घटित हुईं, जिसमें 8605 हत्या के मामले और 8008 बलात्कार के मामले सामने आये हैं. ये आंकड़े गवाह हैं कि हर वर्ष 35 फीसदी से अधिक बलात्कार हो रहे हैं.

उत्तर प्रदेश में आये दिन दिल दहला देने वाली घटनायें हो रही हैं और यह सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है. पिछले दिनों बदायूं, सीतापुर, कुशीनगर, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, मैनपुरी में एक के बाद एक दुष्कर्म की जो खबरें आईं, उसने हर किसी को उद्वेलित कर दिया. ये घटनायें अखबारों और हर न्यूज चैनल की हेड लाइन बनती जा रही हैं.

ज्यादा दूर नहीं, पिछले एक साल का ही रिकार्ड उठा कर देख लें, लखनऊ की लॉ की छात्रा गौरी श्रीवास्तव हत्याकांड में लोहिया पथ पर फेंके गये उसके शव के टुकड़े निर्दयता के गवाह हैं. यह क्रूरता चीख-चीखकर समाज की अमानवीयता और अभद्रता की कहानी कह रहे हैं. या फिर मोहनलालगंज की 35 वर्षीय महिला की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गयी, क्योंकि उसने बलात्कार का विरोध किया था या मऊ जिले में 22 मई 2015 की घटना जिसमें पांच साल की एक मासूम बच्ची के साथ अमानवीय अप्राकृतिक व्यवहार करके उसे मार कर उसका शव खेत में फेंक दिया गया. यह क्या बताता है. इन सारी घटनाओं से समाज की जो तस्वीर सामने आयी है, उससे यह साफ हो जाता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक महिला चाहे व बच्ची हो, युवती हो या अधेड़, वह इस समाज में कहीं भी सुरक्षित नहीं है. समाज में महिला हिंसा का रूप और दायरा बढ़ता जा रहा है. इंडियन पैनल

उत्तर प्रदेश में आये दिन दिल दहला देने वाली घटनायें हो रही हैं और यह सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है. पिछले दिनों बदायूं, सीतापुर, कुशीनगर, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, मैनपुरी में एक के बाद एक दुष्कर्म की जो खबरें आईं, उसने हर किसी को उद्वेलित कर दिया. ये घटनायें अखबारों और हर न्यूज चैनल की हेड लाइन बनती जा रही हैं.



कोड में ऐसे जघन्य अपराधों के लिए कठोर दंड व धारायें हैं, लेकिन उसके बाद भी अपराध का दानव अपने वर्चस्व का शिकंजा कसता ही जा रहा है. क्यों हो रहा है ऐसा? सरकारें क्यों नहीं अंकुश लगा पा रही हैं ऐसी मानसिक विकृतियों पर? क्या कारण है कि आज तक हम इसे खत्म करना तो दूर ऐसी वारदातों की संख्या में भी कमी नहीं ला पाये.

शायद कारण हम खुद हैं, रोज सुबह चाय की चुस्कियों के साथ ऐसी खबरों को पढ़ते हैं और एक ठंडी आह भर कर इन किस्सों को पन्नों में दफन कर अपनी नजरें घुमाकर रोजमर्रा की जिन्दगी में व्यस्त हो जाते हैं. भूल जाते हैं कि यह उसी समाज का घिनौना चेहरा है जिसमें हम खुद भी रहते हैं. इन खबरों की यह आग हमारे घरों तक भी पहुंच सकती है. क्या सिर्फ इन किस्सों पर टिप्पणी कर देने से हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? सरकार का अजब रवैया है, हर बात पर पीड़िता को मदद के नाम पर चन्द रुपये की कीमत देकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना. पीड़िता या उसके परिवार को मदद नहीं इन्साफ चाहिये. कैंडिल मार्च करने या धरना प्रदर्शन करने से अगर इन समस्याओं का समाधान सम्भव होता तो अब तक हम बेखौफ जी रहे होते. सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि महिला हिंसा, बलात्कार, हत्या इन सब पर बड़े-बडे भाषणों में महिला सुरक्षा का बिगुल सुनाई देता है, पर असलियत में यह सब खोखला ही साबित होता है. हम देश में कितनी ही प्रगति कर लें, आसमान की ऊचाईयों को छू लें, महिला सुरक्षा के तमाम नियम बना लें, बड़े-बड़े मंचों पर महिलाओं को सम्मानित कर लें, पर उसका दूसरा पहलू यही है कि जबतक समाज की ऐसी घिनौनी मानसिक विकृति पर अंकुश नहीं लगाया जायेगा, तब तक सब व्यर्थ है, दिखावा है. समाज में वहशी दरिन्दे खुलेआम घूम रहे हैं. समाज इनसे आतंकित है. किसी की भी इज्जत से खेलना और फिर उसकी निर्दयता से हत्या कर देना, यह जैसे उनका अधिकार है. किसने दिया है ये हक इन्हें? सवाल बार-बार उठते हैं लेकिन इसका जवाब न शासन के पास है और न समाज के पास. शासन और प्रशासन केवल तमाशबीन होकर रह गया है. समाज को महिलाओं के प्रति अपनी मानसिकता बदलनी होगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

# धार्मिक क्षेत्र की उपेक्षा पर बढ़ रहा रोष

नलिनी छाबड़ा

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान उत्तर प्रदेश की दो महत्वपूर्ण रेलवे लाइन कोयले की कमी के कारण बंद हो गई थी, जिसमें पहली रेलवे लाइन उतरठिया वाया सुल्तानपुर की थी, जिसे आज़ादी के बाद चालू कर दिया गया. वहीं दूसरी तरफ बुढ़वल से महादेवा वाया बहरामघाट तक जाने वाली रेलवे लाइन आज तक चालू नहीं हो सकी. जबकि इस रेल लाइन के शुरू न होने से स्थानीय लोगों के साथ-साथ दूर-दराज से लोधेश्वर महादेव मन्दिर आने वाले शिव भक्तों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता है.

बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में बनारस के काशी विश्वनाथ के बाद सबसे ज्यादा प्रख्यात एवं प्राचीनतम भगवान शिव का मन्दिर जनपद बाराबंकी स्थित रामनगर तहसील के महादेवा में स्थापित लोधेश्वर महादेव का मन्दिर है. कथनानुसार अज्ञातवास के दौरान कुन्ती अपने पांचों पाण्डवों के साथ यहीं पर रहती थीं और शिवलिंग की स्थापना कर पूजा अर्चना करती थीं, जो आज लोधेश्वर महादेव के नाम से प्रचलित है. तब से लेकर आज तक लोधेश्वर महादेव की पूजा अर्चना में लाखों शिवभक्त दूर-दराज से पैदल अपनी यात्रा पूरी करते हैं. जिसमें मध्यप्रदेश के कई जनपदों के अलावा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखण्ड, झांसी, जालौन, उरई, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर आदि जनपदों से लाखों की तादाद में प्रतिवर्ष दो अत्यधिक महत्वपूर्ण अवसरों पर शिवभक्त शिव की पूजा अर्चना के लिए संसाधन विहीन होने के बावजूद पैदल ही चल कर आते हैं. श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार एवं फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष के माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक तथा वर्ष भर के प्रत्येक माह के सोमवार को लाखों श्रद्धालु लोधेश्वर महादेव पहुंचते हैं. इस दौरान यातायात की समुचित व्यवस्था न होने से अक्सर सड़क हादसे होते रहते हैं. रेल की बुढ़वल जक्शन तक व्यवस्था होने से यात्री एवं श्रद्धालु पैदल ही महादेवा तक जाते हैं.

बंद पड़ी बुढ़वल वाया बहरामघाट रेल लाइन के पुनः शुरू कराने की मुहिम को समाजवादी चिंतक पं. राजनाथ शर्मा ने सत्याग्रह के माध्यम से शुरू किया और लोगों में जन जागरण पैदा किया. यही नहीं गत् 13 फरवरी 2015 को इस आन्दोलन को गति देने के उद्देश्य से जनपद बाराबंकी के रेलवे स्टेशन के बाहर एक दिवसीय सांकेतिक धरने के माध्यम से बुढ़वल से महादेवा वाया बहरामघाट रेलवे लाइन को पुनः शुरू कराने का संकल्प लिया गया. इस एक दिवसीय धरने में राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया, नगर पालिका अध्यक्ष रंजीत बहादुर श्रीवास्तव, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष महेन्द्र प्रताप सिंह, भाकियू के प्रान्तीय महासचिव मुकेश सिंह अपने दल-बल के साथ शामिल हुए. वहीं जनपद के विभिन्न स्वयंसेवी एवं अन्य राजनीतिक अराजनीतिक संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रेलमंत्री सुरेश प्रभु, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित रेल विभाग के कई अधिकारियों, राज्य व केन्द्र सरकार के जन प्रतिनिधियों को पत्र भेजकर रेलवे लाइन को पुनः शुरू कराने की मांग भी की गई.

गौरतलब है कि आजादी से पूर्व बुढ़वल से बहरामघाट तक जाने वाली रेल लाइन के माध्यम से गणेशपुर लकड़ी का उत्पादन केन्द्र बन गया था. काफी लम्बे समय तक यह पूरे पूर्वांचल का लकड़ी उत्पादन का प्रमुख केन्द्र रहा है. द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद और बढ़ते घाघरा के स्तर को देखते हुए जो रेल लाइन ईंधन की कमी से बंद कर दी गई थी, उसको न तो किसी ने प्रमुखता से मुद्दा बनाया, न ही तराई क्षेत्र के विकास






को ध्यान में रखकर सदन में बहस का मुद्दा ही बनाया गया. ऐसे में धीरे-धीरे करके घाघरा की तराई का यह क्षेत्र पिछड़ता चला गया और आज स्थिति यह आ गयी कि यह बेहद पिछड़ा क्षेत्र में तब्दील हो गया है. जिस रेलवे लाइन पर कभी रेल दौड़ा करती थी, उस रेलवे लाइन की पटरियां तो अब नहीं हैं, लेकिन रेल के गुजरने वाले पुल एवं रेल की पटरियों का स्थान आज भी वैसे ही है. उस ट्रैक पर अब रेल नहीं, साइकिल और मोटरसाइकिलें दौडती हैं. तब से अब में फर्क बस इतना है कि रेल का आवागमन न होने से पुल जर्जर हो गये हैं. जिन्हे पुनः दुरुस्त कर रेल यातायात का माध्यम बनाया जा सकता है.

इसी कड़ी में 31 मई 2015 को समाजवादी चिंतक राजनाथ शर्मा के नेतृत्व में रामनगर क्षेत्र के सूरतगंज के पूर्व ब्लाक प्रमुख कृष्ण बिहारी अवस्थी, विजय कुमार सिंह मुन्ना, राजेश यादव, जगन शर्मा सहित कई लोगों के साथ रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया गया. बुढ़वल से बहरामघाट तक जाने वाली रेलवे लाइन अगानपुर, बरुआ, लम्बापुर, रजनापुर, महादेवा, गोबरहा, बड़नपुर, गंजापुरवा, टिन्नापुर से होते हुए बहरामघाट वाया चौकाघाट जंक्शन तक पहुंचेगी. करीब एक दर्जन गांवों से जनसम्पर्क करके रेलवे लाइन शुरू कराने की बात रखी गई, जिस पर ग्रामीणों ने एकमत समर्थन जताया और कहा कि रेलवे लाइन शुरू हो जाए, तो आस-पास गांव के लोगों को रोजगार मिल सकेगा तथा यातायात का आसान माध्यम भी उपलब्ध होगा. रेलवे लाइन के न होने से लोगों को यात्रा में काफी असुविधा होती है, क्योंकि इन गांवों से जाने वाली सड़क जो रामनगर तक जाती है, वहां तक पहुंचने के लिये न तो कोई संसाधन है और न ही कोई यात्रा की सुविधा. ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि वह या तो पैदल रामनगर तक जाते हैं या फिर साइकिल एवं अन्य साधनों से रामनगर तक पहुंचते हैं. जिसके बाद वे रामनगर से अन्य गंतव्य स्थानों तक पहुंचने के लिये बस, मैजिक, ट्रक, टैम्पो आदि संसाधनों का प्रयोग करते हैं. बुढ़वल से महादेवा होते हुए बहरामघाट तक जाने वाले रेलवे ट्रैक से तराई क्षेत्र का विकास तो होगा ही और साथ ही गणेशपुर में स्थापित बीटीसी सेन्टर (डायट) में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षित अध्यापक, अध्यापिकाओं को भी सुविधा मिल जाएगी, जो अभी बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर एवं अन्य स्थानों से बसों के माध्यम से गणेशपुर तक पहुंचते हैं. यदि इस रेलवे लाइन का निर्माण होता है, तो जाहिर है कि रेल विभाग को तो आर्थिक लाभ मिलेगा ही साथ ही यात्रा करने वाले यात्रियों की भी यात्रा सुरक्षित एवं सुविधा जनक होगी.

आज के समय में जितने संसाधन बढ़ रहे हैं उनमें आज भी रेल यातायात सबसे सुगम और सुरक्षित मानी जाती है. ऐसे में यदि रेल मंत्रालय इस रेलवे लाइन को पुनः शुरू करता है, तो रेल विभाग को लाभ के साथ-साथ यात्रियों को भी यातायात की सशक्त सुविधा उपलब्ध हो जाएगी. प्रत्येक वर्ष लगने वाले ऐतिहासिक मेले में शामिल होने के लिये दूर दराज से आने वाले शिवभक्तों को भी सुगम और सुरक्षित यातायात की व्यवस्था दिलायी जा सकेगी. सड़क यातायात के माध्यम से महादेवा तक पहुंचने वाले अनगिनत कांवरिये सड़क हादसे का शिकार होने से बच जाएंगे.

## रेल लाइन के लिए समवेत स्वर

रेल लाइन की मुहिम को व्यापक जन आंदोलन की शक्ल देने में मशक्कत कर रहे समाजवादी चिंतक राजनाथ शर्मा ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से बंद पड़ी रेलवे लाइन को शुरू कराने के लिये जो जन आन्दोलन खड़ा हो रहा है, उसकी आज के परिवेश में समाज को बहुत आवश्यकता है. आंदोलन के अगले चरण में बुढ़वल से गनेशपुर तक पैदल यात्रा निकालकर जनचेतना पैदा करेंगे और अंतिम चरण में दिल्ली कूच करने की तैयारी होगी. रामनगर के समाजसेवी कृष्ण बिहारी अवस्थी कहते हैं कि रेलवे लाइन बनने के बाद सबसे पहले घाघरा के तराई क्षेत्र में बसने वाले ग्रामीणों को लाभ होगा तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे. आंदोलन में शरीक राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया ने कहा कि बुढ़वल से बहरामघाट तक रेलवे लाइन शुरू कराने के लिए वे सड़क से संसद तक संघर्ष करते रहेंगे. सपा नेता व प्रदेश सरकार में मंत्री अरविंद सिंह गोप ने कहा कि रामनगर के विकास में बुढ़वल से महादेवा वाया बहरामघाट रेल लाइन अद्वितीय माध्यम साबित होगी. यही नहीं, महादेवा में रेलवे स्टेशन के बनने से लाखों की तादाद में आने वाले शिवभक्तों की यात्रा सुखद हो जाएगी. केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस मुहिम के प्रसंग में कहा है कि बुढ़वल-महादेवा वाया गणेशपुर रेल लाइन का पुनरनिर्माण करने एवं नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में जल्द ही रणनीति तय की जायेगी.

## शक्ल ले रहा व्यापक जन आन्दोलन

लगभग सात दशकों के बाद लोगों में जन चेतना पैदा कर सत्याग्रह के माध्यम से उन्हें एक ऐसी मुहिम से जोड़ा गया जो आज के समय की अनिवार्यता है. यह मुहिम पिछले कई साल से सामाजिक कार्यकर्ता एवं समाजवादी चिंतक राजनाथ शर्मा चला रहे हैं. उनके साथ रामनगर के वयोवृद्ध समाजसेवी एवं पूर्व ब्लाक प्रमुख पं. कृष्ण बिहारी अवस्थी, राज्यसभा सांसद कांग्रेस नेता पीएल पुनिया, ग्राम्य विकास राज्यमंत्री एवं रामनगर के सपा विधायक अरविन्द कुमार सिंह गोप, नगर पालिका अध्यक्ष रंजीत बहादुर श्रीवास्तव, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष महेन्द्र प्रताप सिंह, भाकियू के प्रान्तीय महासचिव मुकेश सिंह, जागो भारत के अध्यक्ष कृष्ण कुमार द्विवेदी, समाजसेवी मृत्युंजय शर्मा, विनय कुमार सिंह, विजय कुमार सिंह, बब्लू खान, देवेन्द्र प्रताप सिंह ज्ञानू, सुशील कुमार मिश्रा, रोहिताश्व दीक्षित, पारख महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेन्द्र रावत, बृजेश दीक्षित एडवोकेट, हुमायूं नईम खां, एडवोकेट कौशल किशोर त्रिपाठी, युवा प्रगति सामाजिक संस्था के अध्यक्ष फराज अहमद खान, अंशू सिंह, समाजसेवी आनन्द नारायन मिश्रा, पत्रकार मंहत बीपी दास, तारिक खान, आसिफ हुसैन, राजेश यादव, अजय प्रताप सिंह, दानिश सिद्दीकी, मौलाना मो. फहीम सहित कई प्रमुख लोग आंदोलन में शामिल हैं.

## ऐसे गुजरेगी रेलवे लाइन

बुढ़वल से बहरामघाट तक जाने वाली रेलवे लाइन अगानपुर, बरुआ, लम्बापुर, रजनापुर, महादेवा, गोबरहा, बड़नपुर, गंजापुरवा, टिन्नापुर से होते हुए बहरामघाट वाया चौकाघाट जक्शन तक पहुंचेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com



# नवजातों की मौत का अस्पताल

शत्रुन्जय सिंह

गोरखपुर जिला महिला अस्पताल में नवजात शिशुओं की मौत लगातार जारी है. केवल दस दिनों में अस्पताल की लापरवाही के कारण दस नवजात शिशुओं की मौत हो चुकी है. नवजात शिशुओं की मौत से न केवल उनके रिश्तेदार बल्कि अन्य लोग भी नाराज हो उठे और स्थिति उग्र हो गई. शिशुओं की देखरेख में लापरवाही का मुद्दा उठता देख ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर, नर्सें और अस्पताल के कर्मचारी भाग खड़े हुए. अस्पताल में हंगामा शुरू हो गया. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर लोगों को समझा-बुझा कर शांत किया. मौके पर पहुंचे विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल के अतिरिक्त कोई भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा. नगर विधायक डॉ. अग्रवाल ने डीएम से मामले की जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की. गोरखपुर के जिलाधिकारी ने भी मामले की जांच का आदेश दे कर औपचारिकता पूरी कर ली.

महिला अस्पताल में भर्ती चौरी चौरा थाना क्षेत्र स्थित सोनबरसा गांव निवासी महेन्द्र की पत्नी राधिका के नवजात शिशु की मौत हो गई. जन्म के बाद बच्चा पूरी तरह स्वस्थ था. दोपहर में उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी. वहां पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था. डॉक्टर की तलाश की भागदौड़ के बीच बच्चे ने दम तोड़ दिया. कुछ मिनट बाद ही पास के बेड पर मौजूद राजघाट क्षेत्र के रायगंज उत्तरी निवासी सुमित की पत्नी प्रतिभा और पिपराइच के उनौला गांव निवासी रोहित की पत्नी किरन के नवजात की भी मौत हो गई.

विडंबना यह है कि जिला महिला अस्पताल में नवजात दम तोड़ रहे हैं और शिशुओं की मौत पर फिक्र करने के बजाय अस्पताल प्रशासन नवजात के घरवालों को ही मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा है. महिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से नवजात की मौत का मामला कोई नया नहीं है. आए दिन अस्पताल में डॉक्टरों की गैरमौजूदगी और लापरवाही से बच्चों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं. अस्पताल में बीते दस दिनों में ही आठ नवजात डॉक्टरों की लापरवाही की भेंट चढ़ गये. बड़ी बात यह है कि अस्पताल प्रशासन डॉक्टरों और कर्मचारियों को क्लीन चिट दे रहा है और बच्चों के घरवालों को ही दोषी ठहरा रहा है.

प्रदेश में भाषणबाजी में मातृ शिशु सुरक्षा को ढेरों योजनाएं चल रही हैं. लेकिन जमीन पर हकीकत इसके ठीक विपरीत है. सरकारी अस्पताल में मुफ्त सुविधा के साथ ही बच्चे के जन्म से लेकर एक साल तक उसकी मॉनीटरिंग का भी प्रावधान है. इसके तहत मौत होने पर कारण भी बताना होता है. लेकिन इन नियमों और प्रावधानों को ताक पर रख कर लापरवाही जारी है. सरकारी अस्पताल में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता है. जब किसी गर्भवती या उसके नवजात के साथ लापरवाही न बरती जाती हो. मामला बढ़ता है, तो जांच का आदेश हो जाता है और नहीं बढ़ा तो समझा बुझाकर लोगों को लौटा दिया जाता है. जांच में हर बार दोषी शिकायत करने वाले को ही ठहराया जाता है. दस दिनों में आठ मासूम की मौत हो चुकी है, लेकिन इनमें से किसी मामले में दोषी की पहचान नहीं हो सकी. बल्कि हर मामले में अस्पताल प्रशासन की ओर से यही कहा जा रहा है कि गलती घर वालों की है. जिला महिला अस्पताल में नवजातों की मौत के बाद कई लोग प्रसूता व नवजात को लेकर निजी अस्पतालों में चले गये. ■




विडंबना यह है कि जिला महिला अस्पताल में नवजात दम तोड़ रहे हैं और शिशुओं की मौत पर फिक्र करने के बजाय अस्पताल प्रशासन नवजात के घरवालों को ही मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा है. महिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से नवजात की मौत का मामला कोई नया नहीं है.

feedback@chauthiduniya.com

*युवा अधिकारी भारतीय थलसेना में शामिल हुए*

# चीन की हरकत चिंता का विषय-धवन

राजकुमार शर्मा

भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में पहुंचे एडमिरल रोबिन धवन ने कहा कि हिंद महासागर में भारतीय नौ सेना मजबूत स्थिति में है. हिंद महासागर में चीन के दखल को लेकर नौसेना प्रमुख ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में चीन या किसी अन्य नौसेना के भारतीय सीमा में दखल का कोई वाकया सामने नहीं आया है. उन्होंने कहा कि चीनी नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. वैसे भारतीय नौसेना किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है. एडमिरल धवन ने कहा कि हमारा मूल उद्देश्य भारतीय समुद्री रेखा को सुरक्षित बनाए रखना है, जिसके लिए रणनीतिक तौर पर हम सक्षम हैं. लंबे समय से चीन का हिंद महासागर में दखल बढ़ा है. दक्षिणी चीन सागर में चीन की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं. चीन ने कुछ हिस्सों में अपने बेड़ों की तैनाती भी कुछ समय पहले बढ़ाई है. भारतीय समुद्री सीमा में सीधे दखल की घटनाएं अभी सामने नहीं आई हैं, चीन ने मई माह में श्वेत पत्र जारी कर अपनी गतिविधियां बढ़ाने का इशारा किया है, जो भारत सहित अन्य देशों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. यह बातें भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आरके धवन ने दीक्षांत परेड की सलामी के अवसर पर कही.

देश की आन, बान व शान के लिए मर-मिटने की शपथ लेकर 616 युवा अफसर भारतीय थलसेना का अभिन्न अंग बन गये. छह महीने के इंतजार के बाद सैन्य अधिकारियों की कमी से जूझ रही सेना को युवा अफसरों की नई टोली मिली है. इनमें सैनिक बहुल प्रदेश उत्तराखंड के 60 युवा सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं. इसके अलावा 14 मित्र देशों अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, भूटान, लिसिथो, पापुआ न्यू गिनी, सिशेल्स, नाइजीरिया, फिजी व तंजानिया आदि के 71 जेंटलमैन कैडेट भी पास आउट होकर अपने-अपने देश की सेना में शामिल हुए हैं. पिछली बार की तरह इस बार असम राइफल्स का कोई भी जेंटलमैन कैडेट पास आउट नहीं हुआ है. कुल मिलाकर परेड में देश-विदेश के 687 जेंटलमैन कैडेटों ने शिरकत की. अब इंडियन मिलिट्री एकेडमी के इतिहास में देश-विदेश की सेना को 57 हजार 854 युवा सैन्य अधिकारी देने का गौरव जुड़ गया है. इनमें मित्र देशों की सेना को मिले 1,813 सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं. कंपनी सार्जेंट मेजर अभिनव बिश्नोई, मुकुल दत्त, सुनंदित महाजन, श्रीजेश एम, जितेन कुमार व हिमांशु तेवतिया ने ड्रिल स्क्वायर पर अपनी-अपनी जगह ली. कैंडेट्स ने शानदार मार्चपास्ट से दर्शक दीर्घा में बैठे हर नागरिक को मंत्रमुग्ध कर दिया. युवा सैन्य अधिकारी अंतिम पग भर रहे थे, तो आसमान से हेलीकाप्टरों के जरिये पुष्प वर्षा हो रही थी. एडमिरल धवन ने जेंटलमेन कैडेट्स से नव सैन्य अधिकारी बनने जा रहे वीरों को विवेक, सेवा और एकता की सीख दी. उन्होंने कैडेट्स को ओवरऑल बेस्ट परफॉरमेंस व अन्य सम्मान से नवाजा. पीपिंग सेरेमनी में युवा सैन्य अफसरों के कंधे पर सितारे देख अभिभावकों की आंखें भर आईं. इस दौरान डिप्टी कमांडेंट मेजर जनरल वाइएस महिवाल, ब्रिगेडियर ट्रेनिंग (आइएमए) ब्रिगेडियर संदीप कुमार सेंगर आदि मौजूद रहे.

श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ-

स्वार्ड ऑफ ऑनर-ईशान सिंघल (बरेली उप्र)

स्वर्ण पदक-अजय कुमार पाठक (अमेठी उप्र)

रजत पदक-आशीष कपूर (कुरुक्षेत्र, हरियाणा)

कांस्य पदक-नवीन जानू (जयपुर राजस्थान)

सिल्वर मेडल (टीजी)-अंशुमान एस बिष्ट (देहरादून, उत्तराखंड)

सर्वश्रेष्ठ विदेशी कैडेट-अली शरीफ (मालदीव)

## युवाओं को वर्दी की चमक लुभा रही है

एक समय ऐसा था, जब युवा मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ ही डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, बैंक को बेहतर पेशा मानते थे. युवाओं को अब सेना की वर्दी सेना को मिलने वाला सम्मान, सुविधा भाने लगी है. युवा बड़ी संख्या में इन नौकरियों को छोड़कर सेना को करियर के रूप में चुन रहे हैं. आईएमए से पासआउट हुए कई युवा सैन्य अफसर ऐसे थे, जो इंजीनियरिंग, मल्टीनेशनल कंपनियों आदि क्षेत्र में चयनित हो चुके थे. उन्होंने सेना को अपने करियर के रूप में चुना. इन युवाओं की मानें तो सेना की नौकरी देशभक्ति से परिपूर्ण, शाही एवं शान वाली है. यहां हर पल, हर दिन चुनौतियों को पार करते हुए नया सीखने को मिलता है. खासकर, उत्तराखंड के युवा तो विशेष तौर पर सेना को अपने करियर के रूप में चुन रहे हैं. लोहाघाट चंपावत निवासी विनीत फर्त्याल आईएमए से पास आउट होकर सेना में अधिकारी बन चुके हैं. सेना में जाने से पहले विनीत ने इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया. वे चाहते तो इंजीनियर बन सकते थे. लेकिन उन्होंने सेना की राह चुनी. इसी प्रकार दिल्ली निवासी अमरिन्दर सिंह भी बीटेक कर चुके हैं. उनके पिता फौज में थे. इसलिए उन्होंने भी अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हुए सेना ज्वाइन की. कोटद्वार निवासी ईशान रावत भी मैकेनिकल से इंजीनियरिंग कर चुके हैं. उन्हें इंजीनियरिंग से ज्यादा सेना की नौकरी पसंद आई. और वे बतौर अधिकारी सेना में शामिल हो चुके हैं. हर्षित चौधरी भी इलेक्ट्रानिक्स से बी-टेक कर चुके हैं. उन्हें भी कई कंपनियों के ऑफर मिले, उन्होंने सेना को ही अपने करियर के रूप में चुना. इसी प्रकार त्यूनी निवासी राहुल शर्मा भी एनआईटी से इंजीनियरिंग कर चुके हैं और उन्होंने भी सेना को चुना. इन युवाओं का मानना है कि सेना उन्हें गर्व से जीना सिखाती है. एक ओर जहां सेना में अच्छी सेलरी, सुविधाएं भी आकर्षक हो चुकी है, वहीं सेना के माध्यम से वे देश व समाज की सेवा भी करते हैं. उनका मानना है कि चुनौती से जूझते हुए सेना में हर पल, हर दिन नया होता है. सेना में रोमांच और चुनौतियां हैं. ■




feedback@chauthiduniya.com

# विलुप्त होने की कगार पर गौरैया

देवभूमि में तेजी से लुप्त हो रही गौरैया पर्यावरण प्रेमियों के माथे पर चिन्ता की लकीरें उहे रही हैं. दुनिया भर में ग्रामीण और शहरी इलाकों में गौरैया की आबादी घटी है. इससे हिमालयी राज्य उत्तराखंड जिसे देवभूमि के नाम से विख्यात यह प्रदेश भी अब अछुता नही है. गौरैया की घटती आबादी के पीछे मानव और विज्ञान का विकास सबसे अधिक जिम्मेदार है. ग्रामीण और शहरी इलाकों में बाग-बगीचे खत्म हो रहे हैं. बढ़ती आबादी के कारण जंगलों का सफाया हो रहा है. ग्रामीण इलाकों में पेड़ काटे जा रहे हैं. इसका सीधा असर इन पर दिख रहा है. गांव-गांव में अब पक्के मकान बनाए जा रहे हैं. ऐसे मकानों में गौरैया को अपना घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिलती है. पहले गांवों में कच्चे मकान बनाए जाते थे. इसमें लकड़ी और दूसरी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता था. कच्चे मकान गौरैया के लिए प्राकृतिक वातावरण और तापमान के लिहाज से अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराते थे. आधुनिक मकानों में यह सुविधा अब उपलब्ध नहीं होती है. यह पक्षी अधिक तापमान में नहीं रह सकता है. शहरों में भी अब आधुनिक सोच के चलते जहां पार्कों पर संकट खड़ा हो गया. वहीं गगनचुम्बी ऊंची इमारतें इस पक्षी की



समस्याओं को और अधिक बढ़ा दिया है. गौरैया मानव बस्तियों के आसपास रहना पसंद करती है. डीएफओ हल्द्वानी सीएस सनवाल ने बताया कि विश्व में सबसे अधिक पाए जाने वाली पक्षियों में से है. लोग जहां भी घर बनाते हैं देर सवेर गौरेया के जोड़े वहां रहने पहुंच जाते हैं. मोबाइल टावरों के निर्माण से टावरों की तरंगों से दिशा ज्ञान और प्रजनन पर विपरीत असर हो रहा है, जिससे गौरेया का जीवन संकट में है. प्रदूषण एंव विकिरण से तापमान बढ़ना भी इसके विलुप्त होने का मुख्य कारण है. वहीं संचार क्रांति इनके लिए अभिशाप बन गई. शहर से लेकर गांवों तक मोबाइल और आकाश छूते टावरों से निकलते रेडिएशन से इनकी जिंदगी संकट में फंस गई है. वहीं, देश में बढ़ते औद्योगिक विकास ने बड़ा सवाल खड़ा किया है. फैक्टरियों से निकले जहरीले धुएं से इनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई है. उद्योगों की स्थापना और पर्यावरण की रक्षा को लेकर संसद से सड़क तक चिंता जाहिर की जाती है, जमीनी स्तर पर यह दिखता नहीं है. कार्बन उगलते वाहनों को प्रदूषण मुक्त का प्रमाणपत्र चस्पा कर दिया जाता है. हकीकत में ऐसा होता नहीं है. वहीं खेती-किसानी में रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता प्रयोग बेजुबान पक्षियों और गौरैया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है. आहार भी जहरीले हो चले हैं. केमिकलयुक्त रसायनों के अधाधुंध प्रयोग से कीड़े मकोड़े भी विलुप्त हो चले हैं, जिससे गौरैयों भोजन का भी संकट खड़ा हो गया है. बबूल और दूसरे पेड़ों पर गौरैयों के बनाए मंकी टोपी जैसे घोंसले लटकते नहीं दिखते हैं. बड़े-बड़े बुनकरों के लिए चुनौती बने मंकी टोपी वाले घोंसले अब पेड़ों पर लटकते नहीं दिखते हैं और नहीं गौरैया की चीं चीं चीं की कर्ण प्रिय आवाज, चूजों को दाना चुगाते सुनाई पड़ती है. गौरैया का संरक्षण हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी है. विज्ञान और विकास हमारे लिए वरदान साबित हुआ है. इसका दूसरा पहलू हमारे लिए कठिन चुनौती भी पेश की है. मानव के करीब रहने वाली पशु-पक्षियों की कई प्रजाति विलुप्त हो गई हैं या होने के कगार पर हैं. गौरैया एक घरेलू और पालतू पक्षी है. यह इंसान और इसकी बस्ती के पास अधिक रहना पसंद करती है. पूर्वी एशिया में यह बहुतायत पाई जाती है. यह अधिक वजनी नहीं होती. इसका जीवन काल दो साल का होता है. यह पांच से छह अंडे देती है. आंध्र यूनिवर्सिटी के एक शोध में गौरैया की आबादी में 60 फीसदी से अधिक की कमी बताई गई है.ब्रिटेन की रायल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्डस ने इस चुलबुली और चंचल पक्षी को रेड लिस्ट में डाल दिया है.

## विदेशों में भी घट रही है गौरैया

गुरुकुल कांगड़ी विवि की पक्षी विविधता एवं पक्षी संवाद प्रयोगशाला के पक्षी वैज्ञानिक प्रो. दिनेश भट्ट एवं डॉ. विनय कुमार सेठी ने बताया हमारे देश की कई संस्थाएं शोध कर रही हैं. बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी मुंबई, सलीम अली सेंटर फॉर ऑरनिथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री कोयम्बटूर और भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून आदि की ओर से पक्षी जीवन से जुड़ी घटनाओं और इनकी गणना आदि पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन किया जा रहा है. इन सबके बावजूद गौरैया के घटने का पता देर से चल पाया. डॉ. सेठी के मुताबिक हमारे देश में गौरैया की संख्या को लेकर ठोस आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि बड़े, रंगीन और प्रवासी पक्षियों पर लोगों का अधिक ध्यान रहा. पक्षी वैज्ञानिक डॉ. विनय कुमार सेठी ने बताया कि ब्रिटेन में गौरैया की संख्या बढ़ने के बजाय घटकर आधी रह गई है. लंदन शहर में तो गौरैया की संख्या में 80 फीसदी तक गिरावट आई है. ■ *-राजकुमार शर्मा*

## अब विकलांगों को लखनऊ में ही मिल सकेंगे जयपुर-फुट

# विश्वविद्यालय के मंच से सियासत

दीनबंधु कबीर

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बसपा नेता सतीश मिश्रा को समाजवादी परिवार में आने का खुला न्यौता दिया है. अखिलेश ने खुले मंच से यह सियासी आमंत्रण देकर चुनाव की तैयारियों में लगी बसपा प्रमुख मायावती को बौखलाने का मौका दिया है. पत्रकार हत्याकांड में यूपी सरकार की ढिलाई को लेकर मायावती ने अखिलेश पर तीखा प्रहार किया था. उसके बाद अखिलेश ने राजनीति की बिसात पर संदेह का कार्ड फेंक दिया. बसपा नेता सतीश मिश्रा की मां शकुंतला मिश्रा के नाम पर बने राष्ट्रीय विकलांग पुनर्वास विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने मंच से सतीश मिश्रा को बुलावा भेजा. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि जिनकी मां के नाम पर युनिवर्सिटी बनी है. अगर वो आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी. हम तो बुलाने की हिम्मत करते हैं, मगर वो आने की हिम्मत नहीं करते. यह दुर्भाग्य की बात है. मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि विश्वविद्यालय किसी भी सरकार के समय में बना हो, किसी ने भी बनवाया हो, मगर हम समाजवादी पार्टी के लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करते.

बसपा नेता और मायावती के खास सतीश मिश्रा के लिए सपा सरकार की मेहरबानियां लगातार बनी रही हैं. सतीश की मां के नाम पर विश्वविद्यालय तो बसपा सरकार के कार्यकाल में बना, लेकिन उसका विकास समाजवादी पार्टी की सरकार के दरम्यान हुआ. मायावती ने सतीश मिश्रा की बहन आभा अग्निहोत्री को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष और डॉ. दिव्या मिश्रा को राज्य समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था. सतीश मिश्रा के प्रति अखिलेश का प्रेम इतना है कि उन्होंने दिव्या मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया था. हालांकि सतीश मिश्रा की वही बहन भाजपा में शामिल हो गई थीं. सतीश मिश्रा की मां के नाम पर बने विश्वविद्यालय पर अखिलेश यादव की कृपा लगातार बनी हुई है. यूनिवर्सिटी के विकास कार्य के लिए 60 करोड़ रुपये और विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना के लिए 27 करोड़ रुपये की बजटीय-व्यवस्था इसी प्रेम और कृपा का उदाहरण है. इसी विश्वविद्यालय ने मुलायम सिंह यादव को डॉक्ट्रेट की उपाधि भी दी थी.

बहरहाल, शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र की शुरुआत को उत्तर प्रदेश में विकलागों के लिए एक सार्थक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है. जिस जयपुर लिम्ब के लिए लोगों को राजस्थान के चक्कर लगाने पड़ते थे, वह अब प्रदेश में ही उपलब्ध हो सकेगा, इसकी कवायद हो रही है. इसके लिए विश्वविद्यालय और जयपुर फुट के बीच करार भी हुआ. इसी मौक पर मुख्यमंत्री ने सतीश मिश्रा को समाजवादी पार्टी में आने का न्यौता दे डाला.

शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय विकलांग पुनर्वास विश्वविद्यालय और जयपुर फुट के बीच हुए करार के बाद यह उम्मीद बढ़ी है कि अब उत्तर प्रदेश के विकलांगों को राजधानी में ही एडवांस तकनीक से युक्त कृत्रिम अंग मिल सकेंगे. जरूरतमंदों को विश्वस्तरीय कृत्रिम अंग मुहैया कराने के लिए विश्वविद्यालय में

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र का लोकार्पण किया. कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (जयपुर फुट) के बीच करारनामे पर भी हस्ताक्षर हुआ. इसके तहत जयपुर फुट इस केंद्र के लिए अपनी तकनीक मुहैया कराएगा. साथ ही हर साल 15 लाख के कृत्रिम अंग बनाने के लिए निर्माण सामग्री देगा. केंद्र को संवारने के लिए जयपुर से विशेषज्ञ भी भेजे जाएंगे, जो यहां के विशेषज्ञों को तकनीकी सहयोग देंगे. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में बीएमवीएसएस के मुख्य संरक्षक डीआर मेहता और विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. निशीथ राय के बीच करारनामे पर हस्ताक्षर का आदान-प्रदान हुआ. मुख्यमंत्री ने कहा भी कि इस केंद्र के बनने से प्रदेश के विकलांग जनों को कृत्रिम अंग के लिए जयपुर जाना नहीं पड़ेगा. बीएमवीएसएस की तरफ से दिए जा रहे सहयोग से हम प्रदेश के दूसरे जिलों में स्पेशल कैंप लगवाकर उन्हें कृत्रिम अंग मुहैया कराएंगे. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 22 विकलांगों को कृत्रिम अंग भी वितरित किए. उन्होंने दृष्टि सामाजिक संस्थान की छह साल की बालिका को कृत्रिम अंग भी लगाए. बलिया से आए मिथिलेश कुमार को 10 लाख 50 हजार रुपये की सहायता राशि का चेक भी प्रदान किया. मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल का शुभारम्भ भी किया. इस सुविधा से विकलांग जन पहले से पंजीकरण कराकर तयशुदा तारीख पर कृत्रिम अंग प्राप्त कर सकेंगे.

### पैर नहीं, उन्हें तो आधार मिल गया

कानपुर की रहने वाली सुनीता दीक्षित एक दुर्घटना में अपना दायां पैर गंवा बैठी थी. प्राइमरी स्कूल में टीचर सुनीता खुद को असहाय महसूस कर रही थीं. जब उन्हें कृत्रिम अंग मुहैया कराया गया तो उनकी आंखों से आंसू छलक आए. जमीन पर पैर टिकाते हुए सुनीता ने कहा, आज लग रहा है कि जैसे नई जिंदगी मिल गई हो. सुनीता की तरह ही तमाम लोगों ने अपना दर्द बयां किया, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी झलक रही थी. हरौनी से आए मनोज रेल दुर्घटना में अपने दोनों पैर गंवा बैठे थे. जमीन गिरवी रखकर घरवालों ने किसी तरह इलाज तो करा दिया, लेकिन उनके लिए कृत्रिम अंग दिलाना मुश्किल हो रहा था. जब उन्हें मुफ्त कृत्रिम अंग मिला, तो उनका चेहरा खिल उठा. अमेठी से आए गया प्रसाद ने बताया कि सड़क दुर्घटना में उनका पैर चला गया था. उसके बाद से हिम्मत टूट गई थी. जब कृत्रिम अंग दिया गया तो जमीन पर पैर रखते ही लगा जैसे मुझमें जान बाकी है.

### मेहता ने चलना सिखाया

रिटायर्ड आईएएस अफसर डीआर मेहता की लगन से बने जयपुर फुट ने दुनिया भर में खास मुकाम हासिल किया है. 1969 में डीआर मेहता जैसलमेर के कलेक्टर थे. एक दुर्घटना में उनका पैर खराब हो गया था. जिन डॉक्टरों को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि पैर कटवाना पड़ेगा. कुछ डॉक्टरों ने कहा कि एक बार इलाज करके देखते हैं. संयोग से इलाज सफल हो गया. पद्मभूषण मेहता ने बताया कि बेड रेस्ट के दौरान मेरे मन में विचार आया कि मेरे इलाज के लिए तो सरकार खर्चा दे देगी. लेकिन उन गरीब लोगों का क्या होता होगा, जो खर्चा नहीं उठा सकते. बस यहीं से उन्होंने नि:शक्तजनों के लिए कुछ करने की ठान ली. सन 1975 में जयपुर फुट की स्थापना हुई. पहले साल 59 लोगों को कृत्रिम अंग दिए गए. साल दर साल सफर बढ़ता गया और अब वह दुनियाभर में प्रतिमान स्थापित कर चुका है.

### उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विकलांग

उत्तर प्रदेश में विकलांगों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है. पूरे देश में विकलांगों की संख्या दो करोड़ 68 लाख 10 हजार 557 है. अकेले उत्तर प्रदेश में विकलांगों की संख्या 41 लाख 57 हजार 514 है. विकलांगों के मामले में यूपी के बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है. महाराष्ट्र में विकलांगों की संख्या 29 लाख 63 हजार 392 है. महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर बिहार है. बिहार में 23 लाख 31 हजार 9 है. देश के एक करोड़ 86 लाख 31 हजार 921 विकलांग गांवों में रहते हैं.

भारत सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक देश में एक करोड़ 49 लाख 86 हजार 202 पुरुष और एक करोड़ 18 लाख 24 हजार 335 महिलाएं विकलांग हैं. चलने से लाचार लोगों की संख्या 54 लाख 36 हजार 604 है. देश में 50 लाख 32 हजार 463 लोगों की आंखों के आगे अंधेरा छाया है. ऐसे दृष्टिहीन लोगों में 2638516 पुरुष और 2393947 महिलाएं हैं. 50 लाख 71 हजार 7 लोगों को सुनाई नहीं देता है. इसमें पुरुषों की संख्या 2677544 और महिलाओं की संख्या 2393463 है. देश में 19 लाख 98 हजार 535 लोग बोल नहीं पाते हैं. मानसिक विकलांगता के शिकार लोगों की संख्या 21 लाख 28 हजार 534 है. मल्टीपल डिसेबिलिटी के शिकार लोगों की संख्या देश में 21 लाख 16 हजार 487 है. विकलांगता की भयावह तस्वीर दिखाने वाले ये आंकड़े बताते हैं कि सबसे अधिक विकलांगों की संख्या 10 से 19 साल के बीच की उम्र के लोगों की है.

यूपी, महाराष्ट्र, बिहार के बाद विकलांगों की संख्या आंध्रप्रदेश में ज्यादा है. आंध्रप्रदेश में 22 लाख 66 हजार 607, पश्चिम बंगाल में 2017406, राजस्थान 1563694, मध्यप्रदेश में 1551931, कनार्टक में 1324205, उड़ीसा में 1244402, तमिलनाडु में 1179963, गुजरात में 1092302, झारखंड में 769980, केरल में 761843, पंजाब में 653063, हरियाणा में 546374, असम में 480065, दिल्ली में 234882, उत्तराखंड में 185272, जम्मू-कश्मीर में 361153, हिमाचल प्रदेश में 155316, त्रिपुरा में 64346, मणिपुर में 54110, मेघालय में 44317, गोवा में 33012, नागालैंड में 29631, अरुणाचल प्रदेश में 26734, सिक्किम में 18187, अंडमान में 6660, दादर एवं नागर हवेली में 3294, दमन में 2196 व लक्षदीप में सबसे कम 1615 विकलांग हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

# सपा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह का पार्टी के खिलाफ बगावत

शत्रुन्जय सिंह रैकवार

छात्र आन्दोलन की उपज व खांटी समाजवादी नेता देवेंद्र सिंह के भाजपा में जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं. देवेंद्र प्रताप सिंह विधान परिषद सदस्य हैं और पिछले कुछ अर्से से सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंके हुए हैं. उन्होंने अखिलेश यादव के चहेते गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार यादव की अराजकता के खिलाफ जन-मोर्चा खोल रखा था. सपा के विधान परिषद के सदस्य द्वारा बार-बार शिकायत किए जाने के बावजूद सरकार ने एसएसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तब विवश होकर देवेंद्र प्रताप सिंह को सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ा था.

सपा से बगावत करने वाले देवेंद्र सिंह को भाजपा में लाने की उच्चस्तरीय कोशिशें चल रही हैं. हाल में देवेंद्र सिंह द्वारा दिए गए बयान भी कुछ ऐसे ही संकेत और संदेश दे रहे हैं. गोरखपुर-फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य चुने गए सपाई देवेंद्र प्रताप सिंह ने बीते कुछ माह से सपा सरकार व प्रशासन पर हल्ला बोल कार्यक्रम चला रखा है. एक तरफ सपा के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ रखी है, तो दूसरी तरफ गगहां थाना क्षेत्र के अन्तर्गत बासूडीहा कांड को लेकर बांसगांव से भाजपा सांसद कमलेश पासवान के द्वारा किए गए सड़क जाम और आन्दोलन में शरीक होकर भी उन्होंने कुछ संकेत दिए हैं. कई भाजपा नेताओं का कहना है कि देवेंद्र सिंह लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भाजपा के बड़े नेताओं के सम्पर्क में हैं और बीते महीने दिल्ली का दौरा भी कर चुके हैं. दिल्ली जाने और वहां लंबे समय तक रुकने की राजनीतिक वजहें चर्चा में हैं. सीएम से उनका जो मतभेद चल रहा है. उसे रफा-दफा करने में दोनों पक्षों की अरुचि भी अटकलों को बल दे रही है. ग्रामीणों पर ढाए गए एसएसपी के जुल्म के खिलाफ देवेंद्र प्रताप सिंह ने गत 20 अप्रैल को भाजपा सांसद कमलेश पासवान के साथ धरना दिया था. इस साझा धरना ने देवेंद्र सिंह के भाजपा में जाने की चर्चा को और भड़काया. पूरे पूर्वांचल में देवेंद्र प्रताप सिंह की छवि न्यायप्रिय राजनीतिक की है. गोरखपुर पुलिस प्रशासन की अराजकता के खिलाफ शिकायत करने पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने नेता का साथ देने के बजाय एसएसपी प्रदीप कुमार यादव का साथ देना अधिक बेहतर समझा. इसका विरोध करने पर अकिलेश यादव ने देवेंद्र प्रताप सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया. नोटिस में भाजपा सांसद कमलेश पासवान के साथ एसएसपी गोरखपुर के खिलाफ धरना देने का भी कारण पूछा गया था. देवेंद्र सिंह ने नोटिस का करारा जवाब दिया. सीएम को भेजे जवाब में उन्होंने सीएम से पूछा है कि क्या सपा सुप्रीमो और लोहिया के आदर्शों व सिद्धांतों का अनुपालन पार्टी-विरोधी या सरकार-विरोधी कदम है? उन्होंने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के साथ-साथ अपने जवाब की कॉपी पार्टी

### सीएम की नोटिस और एमएलसी का जवाब

समाजवादी पार्टी के कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यदि डॉ. राम मनोहर लोहिया और आदरणीय मुलायम सिंह यादव के संघर्ष के रास्ते पर चलना सरकार विरोधी है, तो बिना समय गंवाए मेरे खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने देवेंद्र प्रताप सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा था कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाए. एमएलसी ने नोटिस का विस्तार से जवाब देते हुए लिखा कि क्या कोई पुलिस वाला आपकी मां का आंचल फाड़े तो क्या आपको इसलिए चुप रहना चाहिए कि सूबे में उसकी अपनी सरकार है? अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष की कोख से ही समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ है. वे डॉ. लोहिया और मुलायम के संघर्ष के रास्ते पर चल रहे हैं, अगर यह गलत है, तो मुख्यमंत्री उनपर तत्काल कार्रवाई करें, अन्यथा बासुडीहा और सीसायल में सरेआम गुंडई मचाने वाले गोरखपुर के एसएसपी प्रदीप कुमार यादव और उसके थानेदारों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए. श्री सिंह के तेवर को देखते हुए उनका सपा से निष्कासन और भाजपा में आगमन तय ही माना जा रहा है. इसीलिए समाजवादी पार्टी नेतृत्व देवेंद्र प्रताप सिंह पर सीधी कार्रवाई से हिचक रही है. पार्टी नेतृत्व उन्हें पार्टी से तो निकाल सकती है, लेकिन वे एमएलसी पूर्ववत बने रहेंगे. ऐसे में पार्टी की और किरकिरी होगी.

सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और पार्टी महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव को भी भेज दी है. इस जवाब के बाद ही सपा के जिलाध्यक्ष मोहसिन खान सार्वजनिक तौर पर यह कहने लगे कि देवेंद्र सिंह कभी समाजवादी पार्टी के सदस्य ही नही रहे हैं. ऐसी बयानबाजी पर देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि वे सपा के आजीवन सदस्य हैं और आजीवन सदस्य को हर साल बार-बार सदस्य नहीं बनना पड़ता है. मोहसिन पर उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया. उन्होंने कहा कि सीएम से भी उनकी कोई नाराजगी नहीं है लेकिन पुलिस अराजकता और एसएसपी की गुंडई के खिलाफ लोगों में तीव्र आक्रोश है. उनकी लड़ाई सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि विगत 16 अप्रैल को एसएसपी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर लूटपाट हुई, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, अबोध बच्चों व बड़ों को भी पीटा गया, लड़कियों की शादी के लिये रखे जेवरात आदि भी लूट लिये गये. इन ज्यादतियों ने अंग्रेजी हुकूमत को भी मात दे दिया. एसएसपी को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए. देवेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि जुल्म और ज्यादती के खिलाफ है, पुलिसिया अराजकता के खिलाफ है, सीएम के खिलाफ नहीं है.

मुख्यमंत्री को संबोधित खुले पत्र में एमएलसी ने लिखा है कि अगर मुख्यमंत्री मेरी सच्ची खरी बातों से नाराज हैं, तो उसकी सजा गोरखपुर की निर्दोष जनता को पुलिस से कहर बरपा कर न दें. उन्होंने गोरखपुर के एसएसपी सहित चार थानाध्यक्षों पर दो गांवों में घुसकर लोगों को बेरहमी से पीटने, नकदी व सामान लूटने और घरों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया. यह भी लिखा कि शिकायत के बावजूद उच्चाधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया. यहां तक कि मुख्यमंत्री ने भी कई बार फोन करने के बाद बात नहीं की. देवेंद्र सिंह ने संवाददाताओं को वह वीडियो भी दिखाया, जो एसएसपी की ज्यादती का स्पष्ट प्रमाण है. पुलिस ने सपा के जिला पंचायत सदस्य शैलेन्द्र प्रताप सिंह को नंगा कर बर्बरतापूर्वक पीटा. बुजुर्गों और महिलाओं तक को नहीं बख्शा. मुख्य सचिव समेत शासन के सभी वरिष्ठ पुलिस अफसरों को देवेंद्र सिंह ने खुद जानकारी दी मगर किसी ने दोषी पुलिस अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी नेतृत्व को यह सोचना चाहिए कि चापलूसों से घिरकर पार्टी का कभी भला नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तक सच पहुंच सके इसलिये वे मीडिया के सामने यह बातें कहने को मजबूर हैं. देवेंद्र सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल खराब है. उन्होंने गोरखपुर के एसएसपी समेत बांसगांव, गगहा, गोला और बेलीपार के थानाध्यक्षों को भी निलंबित करने और उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की. देवेंद्र सिंह ने इस संबंध में प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी से भी मुलाकात की और उन्हें घटना का वीडियो क्लिप उपलब्ध कराकर कार्रवाई की मांग की. इसके पहले उन्होंने गोरखपुर के आईजी को भी वीडियो फुटेज उपलब्ध कराया था. सपा के जिलाध्यक्ष मोहसिन खान कहते हैं कि देवेंद्र प्रताप सिंह सपा के सदस्य नहीं हैं, यद्यपि वे सपा के एमएलसी जरूर हैं. हर तीन वर्ष पर सदस्यता का नवीनीकरण होता है जो उन्होंने नहीं कराया. नवीनीकरण नहीं कराने पर उन्हें नोटिस क्यों नहीं दी गई, तो इसके जवाब में मोहसिन कुछ नहीं कहते. ■

feedback@chauthiduniya.com